राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 193

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 21 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जयशंकर बोले, भारतीय प्रतिभा की राह में रोड़ा न बने अमेरिका

>> 3

सरोकार

पेड़ों का मोल समझा तो कमल किशोर बांटने लगे छांव

चक्रधरपुर : तीस साल में 30 हजार से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं झारखंड के

चक्रधरपुर के कमल किशोर दास को लोग ट्री मैन के नाम से पुकारते हैं। 63 वर्ष की उम्र में भी पौधे लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अपने लगाए पौधों की वह बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

त्रेता की 'संजीवनी' को मिला नया जीवन

अमृतसर : लेह-लद्दाख में सैनिकों और स्थानीय लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने

वाले सोलो नामक पौधे को गुरु नानक देव विवि ने नया जीवन दिया है। यहां लैब में पौधे का टिश्यू प्लांट तैयार किया है। धारणा है कि यही वह संजीवनी बूटी है जिसका जिक्र रामायण में है। (पेज-10)

विश्वास. News

लखनऊ की पुरानी तस्वीर, बार-बार की जा रही है वायरल ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

एक्जिट पोल : झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा के आसार

रांची : झारखंड में 81 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को मतदान का आखिरी चरण संपन्न हो गया। निजी टीवी न्यूज चैनलों के एक्जिट पोल के सर्वे के अनुसार, यहां त्रिशंकु विधानसभा के प्रबल आसार हैं। भाजपानीत गठबंधन सरकार को झटका लग सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार बन सकती है। इंडिया टुडे और एक्सिस माइ इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा को 22 से 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं झामुमो, कांग्रेस व राजद गठबंधन को 38 से 50 सीटें तक मिल सकती हैं। जेवीएम को 2-4, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) को 3-5 सीटें मिल सकती हैं। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। (पेज-4)

उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू, हिंसा में 11 की मौत

अराजकता ▶ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग कई जिलों में भड़की, पुलिस को बनाया जा रहा निशाना

- उपद्रवियों ने बरसाए पत्थर, पुलिस चौकी व 50 से अधिक वाहन फूंके
- हिंसक झड़पों में पुलिसकर्मियों समेत सैकड़ों लोग घायल
- डीजीपी ने कहा, एक भी भी मौत पुलिस फायरिंग में नहीं हुई

विरोध-प्रदर्शन की आग में जल उठा शहर ... उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो उठी। इस दौरान वाहनों को फूंकने के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव करते उपद्रवी। भूषण भास्कर

मेरठ में तीन, बिजनौर और फीरोजाबाद में दो-दो, संभल वाराणसी, कानपुर में एक-एक की मौत

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध की आग शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भड़क गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई मौकों पर बेकाबू भीड़ के आगे उसे कदम पीछे भी हटाने पड़े। इस दौरान हिंसा में 11 की मौत हो गई। उप्र के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि मेरठ में तीन, बिजनौर और फीरोजाबाद में दो-दो की मौत हुई है, जबकि मेरठ, वाराणसी, कानपुर और संभल में एक-एक की जान गई है। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि एक भी मौत पुलिस फायरिंग में नहीं हुई है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के सारे दावे उस समय बेदम साबित हुए जब जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। कानपुर नगर, फीरोजाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, सहारनपुर, अमरोहा, बहराइच, बरेली, मुजफ्फरनगर समेत करीब 15 जिले सुलग उठे। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर 50 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। बिजनौर में एक सिपाही के पेट में गोली लगी, जबकि मेरठ में दो सिपाही गोली लगने से घायल हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को भी सभी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। देश के अन्य हिस्से भी विरोध प्रदर्शन और हिंसा से अछूते नहीं रहे। मध्य प्रदेश में उग्र प्रदर्शन के चलते राज्य सरकार ने बैतूल-होशंगाबाद को छोड़ पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। जोधपुर में उपद्रवियों ने कई जगह दुकानें लूट लीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी छिटपुट हिंसा हुई। प्रदर्शन की आशंका के चलते कोलकाता के भी कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया।

सिर्फ लखनऊ में दिखा पुलिस की सख्ती का असर

पुलिस की सख्ती का असर सूबे की राजधानी लखनऊ में तो रहा, कई अन्य जिले उबल पड़े। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव व वाहनों में आगजनी की घटनाएं शुरू हो गईं। मेरठ में जुमे की नमाज के बाद कोतवाली थाने पर उपद्रवियों ने सीओ और सिपाही पर पथराव कर दिया और इस्लामाबाद चौकी में आग लगा दी। छह पुलिसकर्मी भी पथराव व फायरिंग में घायल हुए हैं। यहां हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में उन्मादी भीड़ ने पथराव, पेट्रोल की बोतलें फेंकी। देना बैंक की शाखा को फूंक दिया। पुलिस, पीएसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी।

667 आरोपित हिरासत में

उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 667 आरोपितों को हिरासत में लिया गया है। कुल 38 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बाधित करा दिया है। सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर सुलतानपुर, गोंडा और बलरामपुर में भी उपद्रव की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस सतर्क रही। आइजी (कानून-व्यवस्था) प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गुरुवार को सपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों की ओर से सीएए के विरोध में विभिन्न जिलों में किए गए धरना-प्रदर्शन के मामलों कुल 17 मुकदमे दर्ज कर 144 को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में 10, वाराणसी में तीन, पीलीभीत में एक, संभल में दो कुशीनगर में एक एफआइआर दर्ज की गई है। सभी जिलों से पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है। वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों को चिह्नित कराया जा रहा है।

जागरण विचार

जिस नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से लेना-देना नहीं उसके विरोध के बहाने देश के कई हिस्सों में जैसी नग्न अराजकता का परिचय दिया जा रहा वह न सिर्फ दुखद है, बल्कि भयावह भी। इस खुली अराजकता को चंद शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से नहीं ढका जा सकता। दुनिया देख रही है कि प्रदर्शन की आड़ में क्या हो रहा है? शर्मनाक यह है कि अराजकता को हवा देने वालों में विपक्षी नेताओं के साथ गैर सियासी शख्सियत भी शामिल हैं। ये सब नित-नए कुतर्क गढ़ने के साथ यह दुष्प्रचार भी कर रहे है कि हिंसा के पीछे तो पुलिस व सरकार है। जनता को समझना ही होगा कि जो अनर्थ हो रहा है वह अपनी बात कहने के बहाने उन्माद दिखाने के अलावा और कुछ नहीं।

दिल्ली-एनसीआर में उग्र प्रदर्शन

जेएनएन, नई दिल्ली

- दरियागंज में उपद्रवियों ने पथराव के साथ फूंकी कार, बंद रहे 19 मेट्रो स्टेशन
- गाजियाबाद, हापुड़ में भीड़ और पुलिस में हिंसक झड़क, 150 हिरासत में लिए गए

दिल्ली-एनसीआर में भी सीएए को लेकर जुमे (शुक्रवार) की नमाज के बाद से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन शाम होते-होते उग्र हो गया। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। घंटों प्रदर्शन के बाद लौटते समय उपद्रवियों ने शाम करीब छह बजे पुलिस पर पथराव कर दिया। उन्होंने दरियागंज थाने के सामने खड़ी एक कार में आग लगा दी और कुछ मोटरसाइकिलों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शन को देखते हुए एहतियातन शुक्रवार को भी छह मेट्रो कॉरिडोर के 19 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। हालांकि शाम तक सात बजे तक जामा मस्जिद, जाफराबाद व मौजपूर-बाबरपुर स्टेशनों को छोड़कर अन्य सभी मेट्रो स्टेशनों को खोल दिया गया। इस बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग क्षेत्र में भी शुक्रवार को आठवें दिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहा। गाजियाबाद में भीड़ हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है।

जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक मार्च : लाल किले पर घंटों प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर तक मार्च करने की बात करने लगे। भीड़ को दिल्ली गेट पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया था। शाम को दरियागंज की मस्जिद से प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की गई। इस दौरान स्थानीय लोग मानवश्रंखला बनाकर प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने लगे। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार छोड़ी और लाठी चार्ज भी किया, जिसमें तमाम लोग घायल हो गए। पुलिस ने पथराव और आगजनी की घटना के लिए दस से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपित यमुनापार के रहने वाले हैं। उधर, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर, साहिबाबाद एवं हापुड़ में भी उपद्रवियों के साथ पुलिस की झड़पें हुईं। कई जगह पथराव व फायरिंग की गई। इसमें सीओ व इंस्पेक्टर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। 60 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मोदीनगर में पथराव में थानाध्यक्ष समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। भीड़ की तरफ से असलहे से फायरिंग भी की गई।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली गेट पर उपद्रवियों द्वारा जलाई गई कार को बुझाने की कोशिश करते पुलिसकर्मी। संजय

शुक्रवार को नमाज के बाद सुनियोजित ढंग से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और पुलिस पर हमला बोला। उपद्रवियों ने कम उम्र के बच्चों को आगे किया, जिनकी सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस ने संयम बरतते हुए त्वरित कार्रवाई की। **-ओपी सिंह, पुलिस महानिदेशक, उप्र**

नीतीश कुमार बोले, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) लागू नहीं होगा। नीतीश की इस प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि जनता दल यूनाइडेट (जदयू) एनआरसी को समर्थन नहीं देने के अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। हालांकि सीएए पर जदयू ने संसद के दोनों सदनों में सरकार को अपना समर्थन दिया था (विस्तृत पेज-5 पर)

ताउम्र जेल में रहेगा कुलदीप सेंगर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव कांड

- 25 लाख जुर्माना भी लगाया, पीड़िता की मां को बतौर मुआवजा मिलेंगे 10 लाख रुपये
- सजा सुनकर कुलदीप सेंगर के साथ परिजन भी अदालत में रो पड़े

नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी कुलदीप सेंगर। फाइल फोटो (प्रेट्र)

सेंगर की गई विधायकी

नई दिल्ली : सजा सुनाए जाते ही कुलदीप की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक, किसी भी केस में दो वर्ष से ज्यादा की सजा होने पर व्यक्ति सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाता है। सजा भुगतने के छह साल बाद ही चुनाव लड़ सकता है, पर उम्रकैद के कारण सेंगर का सियासी भविष्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया है।

कुलदीप सेंगर ने एक लोकसेवक होने के नाते अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाते हुए दुष्कर्म किया। सेंगर जनता का सेवक था, लेकिन उसने लोगों के साथ विश्वासघात किया। **-न्यायाधीश, धर्मेश शर्मा (सजा सुनाते हुए की टिप्पणी)**

अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे भाइयों की और बहनों को भी जरूरत है। **-सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने अपने वकील से कहा**

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को तीस हजारी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है, जो एक माह के भीतर अदा करना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य कोष से भुगतान करना होगा। कोर्ट ने पीड़िता की मां को मुआवजे के तौर पर अतिरिक्त 10 लाख रुपये देने को कहा है। न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सजा सुनाते हुए कहा, कुलदीप सेंगर को अपना शेष जीवन प्राकृतिक मौत तक जेल में बिताना होगा। सजा सुनते ही सेंगर के साथ उसके परिजन भी रो पड़े। सेंगर के वकील ने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।

कुलदीप सेंगर को सजा सुनाने के लिए शुक्रवार दोपहर 12 बजे से सवा एक बजे तक बहस चली। इसके बाद दो बजे फैसला सुनाने का समय तय किया गया। ठीक दो बजे न्यायाधीश धर्मेश शर्मा अदालत में आए और उन्होंने सेंगर को पेश करने के साथ ही कहा कि 10 मिनट में फैसला सुनाया जाएगा। 10 मिनट के बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि कुलदीप सेंगर ने एक लोकसेवक होने के नाते अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाते हुए दुष्कर्म किया। सेंगर जनता का सेवक था, लेकिन उसने लोगों के साथ विश्वासघात किया। अदालत ने कहा, पीड़ित परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान में एक साल तक रहेगा और उत्तर प्रदेश सरकार किराये के लिए प्रतिमाह 15 हजार रुपये का भुगतान करे।

हर तीन माह में पीड़िता की सुरक्षा का आकलन करे सीबीआइ पेज>>7

31 जनवरी को ईयू से ब्रिटेन का अलगाव तय

लंदन, प्रेट्र : नवगठित ब्रिटिश संसद ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की महात्वाकांक्षी ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) योजना पर मुहर लगा दी। अलगाव की बाबत यूरोपीय यूनियन (ईयू) से ब्रिटेन के समझौते को हाउस ऑफ कॉमंस ने 124 मतों के बड़े अंतर से स्वीकार कर लिया। सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में 358 जबकि विरोध में 234 मत पड़े। इसके साथ ही 31 जनवरी, 2020 को ईयू से ब्रिटेन के अलगाव का रास्ता साफ हो गया। ज्ञात हो, पूर्ववर्ती कंजरवेटिव सरकार बहुमत के अभाव में इस प्रस्ताव को संसद में पारित कराने में चार बार विफल रही थी। तीन बार विफल रहने पर टेरीजा मे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जॉनसन की पूर्व सरकार ने ईयू के साथ अलगाव के लिए समझौता किया था लेकिन बहुमत न होने से वह उस पर संसद की मुहर नहीं लगवा सके थे। इसके चलते ब्रेक्जिट के लिए 31 अक्टूबर की तय समयसीमा टल गई थी। इसी के बाद जॉनसन ने मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला किया। ब्रेक्जिट का नारा देकर जनता से बहुमत मांगा। मतदाताओं ने भी जॉनसन की मांग पूरी की।

जयपुर धमाकों के चारों दोषियों को फांसी की सजा

जागरण संवाददाता, जयपुर

जयपुर में 2008 को हुए श्रद्धलाबद्ध बम धमाकों के चारों दोषियों को विशेष अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार को दिए फैसले में कहा, सैफुर्रहमान अंसारी, मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मुहम्मद सरवर आजमी और मुहम्मद सलमान ने इंडियन मुजाहिदीन के अपने आकाओं के कहने पर दिल्ली में साजिश रची और फिर धमाकों को अंजाम दिया। ज्ञात हो, 13 मई 2008 की शाम श्रृंखलाबद्ध आठ बम धमाकों में गुलाबी नगरी दहल उठी थी। 11 साल सात माह पहले महज 15 मिनट में हुए विस्फोटों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे। कोर्ट ने बुधवार को चारों को दोषी करार दिया था।

महज दस मिनट में सुनाया फैसला : अजय कुमार शर्मा ने मात्र 10 मिनट में अपना फैसला सुना दिया। सबसे पहले सैफुर्रहमान, फिर सैफ उर्फ कैरीऑन को फांसी की सजा सुनाई। फिर बोले, 'जो सजा उक्त दोनों को दी गई है, वही शेष दो अन्य दोषियों को सुनाई जाती है।' उन्होंने फैसले में देश में जिहादी मानसिकता के चलते किए गए धमाकों पर भी टिप्पणी की। साथ ही विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार की तरफ से दिए गए मुआवजे की जानकारी मांगी।

जानें इंडियन मुजाहिदीन के इन चारों गुर्गों के बारे में

मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन।

मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, (पिता सपा के पदाधिकारी रहे) निवासी सरायमीर, आजमगढ़ (उप्र)। **गिरफ्तारी** : 23 दिसंबर 2008

पहला बम धमाका इसी ने किया था। माणक चैक खंदे क्षेत्र में बम रखा।

मुहम्मद सरवर आजमी

मुहम्मद सरवर आजमी, (प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार का सदस्य) निवासी-चांद पट्टी, आजमगढ़ (उप्र) **गिरफ्तारी** : जनवरी 2009 में चांदपोल हनुमान मंदिर के सामने बम रखा था।

सैफुर्रहमान अंसारी

सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी(पिता समेत परिवार में तीन सदस्य डॉक्टर) निवासी-आजमगढ़(उत्तर प्रदेश)। **गिरफ्तारी** : 23 अप्रैल 2009

छोटी चौपड़ पर फूल वालों के खंदे में बम रखा था। धमाके में कई बेगुनाह मारे गए थे।

मुहम्मद सलमान। सभी फाइल फोटो

मुहम्मद सलमान, **निवासी** : निजामाबाद, सरायमीर आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। **गिरफ्तारी** : 3 दिसंबर 2010। सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखा। धमाके में कई श्रद्धालुओं की हुई थी मौत।

किसी ने बम लगाते हुए नहीं देखा, हाई कोर्ट में करेंगे अपील पेज>>2

खरी बात

सही और सच्चे कारोबारी फैसलों पर नहीं होगी कोई अनुचित कार्रवाई, प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक सुस्ती के दौर से और मजबूत होकर निकलेगा देश, पारदर्शी और मजबूत बैंकिंग प्रणाली से मिलेगी पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को मदद

डरें नहीं, बैंक और उद्योग खुलकर करें निवेश : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जांच व कार्रवाई के डर से कर्ज देने में हीलाहवाली कर रहे बैंकों और खर्च करने से हिचक रहे उद्योग जगत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर फैसले लेने, निवेश करने और खर्च करने को कहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सही और वास्तविक वाणिज्यिक निर्णयों पर कोई अनुचित कार्रवाई नहीं होगी। मोदी ने कॉरपोरेट जगत को विश्वास दिलाते हुए कहा कि पुरानी कमजोरियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार-चढ़ाव पहले भी आए हैं, लेकिन देश हर बार ऐसी स्थिति में पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला है। इसलिए अभी की स्थिति से भी भारत अवश्य बाहर निकलेगा।

अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और मांग में कमी के लिए बैंकों से मिलने वाले कर्ज में कमी पर उद्योग निरंतर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। कई सेक्टर खासतौर पर एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र कर्ज की कमी की शिकायत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एनपीए की आशंका में बैंकों ने कर्ज देने की रफ्तार धीमी कर दी है। इन आशंकाओं को दूर करते हुए पीएम ने कहा, पिछले पांच साल में लिए गए सरकार के फैसले उद्योग जगत की पूंजी को सुरक्षित रखने में मदद करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री उद्योग संगठन एसोचैम की सालाना बैठक को संबोधित कर रहे थे। एसोचैम की स्थापना का यह सौवां वर्ष है। पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य पर पीएम ने कहा, देश की बैंकिंग प्रणाली की नींव अब इतनी पारदर्शी और मजबूत हुई है कि वह इस लक्ष्य को ताकत दे सकती है। गत 20 वर्ष में जितना एफडीआइ भारत आया, उसका 50 फीसद बीते पांच साल में आया है। देश ने अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार किया है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में है। सरकार के कामों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री चुटकी लेने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा, 'अगर पांच साल के कार्यों के बाद पिछले छह महीने के उदाहरण और देने लगूंगा तो आपका लंच ब्रेक तो गया समझिए।'

असंभव को संभव किया : इस लक्ष्य की चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने पिछले कार्यकाल के चुनौती भरे लक्ष्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 60 महीने में 60 करोड़ की आबादी को खुले में शौच से मुक्ति दिलाकर असंभव को संभव कर दिखाया। तीन साल से भी कम समय में आठ करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना, 10 लाख से अधिक गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खड़े करना असंभव लगता था, लेकिन संभव हुआ। हर परिवार को बैंकिंग से जोड़ना, हर बेघर को अपना पक्का घर देना असंभव लगता था, लेकिन यह संभव हो रहा है।

'हमसे पहले इकोनॉमी की तबाही का तमाशा देख रहे थे कुछ लोग' पेज>>12

नई दिल्ली में शुक्रवार को उद्योग संगठन एसोचैम की सालाना बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

'इरादे भी साफ हैं और हौसले भी बुलंद हैं'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भविष्य के लिए हमारे इरादे भी साफ हैं और हौसले भी बुलंद हैं। इस सरकार की पहचान ही यही है कि जो कहती है वह करती है। पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य भी इसलिए संभव है क्योंकि ऐसी अनेक बातें जो पहले असंभव लगती थीं, उन्हें देश ने संभव करके दिखाया है।' मोदी ने उद्योग जगत को सकारात्मक सोच का संदेश देते हुए कहा, 'इसी सकारात्मकता के आधार पर हम पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश इसे ताकत देगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।'

पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नौ सेना के सात अफसर गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसियां : भारतीय नौसेना की संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगाने वाले एक पाकिस्तानी जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और नौसेना की इंटेलिजेंस विंग के साथ मिलकर 'ऑपरेशन डॉल्फिंस नोज' चलाया। देश के अलग-अलग हिस्सों से अब तक नौसेना के सात अफसरों और एक हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने इन सभी को विजयवाड़ा की अदालत में पेश किया जहां इन्हें तीन जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार सातों नौसैनिक अफसर मुंबई, करवर (कर्नाटक) और विशाखापत्तनम में तैनात थे। इन्होंने भारतीय युद्धपोतों व पनडुब्बियों के मूवमेंट की जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों को दी हैं। इससे सुरक्षा संबंधी अहम ठिकानों की खुफिया जानकारियां दुश्मनों के हाथ लग गई हैं।

'ऑपरेशन डॉल्फिंस नोज'

- भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों के मूवमेंट की जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों को दीं
- आरोपित भारतीय नौसैनिक मुंबई, करवर और विशाखापत्तनम में थे तैनात

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन नौसैनिकों को विशाखापत्तनम से, दो को करवर और दो को मुंबई से पकड़ा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंटों को देश के जल क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले ईस्टर्न नेवल कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड की जानकारियां हासिल हो गई हैं। इन गिरफ्तारियों के अलावा कुछ अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ चल रही है।

पाकिस्तान को अरिहंत पनडुब्बी की हर गतिविधि का पता चला पेज>>7

14 डिजिटल रथ तैयार किए हैं भाजपा ने। इनके माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को उनके मकान व भूखंड का मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के फैसले के बारे में बताया जाएगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 21 दिसंबर 2019

न्यूज गैलरी

एकेटीयू ने घोषित की स्थगित परीक्षा की नई तिथि

ग्रेटर नोएडा : डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि ने स्थगित की गई सेमेस्टर परीक्षाओं की नई तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाएं पांच, छह व सात जनवरी को आयोजित होंगी। नई परीक्षा तिथि के संबंध में विवि ने जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी डाल दी है। साथ ही विवि प्रबंधन ने छात्रों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज कर भी नई परीक्षा तिथि की जानकारी दी है। एकेटीयू की सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून से खराब हुए माहौल को देखते हुए विवि ने 19 से 21 दिसंबर तक सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी थीं। इससे छात्रों को निराशा हुई थी। छात्रों को परीक्षा की नई तिथि का इंतजार था। नई तिथि घोषित करने के लिए विवि प्रबंधन ने बैठक। इसके बाद पांच, छह व सात जनवरी को परीक्षा आयोजन पर सहमति बनी। ज्यादातर छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं अब समाप्त हो गई हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन दो जनवरी के बाद होना है। ठंड और अवकाश को देखते हुए ज्यादातर छात्रों ने अपने-अपने घरों को रवानगी शुरू कर दी है। (जासं)

मुनिरका गांव के पॉलीक्लीनिक में खोला फिजियोथेरेपी सेंटर

नई दिल्ली : आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र के मुनिरका गांव की पॉलीक्लीनिक और प्रसूति गृह में नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने शुक्रवार को फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर सांसद निधि के तहत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से बनाया गया है। इस दौरान आरके पुरम के पूर्व विधायक व भाजपा के नई दिल्ली जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा और स्थानीय पार्षद भगत टोकस मौजूद रहे। सासंद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भाजपा सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लगातार देश के अंतिम नागरिक तक सभी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। मैं खुद भी इलाके में सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हूं। पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि इस फिजियोथेरेपी सेंटर में अत्याधुनिक मशीनें आने से गांव व आसपास के लोगों को काफी सहुलियत होगी। अभी तक यहां पर ओपीडी, प्रसूति विभाग, दंत रोग विभाग, आयुर्वेदिक चिकित्सा, महिला रोग विभाग, व सभी प्रकार के टीकाकरण की निशुल्क व्यवस्था तो थी ही, अब यहां पर कुछ और नई सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे लोगों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पर मिल सकेंगी। (जासं)

यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल बढ़ाने पर आज लग सकती है मुहर

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बने यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। शनिवार की बोर्ड बैठक में टोल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि टोल दरें मामूली बढ़ाई जाएंगी। बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया तो नए साल से वाहन यात्रियों को अधिक टोल देना पड़ेगा। बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया तो यमुना प्राधिकरण जेपी के साथ एस्क्रो अकाउंट खोलेगा। उसमें जमा होने वाली धनराशि को प्राधिकरण एक्सप्रेस वे के रखरखाव पर खर्च कराएगा। वहीं, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर यमुना प्राधिकरण भी सेक्टर 29 में एक्सपो मार्ट का निर्माण कराने की योजना बना रहा है। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर के तमाम आयोजना यीडा सिटी में होंगे। एक्सप्रेस वे के किनारे बनने वाले एक्सपो मार्ट में आयोजन और संगोष्ठियां आयोजित हो सकेंगी। (जासं)

ऑडिट के लिए फाइल न देने वालों अफसरों पर होगी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कैग ऑडिट चल रहा है। बताया जाता है कि कई अधिकारी व कर्मचारी ऑडिट के लिए टीम को फाइल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऑडिट टीम ने इसकी शिकायत आला अफसरों से की है। आला अफसरों ने विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट देने की तैयारी कर ली है। चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का कैग ऑडिट चल रहा है। ऑडिट टीम ने प्राधिकरण से 2012 के बाद की फाइलें तलब की थीं। बताया जाता है कि अनेक फाइलें संबंधित अफसरों व कर्मचारियों ने नहीं दी। ऑडिट टीम ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गईं। इससे ऑडिट में अड़चन आ रही है। (जासं)

तैयारी ▶ आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में उपमुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार अभियान का नारा किया लांच

अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल

इस नारे के साथ अगले दो दिनों में पार्टी सभी 70 विस क्षेत्रों में पदयात्रा करेगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में औपचारिक तौर पर 2020 विधानसभा चुनाव अभियान लांच कर दिया। पार्टी ने 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' के नारे के साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अगले दो दिनों में पार्टी इस नारे के साथ सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करेगी। इस नारे को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

डीडीयू मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार अभियान का नारा लांच करने के दौरान कहा कि जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि पांच साल बहुत अच्छे बीते। पांच साल में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए। प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी। 24 घंटे बिजली मिलने लगी, नहीं तो पॉवर कट की वजह से लोगों की जिंदगी जनरेटर व इनवर्टर पर गुजर रही थी। जिन इलाकों में लोग टैंकर माफिया के बीच पिस रहे थे, पांच साल में उनसे आजादी मिल गई। बिजली देश में सबसे सस्ती हो गई। लगभग 70 फीसद घरों में बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा से लेकर मोहल्ला क्लीनिक तक के काम को देख कर लोग कह रहे हैं कि पांच साल बहुत अच्छे बीते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अगले पांच साल तक भी मुख्यमंत्री बने रहें। अब चुनाव का समय आ गया है। आज आम आदमी पार्टी अपना चुनावी अभियान लांच कर रही है, जो जनता के बीच से निकल कर आया है।

आम आदमी पार्टी मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनावी अभियान का शुभारंभ करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (दाएं) और साथ मंत्री गोपाल राय। सौ. आम आदमी पार्टी

इस तरह चलेगा प्रचार अभियान

मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल' अभियान के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में 21 व 22 दिसंबर को पद यात्रा निकाली जाएगी। अलग-अलग वार्ड में पद यात्राएं होंगी और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 दिसंबर को सरकार के पांच साल के काम का रिपोर्ट कार्ड लांच करेंगे। 25 दिसंबर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस रिपोर्ट को लेकर घर-घर जाएंगे। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 35 लाख घरों तक रिपोर्ट लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधायक व नेता 10 से 15 दिन के अंदर 700 मोहल्ला सभाएं करेंगे। वरिष्ठ नेताओं द्वारा सात बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनता काम के नाम पर फिर से हमें वोट देगी। पार्टी का चुनाव अभियान लॉंच किए जाने के मौके पर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के दिल्ली प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, दिल्ली संयोजक गोपाल राय, कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन व राजेंद्र पाल गौतम सहित पार्टी से सांसद, विधायक व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे।

ऐसा कम होता है कि नेता जाकर जनता से पूछे कि हमने क्या-क्या किया : सिसोदिया ने कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि पांच साल की सरकार के बाद कोई नेता या मंत्री जनता के बीच जाए और चुनाव से ठीक पहले पूछे कि आप बताओ कि हमने क्या-क्या काम किए। आम तौर पर यही होता है कि चुनाव से ठीक पहले लोगों के बीच नेता जाकर पांच या दस मिनट का भाषण देकर कहता है कि हमने बहुत काम किया, इसलिए हमे वोट दो। हमने पिछले दिनों जो जनसंवाद किए, उनमें जनता से जाकर हमने पूछा कि आप बताओ की क्या काम हुआ और जनता ने हर सभा में कहा कि 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल'। हर जगह से यह नारा निकल कर आ रहा है। आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का यह अभियान शुरू हो रहा है।

हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन न होने का मुख्य सचिव से पूछा कारण

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में भूकंपरोधी इमारत बनाने के संबंध में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं होने का दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से कारण पूछा है। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी एवं न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने साथ ही इस संबंध में कार्य योजना को अधिसूचित करने के लिए दिल्ली सरकार को अंतिम मौका दिया। अगली सुनाई 8 फरवरी को होगी।

इस बाबत हाई कोर्ट ने 26 अगस्त 2015, 9 फरवरी 2016, एक फरवरी और एक मई 2019 को अलग-अलग आदेश दिए थे। पीठ ने इससे पहले कई फैसलों में अधिकारियों को भूकंपरोधी इमारत बनाने के संबंध में कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। अधिवक्ता अर्पित भार्गव की जनहित याचिका पर पीठ ने पूछा था कि अगर नेपाल में भूकंप आता है, तो दिल्ली में इमारतें कितनी सुरक्षित हैं। भार्गव ने कहा था कि अगर अधिकारियों ने अदालत के पिछले आदेशों का अनुपालन किया होता तो शहर के हालात इतने बदतर नहीं होते। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने पीठ को बताया कि कार्य योजना तैयार कर ली गई है। दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए फाइल वापस भेज दी है।

कोहरे के कारण 19 उड़ानें रद, 250 देरी से उड़ीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ठंड के साथ ही राजधानी में कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आइजीआइ एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं चरमराने लगी हैं। शुक्रवार की सुबह एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर के करीब पहुंच गया था। इसकी वजह से आइजीआइ से आने और जाने वाली 19 उड़ानें रद की गईं। 250 विमानों का संचालन देरी से हुआ। उधर, खराब मौसम और कोहरे के कारण दिल्ली आ रही पांच उड़ानों को डायवर्ट कर अन्य एयरपोर्ट पर उतारा गया। उड़ानों की लेटलतीफी से विमान यात्री खासे परेशान हुए।

गुरुवार को राजधानी में पहली बार घना कोहरे छाया था। इसकी वजह से और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के कारण आइजीआइ एयरपोर्ट से संचालित 25 उड़ानें रद की गई थीं और 25 को रिशेड्यूल किया गया था, जबकि 200 उड़ानें देरी से उड़ीं और उतरी थीं। एयरपोर्ट मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार आधी रात बाद से ही एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाना शुरू हो गया था। कोहरे के कारण सुबह 5.30 बजे तक दृश्यता का स्तर 50 मीटर तक पहुंच गया था। लिहाजा कैट-3बी तकनीक से उड़ानों का संचालन शुरू किया गया। इस दौरान जिन उड़ानों के पायलट कैट-3बी तकनीक से प्रशिक्षित नहीं थे, के अलावा अन्य 19 उड़ानों को रद कर दिया गया। इनमें 11 जाने और नौ आने वाली उड़ानें थीं। दिल्ली आ रही पांच उड़ानों को जयपुर व लखनऊ एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सुबह 8.30 बजे दृश्यता का स्तर 250 और 11.30 बजे 400 मीटर पर पहुंचा। इस दौरान करीब 250 उड़ानें आधे से दो घंटे की देरी से उड़ीं और उतरीं। दोपहर 12 बजे के बाद एयरपोर्ट पर सामान्य तौर पर उड़ानों का संचालन हो सका। प्रभावित उड़ानों में ज्यादातर अमृतसर, देहरादून, जम्मू, गोवा, पटना और बंगलुरू, कोलकाता के अलावा मिलान व दुबई की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी थीं।

रेल यात्रियों पर पड़ने लगी मौसम की मार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रेल यात्रियों पर कोहरे की मार पड़ने लगी है। शुक्रवार को एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें एक घंटे से ज्यादा देरी से राजधानी के अलग-अलग स्टेशनों पर पहुंचीं। नौ ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा। सबसे ज्यादा महाकौशल एक्सप्रेस 13 घंटे की देरी से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। विलंब से आने के कारण यह ढाई घंटे की देरी से रवाना हुई। सचखंड एक्सप्रेस भी लगभग साढ़े आठ घंटे की देरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी बढ़ रहा है। सुबह और देर रात को कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। ट्रेनें देरी से गंतव्य पर पहुंच रही हैं जिस वजह से कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा। शुक्रवार को जीटी एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे, महाबोधि एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, विक्रमशिला एक्सप्रेस तीन घंटे, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ढाई घंटे और कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से राजधानी स्थित रेलवे स्टेशनों पर पहुंची।

देरी से रवाना होने वाली ट्रेनें

- सिकंदराबाद दूरंतो एक्सप्रेस 3.20 घंटे
- गोमती एक्सप्रेस 3.05 घंटे
- श्रीगंगानगर इंटर सिटी एक्सप्रेस 3.05 घंटे
- आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस 2.55 घंटे
- नई दिल्ली-जालंधर सिटी एक्सप्रेस 2.45 घंटे
- हजरत निजामुद्दीन-भुसावल एक्सप्रेस 2.40 घंटे
- महाकौशल एक्सप्रेस ढाई घंटे
- ताज एक्सप्रेस 2.05 घंटे
- आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 2.05 घंटे

लगातार दूसरे दिन जाम से जूझते रहे राजधानी के लोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गुरुवार को भीषण जाम झेलने के बाद राजधानी में शुक्रवार को भी वाहन चालकों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल सकी। शुक्रवार सुबह से विभिन्न इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन के चलते जाम लगा रहा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। विरोध-प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी, बावजूद भीड़ बढ़ती गई और यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हालत यह थी कि यातायात के सभी बंदोबस्त नाकाफी नजर आए। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की तरफ से कई जगह सड़कों पर बेरिकेड लगाने और रूट डायवर्जन के कारण भी जाम लगा।

जामिया से लेकर जामा मस्जिद और जाफराबाद-सीलमपुर में शुक्रवार को भी प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। वहीं जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस व इंडिया गेट पर प्रदर्शन से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई।

जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली गेट के बीच यहां लगा जाम : जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली गेट के बीच प्रदर्शन करने वाले लोगों द्वारा किए गए मार्च के कारण कई इलाकों के कई मार्गों को बंद कर दिया गया था। कई सड़कों पर डायवर्जन किया गया है। इस कारण सुभाष मार्ग, पीली कोठी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, लाल किला और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मार्ग पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। इन इलाकों में लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

दूसरी ओर जंतर-मंतर पर हालांकि कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन, एहतियातन मंडी हाउस जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया। इस कारण तिलक मार्ग, इंडिया गेट, संसद मार्ग, बाराखंभा, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, शिवाजी स्टेडियम से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाम लग गया। यह हालत सुबह करीब 11 बजे से शुरू होकर देर शाम तक बनी रही। इन मार्गों पर घंटों वाहन रेंगते रहे।

सीलमपुर से इन इलाकों में लगा जाम : यमुनापार के सीलमपुर व जाफराबाद इलाके में हुई हिंसा के बाद इलाके में बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च करने और जगह-जगह जांच-पड़ताल करने के कारण सीलमपुर से लेकर वेलकम, जाफराबाद, शाहदरा, भजनपुरा, सीमापुरी व नंद नगरी में भी जाम की स्थिति बन गई। सीमापुरी, नंद नगरी व दिलशाद गार्डन के आसपास के इलाकों में वाहनों की सघन जांच के कारण भी वाहनों की गति धीमी रही।

चाइनीज ई स्कूटर बने आकर्षण का केंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रगति मैदान में शुक्रवार को 10वें ईवी एक्स्पो 2019 का उद्घाटन हुआ। सुरक्षा कारणों के चलते बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के न पहुंचने पर उनके संदेश के साथ ही प्रदर्शनी शुरू की गई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश में ईंधन के मुकाबले बिजली काफी सस्ती है। इसलिए भविष्य में ई-वाहन एक अच्छा विकल्प साबित होगा।

ई -रिक्शा समिति के अध्यक्ष व ईवी एक्सपो के संस्थापक निदेशक अनुज शर्मा ने कहा कि देश भर में वाहनों के धुएं से निकलने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में कदम बढ़ाना अब बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में इको-फ्रेंडली टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिक कार्गो के साथ-साथ वाहनों के पुर्जे, सामान, चार्जिंग स्टेशन, लीथियम आयन बैटरियां और इस क्षेत्र से संबंधित प्रोडक्ट और सेवाओं में आए नए तकनीकी बदलाव और उन्नति को प्रदर्शित किया गया है। एक्सपो में 250 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-वाहन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस प्रदर्शनी में चीन की कंपनी डाओ के इलेक्ट्रिक स्कूटर खासे आकर्षण का केंद्र हैं। दो मॉडलों में प्रदर्शित एक स्कूटर ऐसा है, जिसकी गति 25 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। इसलिए इसे चलाने के लिए न तो लाइसेंस चाहिए और न ही इसका पंजीकरण कराना होगा।

ठिठुरन भरी ठंड से राहत नहीं, प्रदूषण भी हुआ गंभीर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : शुक्रवार को भी दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड से राहत नहीं मिली। बादल छाए रहने से दिन भर कंपकंपाहट बनी रही। दूसरी तरफ कोहरा बढ़ने से प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में सभी जगह एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। शनिवार को भी इस स्थिति से राहत के आसार नहीं हैं और बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 69 से 100 फीसद दर्ज किया गया। शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कोहरा होगा, जबकि बाद में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 और 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शुक्रवार को कोहरे की वजह से सुबह साढ़े पांच बजे पालम और सफदरजंग पर दृश्यता का स्तर शून्य रहा। सुबह साढ़े 11 बजे दृश्यता करीब 600 मीटर हो पाई।

दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 432 दर्ज किया गया। एनसीआर के शहरों में गाजियाबाद का एयर इंडेक्स 444, फरीदाबाद का 420, ग्रेटर नोएडा का 427 और नोएडा का 463 दर्ज किया गया।

दिल्ली में आठ सालों में 15 फीसद बढ़ा प्रदूषण

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली के वायु प्रदूषण में 25 फीसद कमी के दावों पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एजेंसी सफर का कहना है कि आठ सालों में यह प्रदूषण 15 फीसद बढ़ गया है। परिवहन, उद्योगों और ऊर्जा उत्पादन से होने वाला प्रदूषण बढ़ा है, जबकि रिहायशी क्षेत्रों में निर्माण और धूल से होने वाला प्रदूषण घटा है। इससे भी बड़ी बात यह कि खराब और बहुत खराब श्रेणी के प्रदूषण वाले दिन भले कुछ कम हुए हों, लेकिन गंभीर श्रेणी के प्रदूषण के दिन बढ़ गए हैं।

सफर द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2018 तक के प्रदूषण ट्रेंड में खासा बदलाव देखा गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि बेशक पराली का धुआं प्रदूषण बढ़ाता है, लेकिन प्रदूषण बढ़ाने के लिए 26 अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। इनमें कोयला-उपले, ढाबे, कंस्ट्रक्शन साइट, बड़े अस्पताल, ट्रैफिक जंक्शन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लचर परिवहन व्यवस्था, कचरा जलाना, बायोमेडिकल कचरा, मोबाइल टावर, डीजल जनरेटर, हवा की गति एवं दिशा तथा श्मशान घाट प्रमुख हैं।

सफर की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में प्रमुख प्रदूषक तत्व पीएम-2.5 ही नहीं, पीएम-1 भी तेजी से बढ़ रहा है। लोधी रोड और चांदनी चौक में इसकी मॉनीटरिंग की गई है। आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सर्दियों के चार माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के 120 में से लगभग 76 दिन बहुत खराब या गंभीर श्रेणी का प्रदूषण झेलना पड़ता है।

2010 से 2018 के बीच किन क्षेत्रों में कितना प्रदूषण बढ़ा, कितना घटा

क्षेत्र	पीएम 2.5 (2010)	पीएम 2.5 (2018)	घटा/बढ़ा
परिवहन	32	41	40
उद्योग	17.3	22.3	48
बिजली	3.0	3.1	16
रिहायशी क्षेत्र	18.5	5.7	64
धूल	27.8	18.1	26
नए स्रोत	1.3	11.7	800

दिल्ली के प्रदूषण का ट्रेंड बदल रहा है। इसे समझना होगा और उसी के अनुरूप उसे कम करने की प्लानिंग करनी होगी। प्रदूषण का मुद्दा अब गंभीर हो चुका है। बहुत सी व्यवस्थाओं में बदलाव करना भी जरूरी हो गया है।
-डा. गुरफान बेग, निदेशक, सफर

कोयले का उपयोग बंद करना जरूरी : सुनीता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कोयले का उपयोग पूर्णतया बंद करना होगा। चीन का बीजिंग शहर भी इसीलिए प्रदूषण मुक्त हो पाया क्योंकि वहां पर एक किलो कोयला भी नहीं जलाया जाता। ऐसा ही यहां करना होगा। इसके अलावा पुराने ट्रकों का परिचालन बंद करके बीएस छह के मानकों पर आधारित व्यावसायिक वाहनों का ही उपयोग हो। ऑटोरिक्शा बंद करके उनकी जगह भी ई-रिक्शा चलें तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

सुनीता शुक्रवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में सीएसई द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण : आगे क्या? विषय पर आयोजित परिचर्चा में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण ऐसी समस्या है, जिसका राजनीतिकरण नहीं बल्कि इसे थामने के लिए ठोस एक्शन होना चाहिए। हकीकत में इसके विपरीत हो रहा है। एक्शन की जगह इस पर राजनीति ही ज्यादा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत नहीं किया जाएगा, उन्हें अधिकार और पूरे संसाधन नहीं दिए जाएंगे, स्वच्छ वायु मिलना संभव नहीं है।

सुनीता नारायण। फाइल

सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी का कहना था कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि उनके जरिए वायु गुणवत्ता की निगरानी मानकों के अनुरूप की जाए। कहने को दिल्ली में 38 से 40 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, लेकिन तब भी यह कह पाना मुश्किल है कि यहां वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है। उन्होंने कहा कि 25 फीसद प्रदूषण कम होने की खुशी मनाने से ज्यादा जरूरी है कि 75 फीसद प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रयास किए जाएं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था सफर के निदेशक डॉ. गुरफान बेग ने बताया कि पीएम 2.5 और पीएम 10 में 65 फीसद तक का अंतर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की लोकेशन भी एक कार्यप्रणाली के तहत ही निर्धारित की जानी चाहिए। इन्हें कहीं भी लगाने से पूर्व बैकग्राउंड, रिहायश, औद्योगिक क्षेत्र, हवा की दिशा इत्यादि कई पहलुओं पर गौर करना चाहिए। डॉ. बेग ने यह भी कहा कि प्रदूषण कम करने की दिशा में कम बारिश हमेशा खतरनाक होती है, इससे प्रदूषण कम होने की बजाय और अधिक बढ़ जाता है।

कामयाबी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहल पर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी से 25 तक आ जाएंगी मूर्तियां, इन्हें तमिलनाडु के वीरांगल्लूर से चुराया गया था

ऑस्ट्रेलिया से आएंगी 9वीं-10वीं शताब्दी की मूर्तियां

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

भारत से चुराकर विदेश में करोड़ों में बेच दिए गए पुरावशेष (मूर्तियों) को वापस लाने की दिशा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने एक और पहल की है। जल्दी ही एएसआइ ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में मौजूद तीन भारतीय मूर्तियों को वापस लेकर आएगी। इन मूर्तियों में दो तमिलनाडु के वीरांगल्लूर से चुराई गई थीं, जो दो द्वारपालों की मूर्तियां हैं। एक राजस्थान से चुराई गई नागराज की मूर्ति है।

एएसआइ अधिकारियों के अनुसार तीनों मूर्तियों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एएसआइ के अनुसार तीनों मूर्तियों को 18 दिसंबर तक लाया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से 25 दिसंबर तक इन्हें लाया जा सकता है। गौरतलब है कि जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का भारत दौरा प्रस्तावित है।

7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की हैं मूर्तियां : द्वारपालों की मूर्तियां पत्थर की हैं और 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं। इन्हें तमिलनाडु के वीरांगल्लूर से 1995 में चोरी कर लिया गया था। इसके अलावा तीसरी मूर्ति नागराज की है जो राजस्थान या मध्यप्रदेश से चोरी की बताई जा रही है। यह मूर्ति 7वीं से आठवीं शताब्दी की है। इसे साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने न्यूयॉर्क से खरीदा था। इस मूर्ति के बारे में कोई एफआइआर दर्ज नहीं है। इसके चलते यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसे इन दोनों राज्यों में से किस राज्य के किस मंदिर से कब चोरी किया गया था। हालांकि इसके निर्माण शैली से माना जा रहा है कि इसे राजस्थान या मध्य प्रदेश के किसी मंदिर से चोरी किया गया था।

इससे पहले पांच साल में आ चुकी हैं 32 मूर्तियां : 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से पिछले पांच साल में 32 मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। कुछ देशों ने विदेशों के भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर मूर्तियां सौंपी हैं। जो मूर्तियां वापस आई हैं, उनमें मध्य प्रदेश से चोरी हुई पैरेट लेडी, जम्मू-कश्मीर से दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, तमिलनाडु से चोरी हुई उमा परमेश्वरी, गणेश की प्रतिमा, श्री देवी, पार्वती, भूदेवी आदि की मूर्तियां शामिल हैं।

कहां से कितनी मूर्तियां वापस आई

▶ संयुक्त राज्य अमेरिका-21, ऑस्ट्रेलिया-6, कनाडा-1, जर्मनी-1, सिंगापुर-1, यूके- 2

ऑस्ट्रेलिया से जल्द वापस आएंगी द्वारपालों की मूर्तियां। सौजन्य : पुरातत्व विभाग

यादव सिंह के बेटे पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

करोड़ों रुपये के टेंडर घोटाले के आरोपित नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे सनी यादव पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। सनी यादव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रबंधक परियोजना के पद से निलंबित चल रहा है। उस पर भ्रष्टाचार व प्राधिकरण से बिना बताए अनुपस्थित रहने का आरोप है। औद्योगिक विकास विभाग ने सनी यादव को अंतिम नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। जवाब न देने पर सनी यादव को बर्खास्त किया जा सकता है।

सनी यादव लंबे समय तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रबंधक परियोजना के पद पर तैनात रहा। उसके पिता यादव सिंह पर टेंडर घोटाले व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। साथ ही सनी यादव भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपित है। 2018 में सनी यादव प्राधिकरण से जानकारी दिए बिना अनुपस्थित चल रहा था। आठ मार्च 2018 को तत्कालीन सीईओ देवाशीष पंडा ने उसे निलंबित कर दिया था। मामले की जांच के आदेश एसीईओ केके गुप्ता को दिए गए थे। इसी बीच प्राधिकरणों का केंद्रीकरण हो गया। एसीईओ ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। शासन ने जुलाई 2018 में सनी यादव को नोटिस जारी किया था। जुलाई से जनवरी 2019 तक सनी यादव जेल में रहा। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं थी। प्राधिकरण से यह बात पूछी गई तो जवाब दिया गया कि सनी यादव ने यह जानकारी नहीं दी। सनी पर जानकारी छुपाने का भी आरोप है। गत माह सनी को फिर से नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

भारतीय प्रतिभा के प्रवाह में रोड़ा ना बने अमेरिका : एस. जयशंकर

विदेश मंत्री बोले ▶ एच-1बी वीजा ना सिर्फ आर्थिक सहयोग का अहम हिस्सा है बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक सेतु जैसा भी है

व्हाइट हाउस में अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन के साथ इस मसले पर हुई चर्चा

'टू प्लस टू वार्ता' के बाद पत्रकारों से बातचीत करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएफपी

वाशिंगटन, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एच-1बी वीजा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत से होने वाली प्रतिभा के प्रवाह की राह में अमेरिका को रोड़ा नहीं बनना चाहिए। यह वीजा ना सिर्फ आर्थिक सहयोग का अहम हिस्सा है बल्कि दोनों देशों के बीच तकरीबन रणनीतिक सेतु की तरह काम करता है। एच-1बी वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है। इस वीजा के जरिये हर साल बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने इस वीजा पर लगाम लगा दिया है।

वाशिंगटन में आयोजित 'टू प्लस टू वार्ता' में हिस्सा लेने के बाद जयशंकर ने गुरुवार को भारतीय पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, 'कुछ बैठकों में मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने हितों को रेखांकित किया कि अमेरिका में भारतीय प्रतिभा के प्रवाह में रोड़ा नहीं अटकाया जाना चाहिए। प्रतिभा का प्रवाह हमारे आर्थिक सहयोग का हिस्सा है।' उन्होंने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के साथ इस मसले पर भी चर्चा हुई।

एच-1बी वीजा के जरिये कुशल विदेशी पेशेवरों को मिलती है नौकरी

प्रतीकात्मक फोटो

एच-1बी वीजा के जरिये अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में अत्यंत कुशल विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रखने की अनुमति मिलती है, जिनमें अमेरिकी पेशेवरों की कमी है। यह वीजा तीन साल के लिए जारी होता है और छह साल तक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आम श्रेणी में 65 हजार एच-1बी वीजा जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त 20 हजार एच-1बी वीजा उन लोगों को दिए जाते हैं, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है।

पाक पर ट्रंप प्रशासन का रुख सख्त

- अमेरिका चाहता है इस्लामाबाद आतंकवाद पर तुरंत उठाए ठोस कदम
- टू प्लस टू वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पत्रकारों को दी जानकारी

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान पर ट्रंप प्रशासन का रुख एकदम स्पष्ट और सख्त है। वह चाहता है कि इस्लामाबाद आतंकवाद पर तुरंत ठोस कदम उठाए। आतंकी संगठनों पर लगाम कसने के लिए सतत और स्थिर कार्रवाई करे। साथ ही पाकिस्तान यह सुनिश्चित भी करे कि आतंकवाद के लिए उसकी धरती का इस्तेमाल ना होने पाए।

वाशिंगटन में 'टू प्लस टू वार्ता' के बाद जयशंकर ने गुरुवार को भारतीय पत्रकारों से कहा, 'पाकिस्तान के संबंध में हमने सुना है कि अमेरिकी पक्ष का रुख एकदम स्पष्ट है। वह चाहता है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत, निरंतर और स्थिर कार्रवाई करे।' जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ 'टू प्लस टू वार्ता' हुई थी। जयशंकर ने बताया कि इस वार्ता के दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण पूर्व एशिया के मसलों पर भी चर्चा हुई। हालांकि यह वार्ता मुख्य रूप से विदेश, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मसलों पर केंद्रित रही।

कश्मीर पर हुई संक्षिप्त चर्चा : विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि 'टू प्लस टू वार्ता' के दौरान पोंपियो और अमेरिकी सांसदों के साथ एक अलग मुलाकात में कश्मीर की स्थिति व नागरिक संशोधन कानून पर संक्षिप्त चर्चा हुई।

ट्रंप से राजनाथ और जयशंकर ने की मुलाकात

अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ 'टू प्लस टू वार्ता' के बाद विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। एएनआइ समाचार एजेंसी के अनुसार, इस दौरान व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। दोनों भारतीय मंत्रियों की ट्रंप के साथ करीब आधे घंटे मुलाकात चली।

कश्मीर मसले पर भारतवंशी सांसद से मिलने से विदेश मंत्री ने किया इन्कार

वाशिंगटन, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने वाले अमेरिकी सांसदों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने भारतीय मूल की महिला सांसद प्रमिला जयपाल से भी मिलने से इन्कार कर दिया। चेन्नई में जन्मी प्रमिला ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया था। इसमें उन्होंने भारत सरकार से अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद से जम्मू-कश्मीर में लगाई गई सभी पाबंदियों को हटाने की मांग की थी।

वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के समापन के बाद गुरुवार को विदेश मंत्री ने भारतीय संवाददाताओं के एक समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस महीने प्रतिनिधि सभा में पेश प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर की स्थिति का वास्तविक वर्णन नहीं किया गया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं उस प्रस्ताव से अवगत हूं। मुझे नहीं लगता कि यह जम्मू-कश्मीर की स्थिति की निष्पक्ष समझ या भारत सरकार जो कुछ वहां कर रही है उसका निष्पक्ष वर्णन है, इसलिए मेरी (प्रमिला जयपाल के साथ) मुलाकात करने की इच्छा नहीं हुई।'

भारत ने कश्मीर में प्रतिबंध का बचाव इस आधार पर किया है कि पाकिस्तान को छद्म और आतंकवादियों के माध्यम से शरारत करने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ऐसा कर सकता है।

विदेश मंत्री से पूछा गया था कि क्या आपने समिति (विदेश मामलों की) के पास जो प्रस्ताव है उसका उपाय कर लिया है जिसमें भारत में स्थिति की आलोचना की गई है? जयशंकर ने जवाब में कहा, 'मेरी रुचि ऐसे लोगों से मिलने में है जिनके पास लक्ष्य है और चर्चा के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है जिन्होंने पहले से ही अपनी मानसिकता बना रखी है।' इससे पहले वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर में कहा गया था कि जयशंकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपनी मुलाकात रद कर दी। अमेरिकी सांसदों ने जयपाल को बैठक से अलग करने से मना कर दिया जिसके बाद विदेश मंत्री ने यह फैसला लिया।

सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत-चीन के बीच बैठक आज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एनएसए अजीत डोभाल व चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में होगी वार्ता

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गठित विशेष प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता शनिवार को होगी। भारतीय पक्ष की अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे जबकि चीनी पक्ष की अगुवाई विदेश मंत्री वांग यी करेंगे। अक्टूबर, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई वार्ता के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच यह अहम वार्ता होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच होने वाली यह 22वीं बैठक है। वैसे इस बैठक से भी दशकों से लंबित पड़े सीमा विवाद का निपटारा निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब बातचीत काफी अहम दौर में पहुंच गई है।

ध्यान रखने की बात है कि मोदी और चिनफिंग के बीच हुई बैठक के बाद बावजूद दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। कश्मीर को लेकर रिश्तों में लगातार तनाव आ रहा है। वांग यी को सितंबर, 2019 में ही बैठक के लिए आना था लेकिन भारत ने इसे टालने का आग्रह किया था। माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह से चीन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था उसे देख कर ही भारत ने ही वार्ता को टाला था। भारत-चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसके एक बड़े हिस्से को लेकर दोनों देशों में असहमति है जिसे दूर करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता शुरू करायी गई थी।

चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि शनिवार से शुरू होने वाली दो दिवसीय वार्ता में अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण, सीमा प्रबंधन के साथ ही दूसरे साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच यह बैठक चीन में ही हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों को तेज करने की बात कही थी। यह भी बता दें कि मोदी और चिनफिंग के बीच हुई वार्ता के दौरान भी दोनों नेताओं ने सीमा विवाद का ऐसा हल निकालने की बात कही थी जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

जावडेकर ने कहा, भारत में 21 फीसद तक घट चुका है कार्बन उत्सर्जन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा, कॉप-25 में हुई भारत के कामों की सबसे ज्यादा तारीफ
- भारतीय हितों के खिलाफ नहीं लिया गया कोई भी फैसला

नई दिल्ली में शुक्रवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में मैड्रिड में संपन्न हुई कॉप- 25 की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। एएनआइ

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि पेरिस समझौते पर अमल करने वाले देशों में भारत शीर्ष पर है जो तेजी से अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि समझौते के तहत भारत को 35 फीसद तक कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य दिया गया था जो मौजूदा समय में करीब 21 फीसद तक कम हो गया है। वैसे तो भारत को यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करना है।

जावडेकर शुक्रवार को जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में संपन्न हुई कॉप (कांफ्रेस ऑफ पार्टीज)-25 की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में हालांकि बड़े फैसले नहीं लिए गए, लेकिन पेरिस समझौते के तहत दुनियाभर में जो काम हुए हैं उनकी समीक्षा की गई। इस दौरान भारत के कामों की सबसे ज्यादा तारीफ की गई और कोई भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो भारतीय रुख और हितों के विरुद्ध हो। भारत के अलावा और भी जिन देशों के कामों को सराहा गया, उनमें चीन और यूरोपीय यूनियन के ज्यादातर देश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कॉप-25 में विकसित देशों के रुख पर भी चर्चा हुई। खासकर पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को जो वित्तीय मदद दी जानी थी और जो उनकी ओर से नहीं दी जा रही है। बैठक में इस राशि को देने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसे अब 2020 से बढ़ाते हुए 2022 तय किया गया है।

जावडेकर ने विकसित देशों के इस रुख पर नाखुशी भी जताई और कहा कि पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को जो लक्ष्य दिए गए थे, वे उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जबकि विकसित देश अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते के बाद विकसित देशों से सिर्फ 0.02 फीसद राशि मिली है, जबकि समझौते के तहत उन्हें हर साल करीब 100 बिलियन डॉलर की वित्तीय मदद देनी थी।

भारत में पाक, बांग्लादेश, चीन के पर्वतारोहियों को लेनी होगी मंजूरी

- गृह मंत्रालय ने 70 साल पुराने आदेश में किया संशोधन
- भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन मार्गों का निर्धारण करेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन के पर्वतारोहियों को भारत में किसी शिखर पर पर्वतारोहण से पहले अनुमति लेनी होगी। उन्हें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा निर्धारित विशेष मार्गों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के एक आदेश में इस बात की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने 70 साल पुराने विदेशी आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को एक गजट अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि नागरिक या इन चार देशों के मूल वाले लोगों को जो शिखर 'खोले गए' हैं, उनपर पर्वतारोहण शुरू करने से पहले अनुमति लेनी होगी।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आइएमएफ) मार्गों का निर्धारण करेगा। इसके अलावा आइएमएफ संपर्क अधिकारी को संबद्ध करेगा और कुछ प्रतिबंध भी लगाएगा। जिन शिखरों को पर्वतारोहण के लिए खोला गया है उसके लिहाज से यह आवश्यक माना गया है। यह काम केंद्र सरकार द्वारा विशेष आदेश के तहत किया जाएगा।

भारत ने इससे पहले देश भर में 137 शिखरों को पर्वतारोहण के लिए खोला था। इन शिखरों में सिक्किम में कंचनजंघा और नेपाल पीक, उत्तराखंड में गरुड़ पर्वत और पूर्बी दूनागिरि, जम्मू-कश्मीर में माउंट कैलास और हिमाचल प्रदेश में मुल्किला शामिल थे। भारत में करीब 200 शिखर हैं।

गजट में कहा गया है कि कोई विदेशी या विदेशियों का समूह भारत में किसी भी पर्वतीय शिखर पर नहीं चढ़ेगा या चढ़ने का प्रयास करेगा। वे केवल उन्हीं शिखरों पर चढ़ सकेंगे जिन्हें पर्वतारोहण के लिए खोला गया है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।

पार्किंग की जगह नहीं है तो वाहनों के पंजीकरण में कमी करें : एनजीटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को दिल्ली समेत 122 शहरों के अफसरों से कहा कि अगर उनके यहां पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं है तो वे अपने यहां वाहनों के पंजीकरण में कमी लाएं और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाएं। ये 122 शहर वो हैं जहां के वायुमंडल में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है।

एनजीटी चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, पर्यावरण संरक्षण मानकों के तहत किसी भी शहर में वाहनों की संख्या पार्किंग की जगह की उपलब्धता के आधार पर सीमित होनी चाहिए। 'किसी प्रकार के नियामक मानकों के बिना सभी सार्वजनिक स्थलों व सड़कों को पार्किंग में तब्दील नहीं किया जा सकता। पर्यावरण मानकों के अनुपालन के लिए इस पहलू से योजना बनाया जाना पूर्व शर्त है। पार्किंग की अनुमति सिर्फ तय स्थानों पर ही दी जा सकती है। लिहाजा किसी भी अवैध पार्किंग के खिलाफ यातायात पुलिस समेत सभी विधिक अफसरों को सख्त कदम उठाने चाहिए।' ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि ये निर्देश दिल्ली ही नहीं सभी 122 शहरों में लागू करने होंगे। अगर उक्त कदम नहीं उठाए गए तो ट्रिब्यूनल सख्त कदम उठा सकता है।

लड़ाकू विमान सौदे के परीक्षण का समय कम करेगी वायुसेना

नई दिल्ली, एएनआइ : 114 बहुदेश्यीय लड़ाकू विमान निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के सौदे में वायुसेना सभी भागीदारों के लिए परीक्षण की समयसीमा कम करने की योजना बना रही है। नए लड़ाकू विमानों को बल में जल्दी शामिल करने के लिए परीक्षण की समयसीमा को एक साल से कम किया जाएगा।

पिछली बार जब वायुसेना ने 126 बहुदेश्यीय लड़ाकू विमानों के बंद किए जा चुके सौदे के लिए विभिन्न लड़ाकू विमानों का परीक्षण किया था तब ठेके की प्रक्रिया पूरी करने में 18 महीने लगे थे। बाद में जटिलताओं के कारण सौदा निरस्त किया गया, लेकिन कई साल तक रुकावट बनी रही थी।

रक्षा सूत्रों ने कहा, 'इस बार वायुसेना निविदा में एक साल से कम समय में भाग लेने वाले सभी भागीदारों के लिए परीक्षण एक साल से कम समय में करने की योजना बना रही है ताकि समय बचाया जा सके। असल में भागीदार फर्मों की अधिकांश प्रणाली और वैमानिकी की जांच की जा चुकी है। इससे परीक्षण में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।'

विमानों की गुणवत्ता और इसपर होने वाले खर्च के लिहाज से अभी तक के सबसे बड़े

प्रतीकात्मक फोटो

सौदे के लिए खरीद प्रस्ताव का रूस से सुखोई और मिग, अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, यूरोप से यूरोफाइटर कंसोर्टियम और स्वीडन से साब समूह ने जवाब दिया है। वायुसेना अगले कुछ महीनों में रणनीतिक साझेदारी नीति के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सौदे के लिए रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी ले सकती है। रणनीतिक साझेदारी नीति के तहत भारत में विमान निर्माण के लिए भारतीय फर्म को विदेशी साझेदार के साथ समझौता करना होगा।

वायुसेना में बेड़े की कमी के लिहाज से इस सौदे को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि वायुसेना मिग-21, मिग-23 और मिग-27 लड़ाकू विमानों को हटाना चाहती है।

रामलीला मैदान पर कल रैली में मोदी को निशाना बना सकते हैं आतंकी

नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर होने वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की योजना बनाई है। इस संबंध में खुफिया एजेंसियों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे स्पेशन प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) और दिल्ली पुलिस को अवगत करा दिया है। रैली का आयोजन भाजपा ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मसले पर किया है।

केंद्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा प्रबंध करते समय वे 'ब्लू बुक' में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। एजेंसियों का कहना है, उन्हें ताजा जानकारियां मिली हैं कि रामलीला मैदान पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों को भारत भेजा गया है क्योंकि रैली में जबर्दस्त भीड़ और मीडिया का भारी जमावड़ा होगा।

खुफिया एजेंसियों ने इस खतरे का कारण नागरिकता संशोधन कानून (12 दिसंबर), रामजन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (9 नवंबर), जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा (5 अगस्त) और पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर भारतीय सेना और वायुसेना के हमलों को बताया है।

राजस्थान के राज्यपाल ने पेश किया 100 दिन का लेखा-जोखा

जागरण संवाददाता, जयपुर

कलराज मिश्र। प्रेट्र

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को अपने 100 दिन के कार्यकाल का लेखा-जोखा मीडिया के समक्ष पेश किया । उन्होंने अब तक के कार्यकाल को सफल बताया। संविधान के दायरे में रहकर प्रदेशवासियों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देने के साथ ही उन्होंने अपनी आगामी कार्य योजना भी बताई ।

मिश्र ने बताया कि राज्यपाल का पद संभालते ही उन्होंने आदिवासी कल्याण पर विशेष जोर दिया । आदिवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनीं और निराकरण के लिए सरकार से कहा। प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही राज्यपाल कोष से मदद की। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिहाज से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा की दिशा में कई नई पहल की गई। विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई । विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज प्रतिदिन फहराने और महामहिम् शब्द का उच्चारण बंद कराने को लेकर निर्देश दिए गए। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और प्रशासनिक अनुशासन बनाने को लेकर रोडमैप तैयार करने की पहल की गई। प्रत्येक दो साल में पाठ्यक्रमों को रिवाईज करने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए ।

किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती : इस दौरान राज्यपाल मिश्र ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर हिंसा करना लोकतंत्र को ध्वस्त करने जैसा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक पारित करा कर कानून बनाया है । कानून बनने के बाद उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । किसी विषय पर यदि कठिनाई है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात कर सकती है । बातचीत से ही समाधान निकलता है। किसी को आग लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

धार्मिक स्वतंत्रता पर चीन और पाक अमेरिका की नजर में

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोपों के चलते चीन और पाकिस्तान को निगरानी सूची में बनाए रखा है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने की वाली गंभीर शिकायतों के आधार पर यह सूची बनाई है। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में धार्मिक स्वतंत्रता के पालन का विशेष स्थान है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 18 दिसंबर को जारी ताजा सूची में चीन और पाकिस्तान के साथ ही म्यांमार, इरीट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का नाम है। विदेश मंत्रालय ने इन देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। इन सभी देशों में धार्मिक गतिविधियों का संस्थागत रूप से दमन जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की अमेरिकी वचनबद्धता के चलते इन देशों की निगरानी जारी रहेगी।

अमेरिका का मानना है कि हर व्यक्ति को हर देश में अपनी मान्यताओं के साथ जीवन व्यतीत करने की स्थितियां हासिल हों। जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन इन स्थितियों के खिलाफ कार्य करेंगे, अमेरिका उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अग्रसर रहेगा।

मिली अनुमति

मंत्रालय ने ट्रेन के प्रॉपल्शन सिस्टम खरीद के टेंडर निकालने को कहा, जनवरी तक टेंडर जारी होने व मार्च से उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना

आइसीएफ में ही बनेंगे वंदे भारत के 45 नए रैक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक फोटो

पहली वंदे भारत के उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार के विवाद के बीच आखिरकार सरकार ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को वंदे भारत की 45 नए रैक्स के उत्पादन की अनुमति दे दी है। इसी के साथ अब इन नई ट्रेनों के प्रॉपल्शन सिस्टम खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि अगले महीने तक निविदाएं जारी हो जाएंगी और मार्च तक आइसीएफ में वंदे भारत की नई ट्रेन रैक्स का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा।

रेल मंत्रालय ने तीन महीने के इंतजार के बाद वंदे भारत को लेकर ये निर्णय लिया है। ऐसा पहली वंदे भारत उत्पादन में भ्रष्टाचार की शिकायतों की विजिलेंस जांच के कारण हुआ जिसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) के तत्कालीन अफसरों पर एक खास फर्म को अनुबंध देने के लिए टेंडर की शर्तों को तोड़ने-मरोड़ने और दूसरी कंपनियों की उपेक्षा करने के आरोप लगे थे। विजिलेंस जांच के परिणामस्वरूप आइसीएफ के तत्कालीन महाप्रबंधक समेत आठ अफसरों से जवाब तलब किया गया है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार विजिलेंस जांच के कारण वंदे भारत के नए ट्रेन सेट्स के उत्पादन में छह महीने का विलंब हो गया है। लेकिन इसके बावजूद सभी 45 रैक का उत्पादन समय सीमा के भीतर होगा, क्योंकि मंत्रालय ने 2021-22 की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब आइसीएफ के मौजूदा प्रबंधन को तेजी से काम करना होगा और टेंडर के साथ ही नए वेंडर या वेंडरों का चयन कर प्रॉपल्शन सिस्टम की समय पर आपूर्ति के साथ ट्रेन सेट्स का निर्माण शिड्यूल के मुताबिक करना होगा।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि वंदे भारत ट्रेन सेट्स का आयात नहीं होगा। बल्कि ये ट्रेनें देश में ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनेंगी। पहली वंदे भारत में कई खामियां थीं। सबसे बड़ी खामी इसका अधिक वजन था, जिसके कारण बिजली की खपत ज्यादा थी। इसके अलावा ऑटोमैटिक दरवाजों और ब्रेकिंग सिस्टम में भी दोष थे। ऐसा आरडीएसओ की मंजूरी के बगैर उपकरणों की खरीद के कारण हुआ था। परंतु अब ये खरीद आरडीएसओ द्वारा निर्धारित मानकों पर की जाएगी।

इससे पहले बोर्ड पर इस बात आरोप लगाए जा रहे थे कि वंदे भारत ट्रेनों के आयात की मंशा से ही आइसीएफ के पुराने अफसरों को वंदे भारत के अलावा ईएमयू व मेमू की खरीद के मामलों में भी फंसाया गया है। जबकि इन अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' के आह्वान पर भारत की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन का डेढ़ साल के भीतर निर्माण करने के लिए ही फालतू नियमों की अनदेखी की थी। यदि प्रतिभाशाली और परिश्रमी अफसरों के साथ ऐसा सलूक होगा तो भविष्य में कोई भी अफसर देश हित में जोखिम लेने का साहस नहीं करेगा।

कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज की

मुंबई, प्रेट्र : विशेष सीबीआइ कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वह 2012 के शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपित है।

मुखर्जी ने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश जेसी जागडाले की कोर्ट में करीब छह माह पहले स्वास्थ्य आधार पर जमानत अर्जी दायर की थी। उसने चौथी बार जमानत लेने का प्रयास किया।

जमानत पर दलील देते हुए इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने कहा, 'उसके स्वास्थ्य की दशा अत्यंत खराब है। लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि महिला की हालत वापसी की स्थिति में नहीं है, इसलिए इस खराब हो रही हालत से कुछ भी अनहोनी हो सकती है।'

सीबीआइ के वकील मनोज चालडान ने विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई सुबूत नहीं है कि उसका स्वास्थ्य गिर रहा है। पिछली बार नवंबर 2018 में जमानत अर्जी ठुकराए जाने के बाद से उसके स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

लोगों से कहो, मौसम संबंधी चेतावनियों के साथ हमारी चेतावनी पर भी ध्यान दें!

झारखंड में जनता का फैसला लॉक, 23 को खुलेगा पिटारा

अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब नजरें चुनाव परिणाम पर

संताल की 16 सीटों पर बंपर वोटिंग, 71.17 फीसद हुआ मतदान

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में शुक्रवार को पांचवें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब राज्य की सभी सीटों पर जनता का फैसला लॉक हो गया है और सभी की निगाहें 23 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिक गई हैं। पांच चरणों में हुए इस चुनाव में 1,215 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है।

अंतिम दौर में संताल प्रमंडल की सभी 16 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई। इस बार के चुनाव में सर्वाधिक मतदान का आंकड़ा भी इसी चरण की सीटों ने अपने नाम कर लिया। कुल 71.17 फीसद मतदान हुआ, जबकि नाला में सर्वाधिक 78.91 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं, दिव्यांग मतदाताओं ने 92.67 फीसद वोटिंग कर इस बार भी बाजी मारी। फिर भी यह पिछले चुनाव की तुलना में 2.14 फीसद कम है। 2014 के चुनाव में यहां 73.31 फीसद वोटिंग हुई थी। अंतिम दौर में 236 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इनमें 29 महिला तथा 75 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, मंत्री लुईस मरांडी, रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, प्रदीप यादव, सत्यानंद झा जैसे दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा जुड़ गई है।

चाक-चौबंद थी व्यवस्था : इस चरण में कुल 5,389 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ। इनमें 3,690 मतदान केंद्र या तो संवेदनशील या अतिसंवेदनशील थे। चुनाव आयोग ने चाक-चौबंद व्यवस्था की थी।

झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में शुक्रवार को जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ पर मतदान करने के लिए कतार में खड़ीं महिला मतदाता। जागरण

अंतिम समय में बदली गई 45 ईवीएम

मॉक पोल और मतदान शुरू होने के कारण कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की बातें भी सामने आईं। हालांकि समय पर या तो इन्हें ठीक कर लिया गया या बदल दिया गया। इस दौरान 45 बैलेट यूनिट, 42 कंट्रोल यूनिट तथा 120 वीवीपैट मशीनें बदली गईं।

इतने प्रत्याशियों के लिए पड़े वोट

चरण	कुल प्रत्याशी	महिला	निर्दलीय
पहला चरण (13 सीट)	189	15	60
दूसरा चरण (20 सीट)	260	29	73
तीसरा चरण (17 सीट)	309	32	99
चौथा चरण (15 सीट)	221	22	59
पांचवां चरण (16 सीट)	236	29	75
कुल (81 सीट)	1,215	127	366

त्रिशंकु विधानसभा के आसार

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में 81 सीटों के लिए हुए विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को मतदान का आखिरी चरण संपन्न हो गया। निजी टीवी न्यूज चैनल के एक्जिट पोल के सर्वे के अनुसार यहां त्रिशंकु विधानसभा के प्रबल आसार हैं। सर्वे के मुताबिक, राज्य में भाजपानीत गठबंधन सरकार को झटका लग सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार बन सकती है। इंडिया टुडे और एक्सिस माइ इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 22 से 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन को 38 से 50 सीटें तक मिल सकती हैं। एक्सिस माय इंडिया के अनुसार, जेवीएम को 2-4, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) को 3-5 और अन्य को 4-7 सीटें मिल सकती हैं। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।

आइएनएस-सी वोटर और एबीपी के सर्वे में भी भाजपा को झटका लगने का अनुमान है। इसमें त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा किया गया है। सर्वे के मुताबिक, भाजपा को 28 से 36 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, कांग्रेस, झामुमो और राजद गठबंधन भी बहुमत से दूर नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को 81 सदस्यीय विधानसभा में 31-39 सीटें मिलने का अनुमान है।

महासमर
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

एग्जिट पोल

इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया	आइएनएस-सी वोटर और एबीपी
भाजपा : 22 - 32 सीटें	भाजपा : 28 - 36
झामुमो, कांग्रेस और राजद : 38 -50	झामुमो, कांग्रेस, राजद : 31-39
आजसू : 3-5	आजसू : 3-05
अन्य : 4-7	झाविमो : 1-04

2014 में विधानसभा के नतीजे

2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 31.3 फीसद वोट के साथ 37 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। एजेएसयू 3.7 फीसद वोट के साथ 5 सीटें जीती थी। वहीं, जेएमएम 20.4 फीसद वोट के साथ 19 सीटें, कांग्रेस 10.5 फीसद वोट के साथ 6 सीटें और जेवीएम 10 फीसद वोट के साथ 8 सीटें जीती थीं। हालांकि चुनाव के बाद जेवीएम के 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। छह सीटें अन्य को मिली थीं।

हेमंत के भाई बंसत पर पैसे बांटने का आरोप, तीन गाड़ियां जब्त

जागरण संवाददाता, दलाही (दुमका) : झारखंड में दुमका जिले के मसलिया स्थित मसानजोर पंचायत के रंगामटिया गांव में गुरुवार देर रात ग्रामीणों ने झामुमो कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने झामुमो का स्टीकर लगी तीन गाड़ियों को जब्त कर लिया। हालांकि, देर शाम तक मामला दर्ज नहीं किया गया था।

गुरुवार रात को झामुमो के राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष बसंत सोरेन रांगामटिया गांव पहुंचे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंगामटिया गांव में उनको गाड़ी समेत रोक लिया। भाजपाइयों का कहना था कि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन वोटरों में रुपये बांटने के लिए आए थे। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में लिट्टी-चोखा का कार्यक्रम रखा था, उसमें बसंत को भी बुलाया गया था। भाजपा कार्यकर्ता के हंगामा करने पर वे बगैर खाए वहां से निकल गए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों ने बताया कि बसंत गांव के किसी घर में छुपे हैं। पुलिस ने कई घरों में तलाशी ली, लेकिन वे नहीं मिले। एसडीओ ने वाहन कब्जे में लेकर जवानों को देखरेख के लिए तैनात किया। भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी भी पहुंची। शुक्रवार को सुबह क्रेन की मदद से तीनों गाड़ियों को थाना लाया गया। गाड़ी के अंदर एक मोबाइल मिला है। एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई जाएगी।

महाराष्ट्र में 83 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाओं से लाभ नहीं

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं पर 83,496 करोड़ खर्च करने के बावजूद उनसे कोई लाभ नहीं मिला। शुक्रवार को राज्य विधानसभा में रखी गई 2017-18 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 198 परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ है और इनमें 67 परियोजनाएं तो 30 वर्षों में भी पूरी नहीं हुई हैं। इन परियोजनाओं पर 83,496 करोड़ खर्च किया जा चुका है, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद ये पूरी नहीं हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, काम में देरी से इसका लागत मूल्य बढ़ा। इसके अलावा लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। राज्य सरकार से लंबित परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

नोटबंदी के बावजूद महाराष्ट्र का राजस्व बढ़ा : कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के बावजूद महाराष्ट्र सरकार का राजस्व 2017-18 के वित्त वर्ष में बढ़ा। इसमें कहा गया है कि राज्य की आय (राजस्व प्राप्ति) में 19 फीसद की वृद्धि हुई है, जबकि कर संग्रह 23 फीसद बढ़ा है।

66 हजार करोड़ के उपयोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किए गए : कैग ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 31 मार्च, 2018 तक 66,000 करोड़ के उपयोग प्रमाणपत्र जमा नहीं किए। सरकार द्वारा प्रमाणपत्र जमा नहीं करने से सरकारी धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की आशंका है। हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि कब से यह प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया है।

सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- एसीबी ने कहा, पवार के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता
- राकांपा नेता के मंत्री रहते हुआ था 70 हजार करोड़ का सिंचाई घोटाला

महाराष्ट्र में संप्रग सरकार के कार्यकाल में हुए सिंचाई घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी है। ब्यूरो की तरफ से बांबे हाई कोर्ट को दिए शपथपत्र में कहा गया है कि राकांपा नेता अजीत पवार के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता।

19 दिसंबर को उच्च न्यायालय में एसीबी के महानिदेशक परमवीर सिंह की ओर से विदर्भ सिंचाई घोटाले में शपथपत्र देकर अजीत पवार को बेदाग बताया गया है। महाराष्ट्र में 70 हजार करोड़ रुपये का सिंचाई घोटाला 1999 से 2009 के बीच अजीत पवार के सिंचाई मंत्री रहते हुआ था। 2012 में एक सामाजिक संस्था जनमंच की ओर से उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें इस घोटाले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में जोर-शोर से उठाया था। तब भाजपा अध्यक्ष रहे देवेंद्र फड़नवीस ने सत्ता में आने पर अजीत पवार से जेल में चक्की पिसवाने का वादा किया था। अपनी सरकार आने के बाद फड़नवीस ने ही 12 दिसंबर, 2014 को इस मामले की जांच के आदेश भी दिए थे। मामला दर्ज होने के बाद एसीबी ने विशेष जांच दल (एसआइटी) बनाकर विदर्भ के नागपुर एवं अमरावती विभाग में जांच शुरू की थी। जनहित याचिका दायर करने वाली संस्था जनमंच ने एसीबी को सिंचाई घोटाले से संबंधित तमाम दस्तावेज दिए थे। इसके बावजूद जांच में तेजी नहीं आने पर इसने उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की। तब 18 फरवरी, 2016 को एसीबी के महानिदेशक ने एक शपथपत्र दायर कर हाई कोर्ट को 400 निविदाओं की जांच शुरू होने की जानकारी दी थी। 23 फरवरी, 2016 को एवं उसके बाद एसीबी ने कई निर्माण कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस एंड इंस्ट्रक्शन्स के नियम 10 (1) के अनुसार किसी विभाग के तहत होने वाले काम के लिए उस विभाग का मंत्री जवाबदेह होता है। जांच के दौरान जल संसाधन विभाग ने मई एवं जून 2019 में मामले से संबंधित तथ्य जांच एजेंसी को सौंपे थे। सितंबर 2019 में पवार को भी जांच एजेंसी ने 12 सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नावलियां भेजी थीं, जिसके जवाब उन्होंने दिए थे। एसीबी के महानिदेशक परमवीर सिंह का कहना है कि जांच अधिकारियों द्वारा 27 नवंबर, 2019 को दिए गए शपथपत्र का मैं समर्थन करता हूं। बता दें कि इसी दौरान पवार फड़नवीस की 81 घंटे वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। उस समय सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामले बंद करने की जानकारी उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को दी गई थी। तब भी राजनीतिक हलकों में ये आरोप उछले थे कि अजीत पवार ने भाजपा के साथ आकर खुद को बेदाग करवा लिया।

अजीत पवार फाइल

फड़नवीस ने की आलोचना

सिंचाई घोटाले में अजीत पवार को क्लीन चिट दिए जाने की भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने आलोचना की है। करीब एक माह पहले पवार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले फड़नवीस ने कहा है कि हम इस शपथपत्र को नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी इसे नहीं मानेगा। मंत्रियों को बचाकर अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसीबी के महानिदेशक ने 2018 में जो चीजें दी थीं, उनके खिलाफ कोई सुबूत या दस्तावेज नहीं दिया गया है।

मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से दूर रहे फड़नवीस

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र विस में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता विधानमंडल परिसर में मुख्यमंत्री के साथ पारंपरिक फोटोग्राफी से दूर रहे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने फोटोग्राफी कराई। महाविकास अघाड़ी का पहला शीतकालीन सत्र नागपुर में सोमवार से शुरू हुआ और शनिवार को इसका समापन हो जाएगा। पारंपरिक तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ पारंपरिक फोटो सत्र आयोजित किया था। हालांकि, फड़नवीस और उनके पूर्व मंत्रिमंडलीय सहयोगी एवं भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुंगनटिवार एवं गिरीश महाजन ने इसमें भाग नहीं लिया।

इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं, समय से पहले बजट सत्र की तैयारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- मार्च के बजाय फरवरी में होने वाला बजट सत्र चलेगा लंबा
- हरियाणा में पहली बार बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल

हरियाणा में इस साल विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं होगा। इसके उलट बजट सत्र को मार्च के बजाय फरवरी में बुलाने की तैयारी है। वित्त विभाग ने सभी महकमों से बजट अनुमान मांगे हैं। बजट सत्र की खासियत यह होगी कि पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। हालांकि, पड़ोसी राज्यों में ऐसा होता रहा है, लेकिन हरियाणा में यह अपनी तरह का पहला मामला होगा जब वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र लंबा चलेगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं।

मनोहर सरकार की दूसरी पारी में दो बार विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा चुका है। अक्टूबर में नई सरकार बनने के बाद पहले सत्र के दौरान विधायकों की शपथ ग्रहण तथा स्पीकर का चुनाव किया गया। इस सत्र के दौरान सरकार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। नवंबर में ही संविधान दिवस के अवसर पर फिर से विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें डिप्टी स्पीकर के चुनाव के साथ ही कई अहम बिल पास किए गए। नियमानुसार शीतकालीन सत्र को कम से कम तीन दिन चलाया जाता है। ऐसे में सरकार के सामने विधानसभा में पास करवाने के लिए कोई अहम बिल भी नहीं है। एक ही माह में दो सत्र होने का हवाला देकर विधानसभा सचिवालय शीतकालीन सत्र आयोजित करने से पीछे हट गया है। अलबत्ता मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र लंबा चल सकता है। बताया जाता है कि इस बार हरियाणा का बजट तय समय से पहले आ जाएगा। आमतौर पर हरियाणा का बजट सत्र पांच से 20 मार्च तक चलता है, लेकिन इस बार यह सत्र फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में बुलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क है कि मनोहर सरकार का पहला कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होने के कारण अनुमान से अधिक खर्चे हो चुके हैं।

विभागों द्वारा 31 मार्च से पहले-पहले नए बजट का सृजन करते हुए पूर्व में किए गए खर्चों की मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके लिए सत्र बुलाना जरूरी है। इसी दौरान वित्त विभाग द्वारा भी आगामी बजट के मद्देनजर सभी विभागों से बजट अनुमान मांग लिए गए हैं। हरियाणा में पिछला बजट एक लाख करोड़ के पार हो गया था। इस बार के बजट में वृद्धि होना भी लाजिमी है।

मनोहर लाल फाइल

एक लाख 79 हजार 462 करोड़ रुपये का कर्ज

मनोहर सरकार का पिछला बजट एक लाख 32 हजार 166 करोड़ का था। 12 हजार 22 करोड़ के घाटे के बजट में प्रदेश पर कुल कर्ज एक लाख 79 हजार 462 करोड़ रुपये दिखाया गया था।

उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर रायशुमारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह ने शुक्रवार को देहरादून में पार्टी नेताओं के मन की थाह ली। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के अलावा भाजपा के कोर ग्रुप के सदस्यों से मुलाकात कर रायशुमारी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं संग भी उन्होंने विमर्श किया।

भाजपा नेतृत्व ने संगठनात्मक चुनाव सर्वानुमति से कराने का निश्चय किया है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी सर्वसम्मति से होना है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन समेत अन्य समीकरणों के कारण अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसी कारण अध्यक्ष के चयन को पूर्व में तय की गई 15 दिसंबर की तिथि को आगे खिसकाना पड़ा। अब यह चुनाव 30 दिसंबर तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसे देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे और राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह के शुक्रवार के देहरादून दौरे को इसी का हिस्सा माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर भेंट की। सूत्रों के अनुसार, पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत कोर ग्रुप के साथ अध्यक्ष के चयन के मद्देनजर उनके मन की थाह ली। सूत्रों ने बताया कि यह दोनों नेता अब अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस पर मंथन के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक वरिष्ठ पार्टी नेता शिवराज सिंह चौहान और अर्जुनराम मेघवाल 22 से 25 दिसंबर के बीच देहरादून आ सकते हैं। वे ही नए अध्यक्ष के नाम का एलान करेंगे।

अस्तित्व में आई उत्तराखंड की जल नीति

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- राजभवन से स्वीकृति के शासन ने जारी उत्तराखंड राज्य जलनीति की अधिसूचना

19 साल के इंतजार के बाद उत्तराखंड की जल नीति अस्तित्व में आ गई है। राजभवन से स्वीकृति के बाद शासन ने जल नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। पारिस्थितिकी और विकास अभिज्ञता पर आधारित नीति में जल संरक्षण को पारंपरिक तौर-तरीकों को शामिल करने के साथ ही जलस्रोतों के पुनर्जीवीकरण पर खास फोकस किया गया है। भूजल के निरंतर गिरते स्तर को थामने के लिए उपभोग सीमा तय करने पर जोर दिया गया है तो कृषि के लिए सूक्ष्म सिंचाई पर।

सूखते जलस्रोतों ने सभी को बेचैन किया हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट ही बताती है कि राज्य में करीब तीन सौ जलस्रोत व छोटी नदियां सूख चुकी हैं। भूजल का भी अनियंत्रित दोहन हो रहा है। ऐसे में राज्य में दिक्कतें नजर आने लगी हैं। इस सबको देखते हुए लंबे इंतजार के बाद अब राज्य की जलनीति बनी है। पूर्व में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

नीति में जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन को ढांचा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। साथ ही सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, मलजल सफाई व पशुधन की जरूरतें, सिंचाई, जलविद्युत परियोनजाएं, पारिस्थितिकी, वनीकरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकीय पर्यटन, कृषि आधारित उद्योगों व अन्य उपयोग के लिए जल की उपलब्धता को नीति के केंद्र में रखा गया है। सचिव सिंचाई डॉ.भूपिंदर कौर औलख के अनुसार राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जलनीति अधिसूचित कर दी गई है।

यूडब्ल्यूआरएमआरसी का गठन

नीति के अनुसार उत्तराखंड जल संसाधन प्रबंधन एवं नियामक आयोग (यूडब्ल्यूआरएमआरसी) का राज्य में गठन होगा। तब तक पानी के उपयोग व भुगतान के संबंध में उप्र जलसंभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम के प्रविधानों के तहत प्रभार लगाने और वसूली का कार्य उत्तराखंड जल संस्थान करेगा।

जल नीति के मुख्य बिंदु

- जलस्रोत पुनर्जीर्वीकरण को पहल
- ग्रेविटी आधारित योजनाओं को बढ़ावा
- मीटर आधारित चौबीसों घंटे पानी
- भूजल का नियंत्रित दोहन
- अवैध रूप पंपिंग पर कार्रवाई
- नहरों का आधुनिकीकरण
- जल भंडारण को उपाय
- कृषि को ड्रिप सिंचाई
- उद्योगों से दूषित जल का शोधन
- संवेदनशील स्थलों का चिह्नीकरण
- पेयजल की गुणवत्ता पर फोकस
- वर्षा जल संरक्षण को उपाय
- पानी के उपयोग का लेखा-जोखा

धान पर केंद्र की सहमति से संतुष्ट नहीं छग सरकार

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार की सहमति पर सवाल खड़ा किया है। केंद्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दे दी है, लेकिन राज्य सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। सरकार की मांग है कि केंद्र 32 लाख मीट्रिक टन चावल ले, ताकि धान खरीद का आर्थिक बोझ राज्य पर न पड़े।

वन मंत्री मुहम्मद अकबर ने शुक्रवार को राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हम अब भी केंद्र सरकार से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की मांग करेंगे। धान खरीदी से राज्य सरकार को कोई आर्थिक फायदा नहीं होता है। राज्य सरकार केंद्र के एजेंट के रूप में धान की खरीद करती है। अकबर ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस के दबाव में आकर चावल लेने का फैसला किया है। कांग्रेस ने लाखों किसानों के पत्र को राज्यपाल को सौंपा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री ने पीएमओ से लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की और खरीदी करने का दबाव बनाया।

सेंट्रल पूल का चावल लेकर केंद्र ने दिखाई संवेदनशीलता: सोनी : रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में चावल खरीदने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। प्रदेश सरकार अब इसमें भी मीन-मेख निकालने की अपनी दुराग्रही प्रवृत्ति का परिचय देकर किसानों के साथ छलावा करने की नीयत जता रही है।

यह है चावल का गणित : सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। कस्टम मिलिंग के बाद इससे 57.37 लाख मीट्रिक टन चावल तैयार होगा। राज्य के पीडीएस के लिए 25 लाख 40 हजार मीट्रिक टन रखा जाएगा। केंद्र ने 24 लाख मीट्रिक टन लेने की मंजूरी दे दी है। अब केवल सात लाख मीट्रिक टन चावल शेष बचेगा।

विरोध

बठिंडा में जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव में जमकर हुआ हंगामा, विरोध में धरने पर बैठे कांग्रेसी, बिना वोटिंग हाथ खड़े कर करवाया गया चुनाव, अनियमितता का आरोप

पंजाब में कांग्रेसियों का अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना

जागरण संवाददाता, बठिंडा

पंजाब के बठिंडा में कांग्रेसियों ने शुक्रवार को जिला परिषद के चेरयमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव में धांधली व मनमानी का आरोप लगाकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के ग्रुप की महिला मनजीत कौर को चेयरपर्सन लगाया गया और बार एसोसिएशन बठिंडा के पूर्व प्रधान गुरइकबाल सिंह चहल को वाइस चेयरमैन लगाया गया। आरोप है कि यह चुनाव बिना वोटिंग के हाथ उठाकर हुआ।

चुनाव के बाद अनियमितता का आरोप लगाकर भुच्चो मंडी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक प्रीतम कोटभाई व हल्का देहाती कांग्रेस के प्रधान हरविंदर लाडी के ग्रुप के सदस्यों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध जताया। पहले तो उन्होंने बिना वोटिंग के चुनाव करवाने पर मीटिंग हाल में नारेबाजी की और बाद में मेन रोड पर धरना दिया। चुनाव के दौरान सुरक्षा की कमान संभाले एसएसपी डॉ. नानक सिंह ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर गाड़ियों में बैठा दिया और थाना थर्मल व सिविल लाइन में भेजा गया।

मंत्री कांगड़ पर पैसे लेने व पुलिस से मिलीभगत का आरोप : विरोधी गुट के जिला परिषद के मेंबरों सुखपाल कौर, रामपाल कौर बंगी रुलदू जोन व गुरदीप सिंह बलाहड़ विंझू जोन के अलावा ब्लॉक समिति मौड़ की चेयरपर्सन चरनजीत कौर, ब्लॉक समिति संगत की चेयरपर्सन जीत कौर, ब्लॉक समिति बठिंडा की चेयरपर्सन दलजीत कौर व ब्लॉक समिति गोनियाना के चेयरमैन लखविंदर लक्खा ने बठिंडा प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता कर कांग्रेस के मंत्री कांगड़ पर मनमानी करने के आरोप लगा इस्तीफे देने का एलान कर दिया। इन्होंने प्रशासन व पुलिस अधिकारियों पर भी मंत्री के साथ मिले होने के आरोप लगाया। लाडी ग्रुप की मेंबर सुखपाल कौर के बेटे गांव बुलाढेवाला के पूर्व सरपंच मनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उनके एक जिला परिषद के मेंबर तेज सिंह को तीन दिन से अगवा किया हुआ है। वहीं, कई मेंबरों के घर पर पुलिस भी भेजी गई। यहां तक कि उनको आने भी नहीं दिया जा रहा था।

बेबुनियाद हैं आरोप : **कांगड़** : राजस्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने कहा कि चुनाव पारदर्शी ढंग से हुआ है। उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सभी बेबुनियाद हैं। चुनाव प्रक्रिया सभी की सहमति से हुई है। इसके लिए सीनियर जूनियर को भी देखा जाता है। जहां तक कि पैसे लेने का सवाल है, तो यह झूठ है। यह लोग भी कांग्रेसी हैं। इनको चाहिए कि वह पार्टी के साथ चलें।

बठिंडा में जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव के बाद भड़के कांग्रेसी मेन रोड पर धरना देने बैठ गए। जागरण

रोजवैली घोटाला : कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त से पूछताछ

जागरण संवाददाता, कोलकाता

रोजवैली चिटफंड घोटाला मामले में शुक्रवार को सीबीआइ ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती को तलब कर घंटेभर पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे पूर्व आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती साल्टलेक के सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित सीबीआइ कार्यालय पहुंचे। जांच अधिकारियों ने उनसे करीब एक घंटे तक पूछताछ की। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार, रोजवैली चिटफंड घोटाले का मामला सामने आने के बाद वर्ष 2010 में सेबी ने कोलकाता पुलिस को एक पत्र भेजा था। उस वक्त गौतम मोहन कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे। उक्त पत्र में सेबी ने पुलिस को क्या जानकारी दी थी यह जानने के लिए गौतम मोहन से पूछताछ की गई। इसके अलावा सीबीआइ ने पुलिस आयुक्त रहते वक्त उन्होंने रोजवैली घोटाले में क्या कार्रवाई की थी? रोजवैली के मुखिया गौतम कुंडू से पूछताछ की थी या नहीं? उन्होंने घोटाले की जांच करने के आदेश दिए थे की नहीं? समेत अन्य सवालों के जवाब उनसे मांगे गए।

उधर, सीबीआइ कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पूर्व पुलिस आयुक्त गौतम मोहन चक्रवर्ती ने सीबीआइ जांच को लेकर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। हालांकि, उन्होंने बताया कि वे सीबीआइ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने सीबीआइ को बताया कि मार्च 2011 तक पुलिस कमिश्नर रहने के दौरान चिटफंड घोटाले में कोई एफआइआर दर्ज नहीं हुई थी, जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उधर, फिर से रोजवैली घोटाले की जांच में तेजी ने आरोपित नेताओं और पुलिस अफसरों की धड़कनें बढ़ा दी है।

600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन का आयोजन सिविल सोसायटी के सदस्यों ने किया था।

नागरिकता के सुबूत के लिए नहीं किया जाएगा परेशान : गृह मंत्रालय

आश्वासन ▶ स्थानीय गवाह या समुदाय द्वारा दिए प्रमाण-पत्र को भी माना जाएगा साक्ष्य

सवाल जवाब के रूप में पर्चे बांटकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश

नीलू रंजन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं के बीच गृह मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि किसी को भी नागरिकता साबित करने के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि एनआरसी के दौरान किसी को अपने पिता या दादा का 1971 के पहले के जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गरीब व अशिक्षित लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्थानीय गवाह और समुदाय की ओर से दिए गए सुबूतों को भी स्वीकार किया जाएगा।

दरअसल, सीएए और एनसीआर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लोगों को यह कहकर उकसाया जा रहा है कि एनसीआर लागू होने के बाद उन्हें 1971 के पहले के अपने पिता या दादा का जन्म प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज देने के लिए कहा

गृह मंत्रालय का दफ्तर। फाइल

जाएगा। दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में उन्हें देश छोड़ना होगा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अभी एनसीआर के नियम ही नहीं बने हैं। लेकिन यह साफ है कि इसके लिए दस्तावेज देने के नियम कड़े नहीं होंगे, बल्कि कई प्रकार के दस्तावेजों में किसी एक के होने पर भी उन्हें नागरिक माना जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार भी विज्ञापन के जरिये जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं सवाल-जवाब के रूप में संभवतः भाजपा की ओर से पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। इसमें कहा गया है, 'अपना स्वार्थ साधने वालों के बहकावे में न आकर खुद पढ़ें, समझें और फिर इस मामले में विवेक से अपनी समझ बनाएं।' लगभग एक दर्जन सवाल जवाब में सबसे पहले यही बताया गया है कि नागरिकता कानून और एनआरसी अलग-अलग है। नागरिकता कानून संसद की मंजूरी के बाद लागू हो चुका है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एनआरसी असम में लागू किया गया है। पूरे देश के लिए एनआरसी की घोषणा अभी नहीं हुई है और उसके लिए नियम प्रक्रिया तय होने बाकी हैं। कई सवाल हैं जैसे- क्या एनआरसी से भारतीय मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत है? क्या इसे धार्मिक आधार पर लागू किया जाएगा? क्या ऐसे सुबूत मांगे जाएंगे जिसे जुटाना मुश्किल होगा? अगर कोई दस्तावेज न हो तो नागरिकता कैसे प्रमाणित की जाएगी आदि। पर्चे में क्रमवार समझाया गया है कि इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और यह एक रजिस्टर जैसा होगा जिसमें हर किसी को नाम दर्ज कराना होगा। आधार का उदाहरण देते हुए बताया गया कि जैसे उसमें रजिस्टर के लिए नाम पता, जन्मतिथि आदि के कुछ प्रमाण देने होते हैं, एनआरसी भी वैसी ही प्रक्रिया होगी। इसके लिए माता-पिता से जुड़े दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में यह भी बताया गया है कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं हुआ तो गवाह की भी इजाजत दी जा सकती है। कम्युनिटी वेरिफिकेशन का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके पास वोटर कार्ड हैं। ऐसे किसी भी मामले की पहचान ही काफी होगी। इसी संदर्भ में यह भी बताया गया है कि असम में हुई परेशानी और 19 लाख लोगों को बाहर होने को उदाहरण न मानें। असम घुसपैठ से प्रभावित राज्य रहा है। वहां छह साल तक आंदोलन चला और फिर राजीव गांधी के काल में एक समझौता हुआ। इसके आधार पर 1971 को कटऑफ ईयर मानकर नागरिकता तय करने की बात हुई थी। उसे पूरे देश के लिए उदाहरण मानकर घबराने की जरूरत नहीं है।

पूरे देश में लागू नागरिकता कानून के अनुसार 1987 के पहले भारत में जन्मे सभी लोग यहां के नागरिक हैं। जिन लोगों के माता-पिता का जन्म भारत में 1987 के पहले हुआ है, वे भी स्वाभाविक नागरिक माने जाएंगे। 2004 के पहले जन्मे लोगों में यदि माता-पिता में कोई एक भारत का नागरिक हुआ, वे भी देश के स्वाभाविक नागरिक हैं। जाहिर है सीएए और एनसीआर से देश के किसी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है।

सीएए लागू करने में राज्यों ने नहीं किया सहयोग तो केंद्रीय एजेंसियों को दी जा सकती है जिम्मेदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **नागरिकता संशोधन कानून में केंद्र को किसी भी एजेंसी से लागू कराने का दिया गया है अधिकार**
- **फिलहाल राज्यों के जिलाधिकारियों के पास होती है नागरिकता से जुड़े मामलों की शक्ति**

पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से भले ही मना कर दिया हो, लेकिन केंद्र सरकार उनके सहयोग के बगैर भी इसे लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए पिछले हफ्ते संसद से पारित संशोधित कानून में ही प्रावधान कर दिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करवाने वाली एजेंसी का चयन कर सकती है। अभी तक नागरिकता से जुड़े मामलों को लागू करने की शक्ति जिलाधिकारी के पास होती है, जो राज्य सरकार के अधीन काम करता है।

विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों के नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से इन्कार के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों के पास इसका अधिकार है ही नहीं। उनके अनुसार नागरिकता के मामले में पूरा अधिकार केंद्र के पास होता है और जमीनी स्तर पर इसके देखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिलाधिकारी को शक्ति दे दी जाती थी। यानी इस मामले में जिलाधिकारी केंद्र सरकार की तरफ से काम करता है। उन्होंने साफ किया कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो इस शक्ति को किसी अन्य पदाधिकारी को दे सकती है।

दरअसल केंद्र सरकार को सीएए को लागू करने में कई राज्य सरकारों के असहयोग की आशंका पहले से थी। यही कारण है कि संशोधन में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार अपने अनुसार किसी एजेंसी को शक्ति प्रदान कर सकती है। वैसे तो गृह मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि इस संबंध में राज्यों से बात की जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि राज्य सरकारें इसे लागू करने से रोकने की स्थिति में नहीं होंगी।

फिलहाल गृह मंत्रालय सीएए को लागू करने के लिए नियम बनाने की तैयारी में जुटा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियम का एक ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, जिस पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस दौरान यदि कोई सुझाव देना चाहे तो उस पर भी विचार किया जाएगा। एक बार नियम तैयार होने और उन्हें अधिसूचित करने के बाद ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो सकेगा। इन शरणार्थियों को पहले ऑनलाइन आवेदन करने और दस्तावेज जमा करने की सुविधा दी जाएगी। बाद में घर-घर जाकर उनका सत्यापन भी किया जाएगा।

सोनिया गांधी का वार, लोकतांत्रिक आवाज को कुचल रही सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सीएए-एनआरसी पर लोगों की चिंता जायज**

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों और छात्रों के आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार असहमति की आवाज को बर्बरता से कुचलने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। सोनिया ने सीएए के खिलाफ छात्रों और नागरिकों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन का एलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है।

सीएए के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आती खबरों के बीच सोनिया गांधी ने देश के नाम एक विशेष संदेश जारी कर इस पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में छात्रों युवाओं और नागरिकों के खिलाफ भाजपा सरकार के क्रूर दमन पर अपनी गहरी पीड़ा और चिंता व्यक्त करती है। भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थानों में स्वाभाविक तरीके से विरोध

सोनिया गांधी। फाइल

प्रदर्शन हुए हैं। लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसी तरह सरकार का भी कर्तव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओं को दूर करे, लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपा सरकार ने लोगों की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। यही नहीं, उनकी असहमति की आवाज को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र में यह कतई स्वीकार्य नहीं है। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की हरकतों की पुरजोर निंदा करती है और न्याय की लड़ाई में भारतीय नागरिकों व अपने छात्रों के साथ एकजुट होकर खड़ी है।

सीएए को लेकर लोगों में पनपे खौफ और चिंता को सोनिया गांधी ने सही ठहराया। उन्होंनें कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभाव पूर्ण है। इसकी वजह से नोटबंदी की तरह एक बार फिर एक एक व्यक्ति को अपने और अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने सीएए को गरीबों और समाज के वंचित तबकों के लिए भी अनुचित ठहराने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लोगों की इसको लेकर आशंकाएं सही और जायज हैं। कांग्रेस की ओर से उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पार्टी उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े होने और संविधान के बुनियादी मूल्यों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

नागरिकता संशोधन कानून का उग्र विरोध...

गोरखपुर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। शहर के नखास चौक पर पुलिस पर पथराव करते उपद्रवी। जागरण

कर्नाटक के मंत्री रवि बोले- बहुसंख्यकों के धैर्य की परीक्षा न लें, गोधरा याद करें

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने नागरिकता संशोधन कानून पर जारी विरोध-प्रदर्शनों पर कहा कि बहुसंख्यकों के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता यूटी खादर को चेतावनी देते हुए कहा, 'याद करो गोधरा में क्या हुआ था।'शुक्रवार को रवि को एक वायरल वीडियो में कन्नड़ भाषा में बोलते देखा गया कि, 'यह उनका दिमागी फितूर था कि गोधरा में उन्होंने एक ट्रेन जला दी। यह उनका दिमागी फितूर ही था कि उन्होंने कारसेवकों को जिंदा जला दिया। लेकिन जब प्रतिक्रिया की बात आती है तो हम सबको पता है कि गोधरा के बाद क्या हुआ था।' उन्होंने खादर का आह्वान करते हुए गोधरा प्रकरण को याद करने को कहा। रवि ने मंगलुरु के मौजूदा हालात की तुलना गोधरा से की। ध्यान रहे कि विगत गुरुवार की रात को नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे दो प्रदर्शनकारी पुलिस फायरिंग में मारे गए थे।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि यह सीटी रवि का सबसे भड़काऊ भाषण है। पुलिस को तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उन्हें एहतियातन हिरासत में रखना चाहिए।

यूएन के बयान से पलटीं ममता, ईरानी-जावडेकर ने किया हमला

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- **संयुक्त राष्ट्र का उदाहरण दे स्वतंत्र संस्था से जनमत कराने की बात कही : बनर्जी**
- **संसद का अपमान है ममता बनर्जी का जनमत संग्रह वाला बयान : स्मृति**
- **सीएए पर जनमत संग्रह के सुझाव के लिए माफी मांगें ममता : जावडेकर**

सीएए-एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की निगरानी में जनमत संग्रह कराने वाले बयान पर शुक्रवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना रूख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने स्वतंत्र संस्था के जरिये जनमत कराने की बात कही थी। इसका उदाहरण देते हुए मैंने संयुक्त राष्ट्र का उल्लेख किया था, क्योंकि मैं चाहती हूं कि निरपेक्ष विशेषज्ञों की देखरेख में जनमत हो। उधर, ममता के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावडेकर ने उन पर हमला बोल दिया है। ईरानी ने बयान को संसद का अपमान करार दिया है तो जावडेकर ने कहा कि ममता को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

गौरतलब है कि गुरुवार को सीएए-एनआरसी के खिलाफ तृणमूल की युवा व छात्र इकाई की ओर से कोलकाता में आयोजित सभा के मंच से बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि 'पूरे देश में जनमत संग्रह हो। आप (पीएम मोदी) नहीं करेंगे। तृणमूल के भी रहने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रतिनिधि रहेंगे। उन्हें लेकर कमेटी गठित की जाए। हम भी यह देखना चाहते हैं कि आखिर सीएए-एनआरसी कितने लोगों को मंजूर है। हार गए

विदेशी पंच बुलाने की बात घटिया : विश्वास

ममता बनर्जी के बयान पर जाने-माने कवि कुमार विश्वास ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सवाल किया कि भारत के आंतरिक मामले में यूएन? विश्वास ने ट्वीट करके कहा कि राजनीतिक विरोध-विद्वेष सब ठीक है दीदी, जमकर करिए, जोरदार तरीके से करिए, सब साथ आएंगे, पर देश के आंतरिक मतभेद में विदेशी पंच बुलाने की बात बेहद घटिया और खेदजनक है। उन्होंने आगे कहा कि यहीं लड़िए, जीतिए, कानून बनाइए, बदलिए, बाकी यूएन या किसी भी विदेशी पंच की ऐसी की तैसी।

तो इस्तीफा देना होगा, मंजूर है?'

जिद छोड़ राजधर्म का पालन करें पीएम : ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएए और एनआरसी को वापस लेने और राजधर्म पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देशभर में कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जिद छोड़कर जिम्मेदारी लेनी होगी। पूरा देश जल रहा है। आग को बुझाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते तो राजधर्म की याद दिलाते।

...तो मोदी ने क्यों नहीं डाला वोट: ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन कानून इतना ही अच्छा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने इसके लिए संसद में वोट क्यों नहीं डाला?

आप (पीएम) दो दिन संसद नहीं आए। जब आपने वोट नहीं डाला तो मुझे लगा कि आप भी इस कानून के पक्ष में नहीं हैं। आप इस कानून को खारिज कर दीजिए।

23 दिसंबर से एक जनवरी तक आंदोलन की घोषणा: ममता बनर्जी ने राज्यव्यापी जुलूस और सभाएं करने के साथ आंदोलन को और अधिक धारदार बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस एक जनवरी को 'नागरिक दिवस' के रूप में मनाने की बात कही है।

कोलकाता में स्मृति ने साधा निशाना: यूएन वाले बयान को लेकर केंद्रीय कपड़ा एवं महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी की निंदा की। उन्होंने कहा कि ममता का यह बयान संसद का अपमान है। स्मृति ईरानी शुक्रवार को कोलकाता एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंची थी।

ममता पाक की भाषा बोल रही : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की बात कहकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिर गई हैं। विपक्ष के हर दल ने जहां चुप्पी साधकर उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है, वहीं भाजपा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने उनसे देश से माफी मांगने की बात कही तो भाजपा महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह देश के हित को भी क्षति पहुंचाकर भी सत्ता में बनी रहना चाहती हैं।

गौरतलब है कि ममता ने गुरुवार को एक रैली में कहा था कि सीएए पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह होना चाहिए। एक तरह से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर देने की बात कही थी। यह बयान कितना घातक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस और वाम समेत किसी भी दल ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। दरअसल उन्हें डर है कि ममता के बयान पर प्रतिक्रिया शुरू हुई तो विपक्ष का आंदोलन ध्वस्त हो सकता है। जबकि ममता की आलोचना करने से विपक्षी एकजुटता ध्वस्त होगी। बहरहाल, जावडेकर ने कहा-'यह तो देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। संयुक्त राष्ट्र भारत के मामलों में झांकने वाला कौन होता है। ममता को माफी मांगनी चाहिए।' वहीं विजयवर्गीय ने कहा, 'ममता सस्ती राजनीति करती रही हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि उनके बयान के क्या अर्थ हैं और पाक जैसे देश उनके बयान का कैसे तरह फायदा उठाने की कोशिश करेगा। राजनीतिक स्वार्थ में उन्हें देश हित भी नहीं दिखता।'

हाई कोर्ट का अपमान करने वाले वकीलों के खिलाफ याचिका

जासं, नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया में हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अन्य कई अधिवक्ताओं ने अवमानना की कार्रवाई की मांग की। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वह मामले को इससे जुड़ी कमेटी के समक्ष भेजेंगे, जो उचित कार्रवाई करेगी।

इस मामले में दायर छह याचिकाओं पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। मुख्य पीठ ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया तो याचिकाकर्ताओं के कुछ वकीलों ने मुख्य पीठ के समक्ष शेम-शेम के नारे लगाए थे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी इसकी निंदा की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्टैंडिंग काउंसल अनिल सोनी, रिपुदमन सिंह भारद्वाज, अजय दिगपॉल, विवेक गोयल, अरुण भारद्वाज, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के नेता अभिजीत व वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन शर्मा ने मुख्य पीठ से कहा कि अदालत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का अदालत को संज्ञान लेना चाहिए।

दो टूक

भारतीय रोड कांग्रेस के आयोजन से लौटने के क्रम में एक पंक्ति में दी अपनी प्रतिक्रिया, पार्टी के भीतर कुछ नेता एनआरसी पर मुख्यमंत्री से वक्तव्य का अनुरोध कर रहे थे

नीतीश बोले- बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) पर एक पंक्ति की सधी हुई प्रतिक्रिया दी कि बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी। मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया से यह साफ हो गया है कि जदयू एनआरसी को समर्थन नहीं देने के अपने पुराने स्टैंड पर कायम है।

मुख्यमंत्री भारतीय रोड कांग्रेस के 80 वें अधिवेशन में शामिल होने राजधानी स्थित बापू सभागार पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, तभी मीडिया ने उनसे एनआरसी के मसले पर हो रहे हंगामे पर सवाल किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यहां कहां से लागू होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री निकल गए।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर जदयू ने संसद के दोनों सदनों में सरकार को अपना समर्थन दिया था। जबकि जदयू नेता प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से ट्वीट कर सीएए के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस पर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी के दिग्गजों से ही कड़ी नसीहत मिली

नीतीश कुमार। फाइल

थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री से भेंट की थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लौटने के क्रम में प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं। इस पर जदयू नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से एनआरसी के बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिए।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गया में अपनी सभा में यह कहा था कि उनके रहते अल्पसंख्यकों के हित की अनदेखी नहीं हो सकती। अल्पसंख्यकों के बीच कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं।

लोगों का भ्रम दूर करने में विफल रही सरकार : लोजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर केंद्र सरकार से दूरी बनाते हुए संकेत दिए कि वह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध कर सकती है। लोजपा ने कहा कि देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से साफ है कि केंद्र सरकार सीएए पर समाज के एक बड़े वर्ग का भ्रम दूर करने में विफल रही है।

संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाली लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सीएए को एनआरसी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लिखा एक पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने विवादित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए राजग की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। चिराग ने कहा, 'लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बावजूद कानून को लेकर लोगों में असंतोष जारी है। लोजपा ने सरकार से घटक दलों के बीच विचार-विमर्श का अनुरोध किया था ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।' उन्होंने ट्वीट में मुस्लिमों और दलितों के अलावा समाज के अन्य वंचित वर्गों को आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी एनआरसी पर उनकी चिंताओं पर पूरा ध्यान देगी। चिराग ने कहा, 'लोजपा ऐसे किसी भी विधेयक का समर्थन नहीं करेगी जो आम आदमी के हित में न हो।' लोजपा अध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया कि वह प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके एनआरसी पर उनकी चिंताओं का निराकरण करे। ऐसा करना सरकार की जिम्मेदारी भी है। चिराग ने बताया कि उनकी पार्टी ने देश के हालात पर विचार-विमर्श किया है और गृह मंत्रालय को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर भाजपा ने अपना ट्वीट हटाया

नई दिल्ली, आइएएनएस : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशभर में चल रहे आंदोलनों के बीच भाजपा ने अपना एक पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया है। चार नवंबर के इस ट्वीट में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान था कि हम पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करेंगे। बौद्ध, हिंदू और सिख को छोड़कर एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। उग्र होते आंदोलनों के बीच सरकार कह रही है कि सीएए और एनआरसी के बीच कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ कई लोग इस ट्वीट को विरोध प्रदर्शन का कारण मानते हैं।

कई राजनीतिज्ञ भी इस ट्वीट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे थे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पांच दिन पहले ट्वीट किया, 'अमित शाह ने बंगाल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीएए और नागरिक रजिस्टर साथ-साथ चलेगा। कालक्रम के अनुसार, पहले शरणार्थियों के लिए नागरिकता कानून और फिर घुसपैठियों के लिए नागरिक रजिस्टर। भाजपा नेताओं ने कहा है कि जो लोग अंतिम एनआरसी से बाहर रह जाएंगे, उनके पास मताधिकार नहीं रहेगा।' दूसरी तरफ, गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एनआरसी को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है।

परेश रावल ने किया प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन

मुंबई, आइएएनएस : अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने परेश रावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है और उनकी तुलना सरदार पटेल से की है। उन्होंने ट्वीट किया कि सरदार पटेल ने देश का एकीकरण किया था और मोदी इसका विभाजन नहीं होने देंगे। उल्लेखनीय है कि फरहान अख्तर और अनुराग कश्यप जैसे बॉलीवुड हस्तियों ने सीएए का विरोध किया है।

जामा मस्जिद के आगे दिनभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, की नारेबाजी

विरोध ▶ जुमे की नमाज के बाद दोपहर एक बजे से जुटने लगे थे लोग

पुलिस ने कर रखे थे पुख्ता इंतजाम, दो ड्रोन पूरे दिन नजर रखे रहे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में जामा मस्जिद के गेट नंबर एक पर दिनभर प्रदर्शनकारी डटे रहे। इस बीच हजारों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कुछ लोगों ने अर्द्धनग्न होकर भी विरोध दर्ज कराया। दोपहर से शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। इस बीच दिल्ली पुलिस के दो ड्रोन पूरे दिन प्रदर्शनकारियों पर नजर रखे रहे।

हालात को देखते हुए जामा मस्जिद क्षेत्र में शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया था। यहां पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई थी और किसी तरह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध था। इसके बाद भी जुमे की नमाज के बाद दोपहर एक बजे से लोगों ने जामा मस्जिद के गेट नंबर एक स्थित सीढ़ियों पर जुटना शुरू कर दिया। यह लोग पहले से ही अपने साथ तिरंगा, पोस्टर व बैनर को लेकर पहुंचे थे। नमाज पढ़ने के बाद नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। देखते ही देखते मस्जिद परिसर के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग जुट गए थे। एहतियातन पुलिस ने दरियागंज चौक समेत जामा मस्जिद क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का इतंजाम किए हुए थे।

दिल्ली गेट पर पुलिस पर पथराव, कार फूंकी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली गेट पर किया जा रहा प्रदर्शन शाम होते-होते हिंसक हो गया। शाम की नमाज के बाद सकारात्मक भूमिका निभाते हुए स्थानीय मस्जिद से शांति की अपील करते हुए लोगों से प्रदर्शन खत्म कर घर जाने को कहा गया। शाम साढ़े पांच बजे तक ज्यादातर लोग घटना स्थल से वापस जा भी चुके थे। इसी बीच छह बजे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और दरियागंज थाने के सामने खड़ी पुलिस की एक कार में आग लगा दी। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें खदेड़ा।

पुलिस अधिकारियों ने आगजनी की इस घटना में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपित यमुनापार के रहने वाले हैं। उन्होंने भीड़ का हिस्सा बन शांत माहौल को बिगाड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने दोपहर की नमाज के बाद जामा मस्जिद इलाके से जंतर-मंतर तक मार्च किए जाने का आह्वान किया था। इसके तहत दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी। जामा मस्जिद इलाके में जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं, मार्च जंतर-मंतर तक न पहुंचे इसके लिए दिल्ली गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। दोपहर करीब 1.30 बजे प्रदर्शनकारी जामा मस्जिद से जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए। लेकिन पुलिस ने सर्तकता बरते हुए उन्हें दिल्ली गेट पर रोक लिया था।

यहां पर जमे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा झंडा लिए नागरिकता संशोधन कानून वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। उन्होंने रिजेक्ट सीएए और एनआरसी, जान देने को तैयार, लेकिन नहीं लागू होने देंगे कानून इत्यादि लिखे नारों की तख्तियां ले रखी थीं। दोपहर बाद तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन शाम को हिंसा भड़क गई।

नई दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जुटे लोग। ध्रुव कुमार

कई बार तनावपूर्ण हुई स्थिति

जामा मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी दिनभर नारेबाजी करते रहे। ऐसे में दिन में कई बार ऐसी स्थिति हुई जब भीड़ आक्रामक हो गई थी और हालात तनावपूर्ण बन गए। लेकिन, विभिन्न संगठनों व स्थानीय नेताओं द्वारा भीड़ को शांत कर वहीं बैठाया जा रहा था।

अजान से किया शांति पूर्ण प्रदर्शन का आह्वान

शाम चार बजे नमाज पढ़ने के बाद जामा मस्जिद के लाउडस्पीकर से भी प्रदर्शनकारियों के लिए दुआ मांगी गई। इसके साथ ही शांति पूर्ण प्रदर्शन के जरिये इसे सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस बीच कई सामाजिक संस्थाओं ने बिस्कुट, केला व पानी की बोतलों का वितरण किया।

इलाके में दिखी दहशत

प्रदर्शन को देखते हुए जामा मस्जिद क्षेत्र के साथ आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल रहा। यही कारण था कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी मुनासिब नहीं समझा। प्रदर्शन को देखते हुए कुछ लोग स्कूलों से बच्चों को छुट्टी से पहले ही ले गए थे।

गुजरात और तमिलनाडु में सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज

अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात और तमिलनाडु में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के नाम पर उपद्रव करने वाले सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गुजरात पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और दंगा करने के मामले में 3022 पर लोगों पर एफआइआर दर्ज की है। तमिलनाडु में भी 600 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।

गुरुवार को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई अन्य राज्यों में भी सीएए के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और छिटपुट हिंसा हुई, लेकिन कहीं से बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई। वडोदरा में मस्जिद के बाहर एहतियातन वीडियोग्राफी कर रहे पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस बीच हिंसा में घायल हुए एक पुलिसकर्मी की फोटो ट्विटर पर खूब वायरल हुई। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मुंबई में हरी मस्जिद के बाद हजारों लोगों की भीड़ ने प्रदर्शन किया। बीड और परभनी इलाकों में पत्थरबाजी में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए। भिवंडी एवं ठाणे में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। पुणे में 10 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ ने प्रदर्शन किया। केरल में भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर हाईवे जाम करने और बसें रोकने की कोशिश हुई। यहां कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल प्रदर्शन करती भी दिखाई दी है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को चेन्नई में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। एएनआइ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि असंवैधानिक सीएए को कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं लागू होने दिया जाएगा। कर्नाटक में भी मंगलुरु एवं कुछ अन्य जिलों में प्रदर्शन हुआ। यहां पुलिस ने कुछ संवाददाताओं और कैमरामैन को हिरासत में ले लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। मंगलुरु में कर्फ्यू के बाद हालात सामान्य रहे। बेंगलुरु में भी हालात नियंत्रित हो गए हैं। तेलंगाना में ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में नमाज के बाद पुलिस ने एहतियातन कई लोगों हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इस बीच, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध के नाम पर हो रही हिंसा की निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से सीएए को लेकर फैले भ्रम पर सफाई देने को भी कहा। विरोध की हवा केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भी पहुंच गई। यहां पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काउंसिल ने विरोध स्वरूप 23 दिसंबर को होने जा रहे दीक्षा समारोह के बहिष्कार का एलान किया है।

भाजपा ने समर्थन में निकाली रैली : तमिलनाडु में भाजपा की राज्य इकाई ने सीएए के समर्थन में रैली निकाली और मुस्लिमों को भ्रमित करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एच राजा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लाकर बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस और डीएमके बेचैन हैं और मुस्लिम समुदाय व छात्रों को बरगलाकर फायदा उठाना चाह रहे हैं।

उत्तराखंड रोडवेज ने दिल्ली, उप्र जाने वाली बसों का संचालन रोका

जासं, देहरादून : सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) को लेकर चल रहे उपद्रव को देख उत्तराखंड रोडवेज ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के लिए बसों का संचालन रोक दिया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट आइएसबीटी पर फंसी रोडवेज की करीब 30 वाल्वो और एसी बसों को वहीं खड़े रहने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के लिए भेजी गई सभी बसें शुक्रवार की शाम मोहननगर से ही वापस बुला ली गईं। साथ ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखनऊ समेत गुड़गांव व फरीदाबाद के लिए किसी बस का संचालन नहीं किया गया। दिल्ली में उपद्रवियों द्वारा सीलमपुर में बसों में तोड़फोड़ की घटनाओं के मद्देनजर रोडवेज के प्रबंध निदेशक रणवीर चौहान ने शुक्रवार दोपहर दिल्ली रूट की सभी बसों का संचालन अग्रिम आदेशों तक रोकने का आदेश दिया।

उपद्रव को देखते हुए यात्रियों की संख्या भी काफी कम बताई जा रही। संचालन प्रभावित होने से रोडवेज को करीब 40 लाख की चपत लगी है। माना जा रहा कि अगर शनिवार को इसी तरह से संचालन बंद रहा तो यह चपत एक करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी।

विरोध प्रदर्शन में प्रियंका भी हुईं शामिल

नई दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (नीली जैकेट में) ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। एएनआइ

भाजपा की मुसलमानों से अपील, विपक्षी दलों के बहकावे में न आएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को मुसलमानों से अपील की कि वह विपक्षी दलों की ओर से फैलाई गई अफवाहों के बहकावे में न आएं। साथ ही इस बात को गांठ बांध लें कि नागरिकता कानून का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुसैन ने कहा कि यह देश मुसलमान नागरिकों का भी उतना ही जितना दूसरों का है। उन्होंने कहा कि नए कानून को लेकर विपक्षी दल भारतीय मुसलमानों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट किया है कि नागरिकता कानून का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है। विपक्षी दलों की खिंचाई करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह आपका देश है। कृपया विपक्षी दलों के अफवाह फैलाने के जाल में फंसने से बचें।

परिणीति को 'बेटी बचाओ' के ब्रांड एंबेसडर से हटाया गया

मुंबई, आइएएनएस : बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के बारे में खबर है कि हरियाणा सरकार ने उनको 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के ब्रांड एंबेसडर पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ ट्वीट करने के लिए उनको अभियान के ब्रांड एंबेसडर पद से हटाया गया। इस खबर की हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

17 दिसंबर को परिणीति ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए ट्वीट किया था, 'जब-जब जनता अपनी बात रखेगी और उसके साथ यदि ऐसा ही होता रहा, तो कैब को भूल जाओ। अब हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को आगे से लोकतांत्रिक देश नहीं कहना चाहिए। अपनी बात रखने के लिए निर्दोष लोगों को पीटना बर्बरता है।' बता दें कि

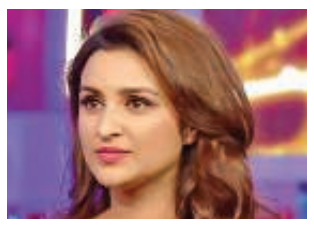
परिणीति चोपड़ा। फाइल

परिणीति अकेली कलाकार नहीं हैं, जिन्हें हाल में उनके काम से हटाया गया है।

इससे पहले सुशांत सिंह को भी सावधान इंडिया के होस्ट से हटा दिया गया था। मुंबई में सीएए विरोधी रैली में भाग लेने के एक दिन बाद उनको हटाया गया था। गौरतलब है कि बॉलीवुड का एक खेमा सीएए का विरोध कर रहा है। इनमें फरहान अख्तर, अनुराग कश्यम जैसे कई लोग शामिल हैं।

सीएए के समर्थन में भी शुरू हुआ प्रदर्शन

जेएनएन, नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने राजधानी दिल्ली में इसके समर्थन में प्रदर्शन किया। भाजपा ने जयपुर में रैली कर राज्य में इस कानून को लागू करने की मांग की तो पंजाब के अमृतसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) रैली निकालकर खुशी जताई।

जयपुर में आयोजित रैली में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विरोध करने और आंदोलन करने का अधिकार सबको है लेकिन कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सबका सम्मान करेगा लेकिन आतंकवादी और टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्त भी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून विस्थापितों के लिए लाया गया है। हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर लागू नहीं है। इसे एनआरसी से मत जोड़िए। उसकी अलग प्रक्रिया होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार का है और उसने अधिसूचना के जरिए कलेक्टरों को अधिकृत कर रखा है। यदि राज्य कलेक्टरों को यह काम नहीं करने देंगे तो हम आयकर अधिकारियों या कस्टम अधिकारियों को यह नागरिकता देने का अधिकार दे देंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस में कार्यक्रम आयोजित कर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) व कांग्रेस सहित अन्य विरोधी पार्टियों पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन नेताओं पर है, वही माहौल बिगाड़ रहे हैं।

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इनर सर्किल में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा लेकर मार्च करते लोग। पारस कुमार

हिंसा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 19 दिसंबर को लखनऊ में हुई हिंसा और संपत्ति के नुकसान मामले में उप्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही जिलाधिकारी लखनऊ को उपद्रव में हुई क्षति का आकलन करने का भी निर्देश दिया है। इस बाबत सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी। पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि हिंसा में जिन संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हिंसा फैलाने वालों से ही की जाए। याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ही पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह भी कहा है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से कराई जाए, जो इसमें शामिल थे। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को संक्षिप्त शपथ पत्र के जरिए अपनी बात कहने का निर्देश दिया है।

आरोप-प्रत्यारोप

भाजपा विधायकों ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि पोषाहार माफिया के दबाव में अफसर को किया गया प्रताड़ित, सत्तापक्ष ने कहा- स्वेच्छा से वीआरएस लिया, गलती की वजह से किया था तबादला

आइएएस गौरी सिंह के नौकरी छोड़ने को लेकर मप्र विस में हंगामा

नईदुनिया, भोपाल

1987 बैच की आइएएस अफसर गौरी सिंह के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर नौकरी छोड़ने के मुद्दे पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि पोषाहार माफिया के दबाव में सिंह को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें नौकरी छोड़ने जैसा कदम उठाना पड़ा। प्रदेश में तबादला माफिया हावी है। ईमानदार अफसर परेशान हैं। सत्तापक्ष की ओर से मंत्रियों ने कहा कि सिंह ने स्वेच्छा से वीआरएस लिया। तबादला उनके द्वारा गलती करने की वजह से किया था। मामले में विपक्ष ने गर्भगृह में आकर नारेबाजी की और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने जरूरी सरकारी काम पूरे कराकर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरी सिंह के नौकरी छोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार

गौरी सिंह फाइल

चरम पर है। सिंह का तबादला पोषाहार माफिया के दबाव में किया गया क्योंकि उन्होंने पोषाहार के प्लांट एमपी एग्रो को देने का विरोध किया था। वहां ठेकेदार काम करेंगे। ईमानदार अफसर नौकरी छोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पूछा कि सिंह ने फाइल पर ऐसा क्या लिखा था कि तबादला किया गया। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, वित्त मंत्री तरण भनोत सहित अन्य मंत्रियों ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पटेल ने कहा कि आरोप निराधार हैं। सिंह ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया है। उनका तबादला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने नियम-कायदों के परे जाकर पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया। न तो मुझसे (विभागीय मंत्री) से अनुमोदन लिया और न ही मुख्यमंत्री को बताया। किसी को भी नियम-कायदों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।

वीआरएस लेने वाली पहली अफसर नहीं सिंह : पूरक पोषण आहार को लेकर लगाए गए आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि पोषाहार का काम ठेकेदारों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भाजपा सरकार में पोषाहार व्यवस्था में घोटाले होते थे। कमलनाथ सरकार इन व्यवस्थाओं को सुधार रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। उधर, जनसंपर्क मंत्री शर्मा ने कहा कि जिस अधिकारी की जहां उपयोगिता होती है, वहां लगाया जाता है। सिंह पहली अफसर नहीं हैं, जिन्होंने वीआरएस लिया है। भाजपा सरकार में प्रवेश शर्मा, रश्मि शुक्ला शर्मा, अनिल यादव और मुकेश कक्कड़ वीआरएस ले चुके हैं। क्या इन्हें भाजपा ने प्रताड़ित किया था।

यह है मामला

गौरी सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर दिया है। बताया जा रहा है कि वे नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र काम करने वाली दुबई स्थित अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करेंगी। सिंह का चयन संस्था के उप महानिदेशक पद के लिए हुआ है। पिछले दिनों ही उनका तबादला पंचायत एवं ग्रामीण विकास से प्रशासन अकादमी में महानिदेशक के पद पर किया गया था। यह माना जा रहा था कि वे इससे खफा हैं। सिंह मध्य प्रदेश आइएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं।

डिग्गी पैलेस में आखिरी बार होगा जेएलएफ का आयोजन

मनीष गोधा, जयपुर

जयपुर की पहचान बन चुका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) इसके स्थाई आयोजन स्थल डिग्गी पैलेस में इस मर्तबा आखिरी बार होगा। आयोजन अगले साल 23 से 27 जनवरी के बीच होगा। इसके बाद अगली बार से आयोजकों को कोई नया स्थान ढूंढना होगा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में गुरवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा कारणों से यह फैसला किया है। वर्ष 2021 में होने वाला जेएलएफ डिग्गी पैलेस में आयोजित नहीं होगा। हालांकि इस बार का जेएलएफ 23 से 27 जनवरी तक डिग्गी पैलेस में ही होगा। फेस्टिवल के निदेशक संजोय रॉय का कहना है कि जेएलएफ के जयपुर शहर के साथ जुड़ाव पर अत्यंत गर्व है। हम राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, जयपुर पुलिस और जयपुर के नागरिकों के निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम जेएलएफ को फिर से विचारों का उत्सव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें आने वाले सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

गौरतलब है कि अपने पहले आयोजन के समय से ही जेएलएफ प्रतिवर्ष डिग्गी पैलेस में आयोजित किया जाता है। यह इस कार्यक्रम का स्थाई आयोजन स्थल बन गया है। डिग्गी पैलेस जयपुर के व्यस्ततम मार्ग टोंक रोड पर है और इसके नजदीक ही राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित है। शुरआती सालों में तो ज्यादा परेशानी नहीं आई लेकिन पिछले पांच-छह वर्ष से जेएलएफ बहुत बड़ा आयोजन बन गया है। हर वर्ष पांच दिन में हजारों लोग इस आयोजन में आते हैं और इनमें देश-विदेश की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं।

8.3 किलोग्राम वजन के 50 सोने के बिस्कुट जब्त किया है राजस्व खुफिया निदेशालय की कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) रेलवे स्टेशन पर कंचनजंघा एक्सप्रेस से। सोने के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है।

न्यूज गैलरी

रंजीत हत्याकांड में जज बदलने की मांग हाई कोर्ट ने ठुकराई

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ चल रहे पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में जज बदलने की मांग खारिज दी है। कोर्ट ने याचिका को आधारहीन माना। इससे पहले सीबीआइ अदालत भी इस मांग को ठुकरा चुकी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची और रंजीत हत्याकांड में सह आरोपित कृष्ण लाल ने कहा कि सीबीआइ जज जगदीप सिंह पहले भी गुरमीत सिंह के खिलाफ दो मामलों में फैसला सुना चुके हैं। ऐसे में यह मामला उन सजाओं से प्रभावित होगा। इसलिए रंजीत सिंह हत्या मामले में वह जज जगदीप सिंह से सुनवाई नहीं करवाना चाहता है। हाई कोर्ट ने कहा कि याची की ऐसी शंका निराधार है। डेरा प्रबंधक रहे रंजीत सिंह हत्याकांड में अब अंतिम बहस शुरू होने वाली है, परंतु पिछली सुनवाई में अचानक बचाव पक्ष की ओर से जज बदलने की मांग उठा दी गई थी। (राज्य)

सीआरपीएफ ने जम्मू में सभी अधिकारियों को ड्यूटी पर बुलाया

नई दिल्ली : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने जम्मू में कमांडेंट और उससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारियों को हर हाल में ड्यूटी पर पहुंचने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में ट्रेन या फ्लाइट कैंसल होने जैसा कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होगा। छुट्टी पर चल रहे अधिकारियों को भी रिपोर्ट करने को कहा गया है। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई स्टाफ या ऑफिसर टेन या फ्लाइट कैंसल होने से प्रभावित नहीं हो और ड्यूटी पर रिपोर्ट करे। किसी भी हाल में किसी अधिकारी को फ्लाइट रद होने के कारण दिल्ली में नहीं फंसे रहना है।' अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर सड़क मार्ग से आने को भी कहा गया है। हालांकि यह निर्देश भी दिया गया है कि सड़क मार्ग से आते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। (एएनआइ)

नीरव मोदी के भाई निहाल के खिलाफ आरोपपत्र

मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर के घोटाले में सीबीआइ ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई निहाल और चार अन्य आरोपितों के खिलाफ एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है। जज वीसी बरडे ने बताया कि आरोप पत्र में नीरव मोदी के अलावा उनके भाई निहाल मोदी (देश से फरार) पीएनबी के निलंबित मैनेजर संजय प्रसाद, नीरव मोदी के सहयोगी अमित मागिया, संदीप मिस्त्री और मिहिर भंसाली के नाम दर्ज हैं। भंसाली, मिस्त्री और निहाल मोदी देश के बाहर हैं। सीबीआइ का कहना है कि इन तीनों के खिलाफ समन जारी किया जाएगा। विशेष अधिवक्ता ए.लिमोसिन ने बताया कि जांच एजेंसी में सुबूतों को नष्ट किए जाने के नए आरोप लगे हैं और गवाही देने की बात कही गई है। (प्रेट्र)

मौसम की मार ▶ उत्तराखंड के चार धाम में फिर हिमपात, ठिठुरन बरकरार, लोग हुए परेशान

शिमला से भी ज्यादा ठंडे हिसार व बठिंडा

दिल्ली-एनसीआर में भी दिख रहा है ठंड का असर

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ रही है। वहीं, उसका असर दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब और पूरे हरियाणा में भी दिखाई दिया। पंजाब के बठिंडा और हरियाण के हिसार में तो शिमला से भी कम तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड समेत हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड बरकरार है।

पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर शहरों में शीतलहर के कारण सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को पंजाब का बठिंडा और हरियाणा का हिसार शिमला से भी ठंडा रहा। बठिंडा का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस और हिसार का रात का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि शिमला से भी कम था।

उत्तराखंड में शुक्रवार देर शाम को ज्यादातर इलाकों में बादलों ने डेरा डाल दिया। इस बीच पर्वतीय क्षेत्रों में चार धाम के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात से कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि अब भी प्रदेश के आठ शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इतना ही नहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से पांच से सात डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है।

बारिश और बर्फबारी के आसार : उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन शीतलहर का असर बना रहा। मसूरी, चमोली के जोशीमठ और कुमाऊं के चंपावत में पारा तीन डिग्री सेल्सियस से भी कम है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। वहीं, हिमाचल में भी अगले दो दिन बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है।

हिमाचल में इस बार व्हाइट क्रिसमस की आस कम : इस बार मौसम के तेवर बेशक कड़े हैं, लेकिन व्हाइट क्रिसमस की आस कम है। मौसम विभाग ने 22 से 26 तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि 15 दिसंबर को हुई बर्फबारी से क्रिसमस पर भी बर्फ गिरने की उम्मीद की जा रही थी।

कश्मीर में शुरू हुआ चिल्ले कलां : कश्मीर में चिल्ले कलां (सबसे सर्द 40 दिन) शनिवार यानी आज से शुरू हो जाएगा। इसके पहले शुक्रवार से ही मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया। पहाड़ों समेत मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। उच्च पर्वतीय इलाकों के साथ वादी के निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई जो देर रात तक जारी थी। हर साल चिल्ले कलां के दौरान ही तापमान जमाव बिंदु से नीचे जाता है, लेकिन इस बार पहले से ही चला गया। इसके चलते जलस्रोत पहले से ही जमने लगे थे।

उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर हर्षिल के निकट बर्फ बन चुका झरना कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। यह झरना अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हरदेव पंवार

क्या है चिल्ले कलां

कश्मीर में सर्दी के सबसे ठंडे 40 दिनों को चिल्ले कलां नाम दिया गया है। इस समयावधि में मौसम के मिजाज तीखे रहते हैं। बर्फबारी व बारिश होती है। घने बादलों के चलते धूप नहीं निकलती। इसके बाद 20 दिन का चिल्ले खुर्द शुरू होता है। इस अवधि में चिल्ले कलां की तुलना में सर्दी कम होती है। इसके बाद 10 दिन का चिल्ले बच्चा शुरू होता है। इस समय मौसम में सुधार आने लगता है। पारा जमाव बिंदु के ऊपर आने लगता है।

अयोध्या कचहरी विस्फोट में दो आतंकियों को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, अयोध्या

12 साल बाद आया फैसला, दोषियों पर एक लाख का जुर्माना

अयोध्या में कचहरी सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकवादियों तारिक काजमी और मुहम्मद अख्तर को शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना के 12 साल बाद सुनाए गए फैसले में दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है। उन्हें लखनऊ सीरियल ब्लास्ट मामले में पहले इतनी ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि तारिक काजमी को एक अन्य बाराबंकी विस्फोट बरामदगी मामले में भी सजा दी जा चुकी है। तीसरे अभियुक्त सज्जादुर्रहमान को मामले में बरी कर दिया। चौथे अभियुक्त खालिद मुजाहिद की मौत मई 2013 में न्यायिक हिरासत में हो गई थी।

मुहम्मद अख्तर लखनऊ जेल से मंडल कारागार में लगी अदालत में नहीं लाया जा सका। कोर्ट ने उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद तारिक काजमी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बाराबंकी जेल वापस भेज दिया गया, जबकि सज्जादुर्रहमान की रिहाई शनिवार को होगी। वह लखनऊ के सीरियल ब्लास्ट मामले में पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है।

इन धाराओं में मिली सजा : अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विजय ओझा ने बताया कि सजा पाए दोनों अभियुक्तों को धारा 302 (हत्या), 307 (जानलेवा हमला), 121 (राष्ट्रद्रोह), धारा 3/4 (विस्फोटक अधिनियम), धारा 16/20,18 व 23 (विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम) का दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को धारा 307 में भी 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त 2008 से जेल में निरुद्ध हैं। जेल में काटी गई अवधि भी उसकी सजा में जुड़ेगी।

यह थी घटना

23 नवंबर 2007 की दोपहर करीब एक बजे कचहरी के शेड नंबर चार में साइकिल बम में हुए विस्फोट से अधिवक्ता राधिका प्रसाद मिश्र समेत चार लोगों की मौत हुई थी। करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सीरियल ब्लास्ट की विवेचना एटीएस ने की थी। 2008 में चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र अदालत भेजा गया। आतंकवादियों ने अपने एक साथी वलीउल्लाह पर कचहरी में हुए हमले का बदला लेने और दहशत कायम करने के लिए वारदात की।

कश्मीर में सब सामान्य, शांति से हुई जुमे की नमाज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ न तो जामा मस्जिद परिसर और न ही बाहर हुई भड़काऊ नारेबाजी

▶ श्रीनगर में किसी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुआ

कश्मीर में स्थिति के पूरी तरह सामान्य है। शुक्रवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में अलगाववादियों का गढ़ कहलाने वाले डाउन टाउन स्थित ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। नमाज के बाद न मस्जिद परिसर के भीतर और न ही बाहर किसी तरह की भड़काऊ नारेबाजी सुनने को मिली। कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ और न किसी आतंकी का पोस्टर या पाकिस्तानी झंडा नजर आया।

ऐसी आशंकाएं थीं कि जामिया मस्जिद में शायद नमाज नहीं होगी और प्रशासन भी शायद ही अनुमति दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबकुछ शांतिपूर्ण रहा। जामिया मस्जिद के दरवाजे सुबह ही खुल गए और लोगों ने बिना किसी रुकावट के नमाज हुई। नमाज के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया था। मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर स्थानीय युवक भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करते नजर आए। करीब 1200 लोग नमाज के लिए पहुंचे थे। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक कथित रूप से बीमार व नजरबंद होने के कारण मस्जिद में नहीं पहुंचे। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरी वादी में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासनिक पाबंदियों को लागू कर दिया था। इसका असर जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज पर भी हुआ। शुरू में दावा किया जाता रहा कि प्रशासनिक पाबंदियों के चलते लोग मस्जिद में नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन करीब एक माह पहले प्रशासन ने इस इलाके में भी प्रशासनिक पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया था। इसके बावजूद मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी। प्रशासन ने नमाज की बहाली के लिए गत माह कई बार मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और मस्जिद प्रबंधकों से संपर्क किया था। इस पर उन्होंने कहा था कि नमाज के लिए मस्जिद नहीं खुली। संबंधित सूत्रों ने बताया कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो इस मस्जिद के प्रमुख हैं और कथित रूप से उनके इशारे पर ही मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और उसके बाद दो दिन पहले जामिया मस्जिद में करीब 136 दिन बाद नमाज हुई थी।

श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जागरण

फारूक अब्दुल्ला को मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत

नवीन नवाज, जम्मू

▶ पूर्व मुख्यमंत्री को घर में ही पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया

▶ मोबाइल के माध्यम से अपने परिजनों से संपर्क में हैं पूर्व मुख्यमंत्री

जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अपने घर में कैद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला को प्रशासन ने मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान कर दी है। वह इसके माध्यम से परिजनों के संपर्क में भी हैं। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि वह सुविधा का इस्तेमाल सियासत या समर्थकों संग चर्चा के लिए नहीं करेंगे। हिरासत के बाद से पहली बार दैनिक जागरण प्रतिनिधि ने उनसे फोन पर बात की।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पेश होने से पूर्व प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में ले लिया था। डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर सितंबर में पीएसए लगा दिया गया था। उनको श्रीनगर में गुपकार मार्ग पर उनके आवास पर ही रखा गया है।

बोले- कुशल से हूं, सियासी टिप्पणी से इन्कार : दैनिक जागरण के साथ बातचीत में डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां यह बता दें कि वयोवृद्ध नेता हृदयरोगी हैं और उनकी किडनी का भी प्रत्यारोपण हुआ है। उन्होंने जम्मू के हालात और मौसम के बारे में पूछा। कहा कि यहां श्रीनगर में भी बहुत ठंड हो गई है। खुदा सभी को सलामत रखे। सियासी बातचीत से इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जो खुदा की मर्जी होगी, वही होगा।'

उमर व महबूबा को लैंडलाइन के इस्तेमाल की इजाजत : इस बीच, सूत्रों के अनुसार उनके पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमाक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी लैंडलाइन फोन के सीमित इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एमएलए हॉस्टल श्रीनगर में एहतियातन हिरासत में रखे गए विभिन्न राजनीतिक दलों के 33 नेताओं को भी सीमित आधार पर मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है।

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप

नई दिल्ली, प्रेट्र : अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शुक्रवार को जबर्दस्त भूकंप से उत्तर भारत के कई राज्य दहल गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) ने बताया कि भूकंप का असर दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के कई हिस्सों में दिखा। हालांकि कहीं भी भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है।

एनसीएस के डायरेक्टर, ऑपरेशंस जेएल गौतम ने बताया कि शाम 5:10 बजे क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में धरती से करीब 200 किलोमीटर अंदर था। इसका व्यापक असर उत्तरी पाकिस्तान में भी दिखा। पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके यहां स्वात, नौशेरा, एबटाबाद और कोहाट समेत कई जगहों पर महसूस किए गए। पाकिस्तान के स्थानीय टीवी चैनलों ने बताया कि झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर की ओर भागने लगे। सांसद भी बीच सत्र में निकलकर बाहर आ गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी कार्यालयों से बाहर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में लोग दहशत में देखे गए। हालांकि भूकंप से कहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

पीड़िता ने कहा, पिता के हत्यारों को भी दी जाए ऐसी ही सख्त सजा

उन्नाव दुष्कर्म कांड

जागरण संवाददाता, उन्नाव

▶ विधायक को उम्रकैद पर दुष्कर्म पीड़िता ने जताया संतोष

▶ टीवी पर फैसला सुन वकील से पुष्टि की, फिर खूब रोई

उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देने वाले उन्नाव दुष्कर्म कांड में विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा पर पीड़िता बोली, अब लग रहा है कि उसके साथ न्याय होगा। दैनिक जागरण से बातचीत में पीड़िता ने कहा कि मेरे पिता के हत्यारों को भी ऐसी सख्त सजा दी जाए। उत्पीड़न-दमन के खिलाफ लड़ाई में पिता, चाची और मौसी को खो देने और न्याय के लिए करीब ढाई साल से इंतजार कर रही पीड़िता फैसला सुनने के लिए शुक्रवार सुबह से ही टीवी के सामने बैठी थी। बकौल मां, बिटिया सुबह से ही परेशान थी, किसी से कुछ बात तो नहीं कर रही थी पर बार-बार टीवी ऑन-ऑफ कर रही थी। दोपहर दो बजे के बाद टीवी पर सजा की खबर देखने के बाद अपने वकील से पुष्टि की और खूब रोई।

जागरण से बात करने को तैयार हुई पीड़िता ने पहले तो अन्याय के खिलाफ साथ देने के लिए धन्यवाद कहा और फिर बोली कि अब उसे लग रहा है कि उसके साथ न्याय होगा। कोर्ट और अपने वकीलों का आभार जताते हुए कहा कि विधायक को मिली सजा से वह संतुष्ट है। उसने कहा कि विधायक के दबदबे के कारण पुलिस ने सुनवाई नहीं की। न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में पैरवी कर रहे पिता को तारीख से लौटते वक्त पीट-पीटकर मार डाला गया। उनके हत्यारों को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए।

चाचा की रिहाई तक न्याय अधूरा

पीड़िता का कहना था कि उसे न्याय मिला पर वह बेगुनाह चाचा की रिहाई तक अधूरा ही रहेगा। उसने कहा कि पिता की हत्या के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए दिल्ली में रहे चाचा ने कारोबार छोड़ दिया। चाची की हत्या के बाद उनका परिवार भी तबाह हो गया। छोटे चचेरे भाई के सिर से मां का साया उठ गया। उसका आरोप है कि विधायक ने चाचा के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए और जमानत नहीं होने दी। एक में उनको सजा भी हो गई। जब तक वह बरी नहीं होते उसे पूरा न्याय नहीं मिलेगा।

हर तीन माह में पीड़िता की सुरक्षा का आकलन करे सीबीआइ

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

अदालत ने सीबीआइ को निर्देश दिया कि वह हर तीन महीने में पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का आकलन करती रहे। ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों का जीवन सुरक्षित रहे। पीड़ित परिवार किसी भी सहायता के लिए सीबीआइ, दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव या जिला गवाह सुरक्षा समिति, दिल्ली से संपर्क कर सकते है।

सेंगर को अधिकतम सजा देने की जहां पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने जोरदार अपील की, वहीं सेंगर के वकील तनवीर अहमद मीर दया मांगते रहे। मीर ने जुर्माना भी कम से कम करने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि सेंगर का परिवार मुश्किल से चल रहा है। बच्चों की फीस रिश्तेदारों से उधार लेकर देनी पड़ रही है। चुनाव के दौरान सेंगर ने जो संपत्ति का ब्योरा दिया था, उससे पीड़िता का मुआवजा तय नहीं करना चाहिए। वहीं, पीड़िता के वकील द्वारा बार-बार कुछ तथ्यों को दोहराने पर न्यायाधीश ने उन्हें टोक भी दिया।

पॉक्सो के तहत ठहराया गया था दोषी : कुलदीप सेंगर ने जून, 2017 में पीड़िता के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया था। इस मामले में सेंगर की सहयोगी शशि सिंह को अदालत ने विगत सोमवार को बरी कर दिया था। सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हुई है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

कई मामले में अभी विचाराधीन : दुष्कर्म के इस मामले के साथ ही पीड़िता से ही सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या और पीड़िता को ट्रक से कुचलने की कोशिश के मामले अभी इसी अदालत में विचाराधीन हैं। हिरासत में हत्या व पीड़िता को ट्रक से कुचलने की कोशिश के मामले में कुलदीप सेंगर भी आरोपित है।

> यह ऐतिहासिक फैसला है। पीड़िता को अदालत ने न्याय दिया है। हमारी लड़ाई अन्य मामलों में न्याय दिलाने के लिए भी जारी रहेगी।
>
> -धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पीड़िता के वकील

> अदालत के इस फैसले के खिलाफ जल्द ही हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।
>
> -तनवीर अहमद मीर, दोषी के वकील

लोकतंत्र के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने किया घिनौना कार्य : अदालत

जासं, नई दिल्ली : कुलदीप सेंगर को सजा सुनाते वक्त तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने घिनौना कार्य किया है। एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी गरिमा, शुद्धता, सम्मान और प्रतिष्ठा पर दाग लगाया गया। उन्होंने कहा कि दबंग व्यक्ति द्वारा किए गए इस तरह के जघन्य अपराध में दया करने का मतलब न्याय का दमन करना होगा। इसमें उदारता की दलील को नहीं माना जा सकता। अदालत ने 25 लाख जुर्माना और 10 लाख मुआवजा देने का आदेश देते हुए पीड़िता के लिए चिंता भी प्रकट की। न्यायाधीश ने कहा कि मुआवजे की कोई भी रकम खोया हुआ जीवन वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन, पीड़िता और उसके परिवार के लिए यह रकम अपमान की भरपाई के लिए कुछ सांत्वना जैसी होगी। दोषी ने खुद और अपने गुर्गों की मदद से पीड़िता और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए हर घिनौना काम किया।

पाक को परमाणु पनडुब्बी अरिहंत की गतिविधियों का पता चला

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

जांच में पता चला है कि पूर्वी कमांड के मुख्यालय विशाखापत्तनम और वहां तैनात परमाणु पनडुब्बी अरिहंत की गतिविधियों की भी जानकारियां पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। यह भी पता चला है कि इसमें भारतीय जल क्षेत्र में आने वाले संदिग्ध चीनी जहाज की भी भूमिका हो सकती है। वहीं वायुसेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में है। करवर समेत उसकी भी जानकारियां पाकिस्तानी एजेंटों के हाथ लग चुकी हैं। इन नौसैनिक अड्डे पर भारत का इकलौता वायुसैनिक युद्धपोत विक्रमादित्य तैनात है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उसकी सभी 'अहम संपत्तियां' सुरक्षित हैं और उसमें किसी की 'घुसपैठ' नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश की पुलिस ने पाकिस्तानी जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए बताया है कि उसने कुछ जूनियर नेवल अफसरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच अब आंध्र प्रदेश की पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए सभी नौसैनिक अफसर एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में थे जिसने फेसबुक पर इन सभी से दोस्ती कर ली थी। ऐसा आरोप है कि इन अफसरों को खुफिया जानकारियां देने के लिए हवाला ऑपरेटर के जरिए रकम अदा की गई थी। इन नौसैनिक नाविकों और उस महिला के बीच हुई चैट यौन व्यवहार संबंधी थी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के गुर्गों ने उस महिला के रूप में एक हनी ट्रैप तैयार किया था। इन्हीं चैट के आधार पर बाद में इन नौसैनिकों को ब्लैकमेल किया गया और उन्हें जानकारियां देने को मजबूर किया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच जारी है और मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एफआइआर दर्ज कर देश के अलग-अलग हिस्सों से नौसेना के सात अफसरों के अलावा एक हवाला ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

बड़ा मामला

एएसआइ निदेशक, केंद्र, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार को नोटिस, सिख फेडरेशन ने दायर की याचिका

हाई कोर्ट पहुंचा गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी विवाद

जागरण संवाददाता, नैनीताल

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के हरकी पैड़ी के पास गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी का दशकों पुराना विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) के निदेशक सहित केंद्र सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।

शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में उत्तराखंड सिख फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गुरदीप सिंह सहोता की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था। गुरुनानक देव के आगमन पर हरकी पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी जो 1976 तक इस स्थान पर थी। 1976 में हरकी पैड़ी के सौंदर्यीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से इस आश्वासन पर हटाया गया कि उसे फिर से इसी स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा, मगर सिखों की इस ऐतिहासिक धरोहर व पवित्र चिह्न को अभी तक वहां स्थापित नहीं किया गया। 1984 में सिख दंगों के दौरान शांति व्यवस्था को देखते हुए स्थान को खाली नहीं कराया। 1986 से सिख संगठन ज्ञान गोदड़ी की जमीन वापस मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2001 में इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में की गई तो आयोग ने उचित स्थान पर भूमि मुहैया कराने के निर्देश दिए। 2003 में तत्कालीन डीएम ने गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की स्थापना के लिए रानीपुर रोड प्रेमपुर आश्रम हरिद्वार में आधा हेक्टेयर भूमि का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेजा। जांच में यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की निकली। इस संदर्भ में आयोग से दोबारा शिकायत करने पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए भूमि आवंटित की जाए, लेकिन यह मामला अभी भी लंबित है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एएसआइ निदेशक, भारत सरकार, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

नैनीताल हाई कोट फाइल

बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या में राहुल दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ सीबीआइ कोर्ट ने गत 30 अक्टूबर को आरोप तय किया था

▶ 15 दिसंबर 2016 को दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डाला गया था

रांची की बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने के मामले में अभियुक्त राहुल राय उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन को अदालत ने दोषी ठहराया है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने गत 30 अक्टूबर को आरोप तय किया था। जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी।

15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। सीबीआइ ने 23 वर्षीय अभियुक्त को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 22 जून को रांची लेकर पहुंची थी। इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। अदालत में राहुल के दोस्त अक्षय ने बताया कि घटना के बाद राहुल उसके साथ स्कूटी से पीड़िता के घर पहुंचा था। घटना की शाम में वह पटना चला गया। वहीं से फोन कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेता था। अक्षय कुमार बूटी बस्ती में ही रहता है। बताया कि घटना के कुछ दिन पहले राहुल नालंदा से रांची आया था। रांची आने पर उससे संपर्क किया और एक किराये का कमरा दिलाने को कहा। तुरंत कमरा नहीं मिलने पर मोहल्ले के ही एक मंदिर के पीछे वाले कमरे में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करा दी थी। मंदिर में रहने के दौरान मोहल्ले के बच्चों से लड़की के बारे में पूछता था। इस हरकत पर दो बार उसे डांटा भी था।

किराए पर मकान के लिए पहुंचा था अभियुक्त : पीड़िता की बहन

पीड़िता की दो बहनों की भी अदालत में गवाही दर्ज की गई है। एक बहन ने अदालत को बताया कि घटना के कुछ दिन पहले राहुल किराए का कमरा लेने के लिए उसके घर आया था। परिवार वालों ने लड़के को कमरा देने से मना कर दिया। उसी दिन के बाद से कई बार अहसास हुआ कि राहुल उसकी बहन का पीछा कर रहा है। घटना से पहले घर के आसपास उसे घूमते हुए भी देखा था, जबकि वारदात के बाद उसे कभी नहीं देखा गया।

दैनिक जागरण

युवावस्था उम्मीदों पर जिंदा रहती है, बुढ़ापा यादों पर

उद्योग जगत को आश्वासन

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने उद्योग-व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के बीच जाकर न केवल इस पर जोर दिया कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को असंगठित से बदलकर संगठित व्यवस्था में ला रही है, बल्कि इस बारे में भी बताया कि भविष्य में और क्या कदम उठाए जाने हैं? आर्थिक सुस्ती के इस दौर में एसोचैम के मंच से प्रधानमंत्री के इस संबोधन का इसलिए विशेष महत्व है कि अगले आम बजट की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने यह जो कहा कि उनकी सरकार ने इसके लिए भरसक प्रयास किए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धारित नियमों से चले और तय लक्ष्यों की ओर बढ़े उससे इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीते कुछ समय में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनके बारे में चर्चा तो खूब होती थी, लेकिन उन पर आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। इस सबके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अर्थव्यवस्था को अनुशासित बनाने के लिए उठाए गए तमाम कदमों के बाद भी अनुकूल नतीजे सामने आना शेष हैं। यह आवश्यक है कि सरकार यह देखे कि उसकी ओर से उठाए गए कदम जमीन पर क्या असर दिखा रहे हैं? इसी क्रम में उसे किस्म-किस्म की मिथ्या धारणाओं और अनावश्यक अंदेशों को भी दूर करना होना होगा। यह इसलिए, क्योंकि कई अंदेशे तो उन नियम-कानूनों को लेकर भी हैं जिनका सरलीकरण किया गया है अथवा जिन्हें पारदर्शी बनाया गया है। यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि उद्योग-व्यापार जगत हर तरह के अंदेशे से मुक्त हो। जब उद्योग-व्यापार जगत के छोटे-बड़े प्रतिनिधि अंदेशे से घिरते हैं या फिर शिकायती मुद्रा में आते हैं तो उससे आम जनता पर भी विपरीत असर पड़ता है। इससे एक नकारात्मक माहौल बनता है। ध्यान रहे कि कई बार आर्थिक सुस्ती की चौतरफा चर्चा उसे बढ़ाने का ही काम करती है।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी में हो रहे लगातार सुधारों के उल्लेख के साथ ही यह भी रेखांकित किया कि आयकर विभाग के कामकाज को दुरुस्त करने के अतिरिक्त बैंकों की हालत सुधारने का काम भी जारी है। उन्होंने यह कहकर भी उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि जरूरी नहीं कि कारोबार में असफलता के पीछे आर्थिक अपराध ही हो। चूंकि सरकार जो कह रही है वह लगातार कर भी रही है इसलिए इसका कोई कारण नहीं कि उद्योग-व्यापार जगत प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा न करे। यह केवल अनुमान ही नहीं है कि आगामी बजट में सरकार आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के कुछ और कदम उठाने जा रही है, बल्कि इसके संकेत भी दिए जा रहे हैं। अच्छा होगा कि जो कदम बजट के पहले उठाए जा सकते हों वे उठा लिए जाएं।

गुणवत्ता से समझौता नहीं

नवादा में घटिया सड़क निर्माण देख बिफरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रशासनिक मशीनरी को कड़ा संदेश दिया है कि वह किसी भी सरकारी कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री की नाराजगी का असर यह हुआ कि विभाग के आला अफसरों ने तत्काल नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू कराया। दरअसल जल-जीवन-हरियाली यात्रा पर मुख्यमंत्री नवादा जिले के रजौली पहुंचे थे। रजौली से सटे प्राणचक गांव में वाहन से उतरकर वह विद्यालय की ओर जाने के लिए दो कदम ही बढ़े थे कि सड़क के कालीकरण पर उनकी नजर पड़ गई। पैरों से सड़क को कुरेद कर देखा तो गिट्टी की परतें उखड़ने लगीं। वह इस पर काफी नाराज हुए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि कुछ अच्छा कराइए, यह कितने दिन टिकेगी। जिस जर्जर सड़क को देखकर सीएम ने नाराजगी जताई वह मुख्यमार्ग नहीं है। गांवों का संपर्क पथ है। उनकी नाराजगी में मतलब यह भी है कि इस तरह की छोटी सड़कों के निर्माण में भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। अभी दो दिन पूर्व गया की जर्जर सड़क पर दायर एक लोकहित याचिका पर सुनवाई के क्रम मुख्य न्यायाधीश संजय करोल वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए खुद अपनी गाड़ी से गया के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़क इतनी खराब थी कि उन्हें गाड़ी छोड़कर ट्रेन में बैठना पड़ा और वे पटना लौटे थे। इस दोनों घटनाओं का सीधा संदेश है कि सड़क निर्माण में किसी तरह की कोताही किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा योजनाओं का मुआयना करते आए हैं। पहले भी कई योजनाओं में की गई कोताही पर फटकार लगा चुके हैं। अपनी समीक्षा बैठकों में भी वह अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि इस योजना के पूर्ण होने पर उसका स्थल निरीक्षण करें। जल-जीवन-हरियाली अभियान पर मुख्यमंत्री यात्रा पर हैं। यह उनका महात्वाकांक्षी अभियान है। स्पष्ट है कि भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से चल रहे इस अभियान में भी किसी तरह अनदेखी मुख्यमंत्री नहीं सहन करने वाले। राज्य के जिन जिलों में वह अब जाएंगे, वहां के प्रशासनिक तंत्र को सजग रहना होगा, ताकि सरकारी कार्यों में किसी तरह की अनियमितता या लापरवाही न हो।

नवादा के रजौली में जर्जर पर मुख्यमंत्री का बिफरना प्रशासनिक मशीनरी के लिए सख्त संदेश है। स्पष्ट है कि गुणवत्ता पर समझौता बर्दाश्त नहीं है

अराजकता की मार झेलती पुलिस

विक्रम सिंह

पुलिस पर गैर जरूरी सख्ती का आरोप लगाने वाले यह बताएं तो बेहतर कि आखिर पुलिस बल तब क्या करे जब उस पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जाएं?

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन और उसके साथ ही अराजकता का दौर थमने का नाम न लेना चिंताजनक है। इस कानून के विरोध में बंगाल के उपरांत दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विवि में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद से हिंसा का सिलसिला तेज हुआ है। इस विश्वविद्यालय की घटना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर अभी तक चल रहा है। कुलपति नजमा अख्तर का आरोप है कि पुलिस ने बिना अनुमति विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। कानूनी स्थिति के बारे में बौद्धिक जमात द्वारा भी जमकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें हमारे बॉलीवुड के कलाकार भी पीछे नहीं हैं। वे कह रहे हैं कि पुलिस को किसी विश्वविद्यालय में बिना अनुमति प्रवेश का अधिकार नहीं है। इस कोरी कल्पना भरी बयानबाजी से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसका बेजा लाभ उठाया गया। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 41, 46, 47, 48 में स्पष्ट वैधानिक प्रावधान है कि हिंसा और अपराध की स्थिति में पुलिस किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने और वैधानिक कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है। देश में जहां-जहां हिंसा हो रही है वहां-वहां पुलिस पर यह आरोप भी चस्पा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर उसने अनुपात से कहीं अधिक बल का प्रयोग किया। आखिर पुलिस तब क्या करे जब कोई उस पर पेट्रोल बम फेंके, पत्थर बरसाए, घटनास्थल पर गीले बोरों को इस उद्देश्य से जमा करे कि जब आंसू गैस छोड़ी जाए तो उसे निष्प्रभावी किया जा सके? इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रदर्शनकारी पुलिस से सीधा मुकाबला करने की मंशा से आ रहे हैं। ऐसी हालात में पुलिस हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती।

इसके बावजूद पुलिस के स्तर पर भी कुछ कमियां जाहिर होती हैं। कोई घटना अकस्मात नहीं होती। यदि अराजक प्रदर्शन की तैयारी हो रही हो तो पुलिस को पहले से कुछ जानकारी होनी चाहिए। तदनुसार तैयारी होनी चाहिए। ऐसा न हो पाने के भी कुछ कारण हैं। समस्त पुलिस बलों के साथ केंद्रीय पुलिस बलों में भी 30 प्रतिशत से ऊपर पद रिक्त हैं। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या भी न के बराबर है। इसके अलावा आधुनिक उपकरणों की भी कमी है। कई देशों में ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनके प्रयोग से हिंसक प्रदर्शनों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे फेस रिकगनिशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी। बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण के लिए स्टन गैस काफी सफल रहा है। अनियंत्रित भीड़ पर छिड़काव से असहनीय दुर्गंध आती है। इससे केवल कुछ ही देर के लिए व्यक्ति मूर्छा की स्थिति में आता है, लेकिन उसे कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचती। हमारी पुलिस को ऐसे उपकरणों और तकनीक की सख्त दरकार है। यदि पुलिस इनसे लैस होकर मैदान में उतरें तो बलवाई उस पर भारी नहीं पड़ेंगे। अभी वे भारी पड़ जा रहे हैं।

अवधेश राजपूत

देश में एक दंगा नियंत्रण योजना पहले से मौजूद है। इसके प्रभावी इस्तेमाल से भी हिंसक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बस जरूरत है कि सभी पुलिस कर्मी उसके बारे में जानकारी रखें। इसके लिए पुलिसकर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज फैलाने के बड़े माध्यम बन गए हैं। इस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में गहन चिंतन की आवश्यकता है। बीते वर्षों में पुलिस सुधार के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन यही कहा जा सकता है कि चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की 2006 की व्यवस्था के उपरांत किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई गई। पुलिस सुधार लागू करने के साथ ही इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर ही की जाए।

हालांकि वर्तमान समय में भी पुलिस के पास ऐसे कुछ उपाय हैं जिसका इस्तेमाल कर वह हालात काबू में कर सकती है। जैसे पुलिस एक्ट 1861 की आलोचना होती रहती है, लेकिन इसकी धारा 15 और धारा 15ए काफी प्रभावी हैं। धारा 15 के तहत हिंसक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल का नियुक्ति की जाती है। वहीं धारा 15ए के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में पुलिस बल की नियुक्ति पर जो खर्च आता है उसकी पूरी भरपाई उपद्रवियों से की जाती है। अगर हिंसा और आगजनी से सार्वजनिक संपत्ति की हानि हुई हो तो यह प्रावधान कहता है कि गुंडा तत्वों को चिन्हित कर उनसे जुर्माना वसूला जाना चाहिए ताकि क्षति की भरपाई की जा सके। हिंसा और दंगे के दौरान पुलिस के नेतृत्व का भी बड़ा महत्व है। जहां पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जाते हैं वहां कमोबेश स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। जिस प्रकार लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने अंततोगत्वा घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस बल का नेतृत्व किया वह हर जगह होना चाहिए। उत्तेजना भरे माहौल में कम्युनिटी पुलिसिंग और शांति समितियों के माध्यम से जनता को विश्वास में लेने से भी फायदा होता है। हिंसक घटनाओं के दौर में पुराने क्रियाशील दंगाइयों की पहचान कर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। ऐसे लोग गिने चुने ही होते हैं। इन पर प्रभावी कार्रवाई हो जाए तो हिंसा का खतरा टल जाता है।

पुलिस को सक्षम बनाने के उपायों पर अमल की जरूरत तो है ही, लेकिन विभिन्न दलों द्वारा नागरिकता कानून को लेकर जिस प्रकार भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है वह भी मौजूदा हिंसा की एक वजह है। एक मुख्यमंत्री सुझाव दे रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एक और राष्ट्रीय स्तर के नेता कहते हैं कि सरकार को धारा 144 लगाने का अधिकार नहीं। कुल मिलाकर हर कोई मनमाने बयान दे रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन नेताओं को समाज को सही जानकारी देनी चाहिए वही जनता और विशेषकर विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अशांति और अराजकता के इस वातावरण में जब कई नेतागण गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं तब कुछ अनुकरणीय दृष्टांत भी प्रकाश में आए हैं। अहमदाबाद में शाह आलम क्षेत्र में जब पुलिस को दंगाइयों ने घेर लिया तो सात मुस्लिम युवाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पथराव झेल रहे पुलिसकर्मियों को बचाया। इन युवाओं ने जिस साहस का परिचय देकर अपने नागरिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया वह वास्तव में अनुकरणीय है। ऐसे युवाओं का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, न कि उनकी जो मिथ्या जानकारी से जन सामान्य को उकसाकर पुलिस और साथ ही कानून एवं व्यवस्था को संकट में डाल रहे हैं।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे हैं)

response@jagran.com

अल्पसंख्यकों से खाली होता बांग्लादेश

कृपाशंकर चौबे

बांग्लादेश का शत्रु संपत्ति संबंधी कानून वहां के अल्पसंख्यकों को जमीन-जायदाद से बेदखल करने का औजार बना हुआ है

नागरिकता कानून पर बहस, हंगामे और हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि वह भारत गए बांग्लादेशियों को वापस लेने को तैयार है, किंतु यथार्थ यह है कि कम से कम कोई अल्पसंख्यक शरणार्थी तो वहां लौटना ही नहीं चाहता। उसे पता है कि अल्पसंख्यक होने के कारण उसे वापस लौटते ही नारकीय जीवन की यातना सहनी पड़ेगी। उस पार से इस पार आने के बाद वे दिहाड़ी मजदूरी कर भी सम्मानपूर्वक जीवन जी लेते हैं, किंतु उस पार उन्हें अल्पसंख्यक होने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वास्तव में जब किसी भी देश का विभाजन होता है तो लकीर केवल सीमा पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर भी खिंचती है। देश विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं का जो भयावह उत्पीड़न होना शुरू हुआ वह एक यथार्थ है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक उत्पीड़न के अमूमन शिकार निरीह हिंदू और बौद्ध हैं। उत्पीड़न से बचने के लिए वे पलायन कर भारत में शरण लेते रहे हैं। इन निरीह लोगों की पीड़ा को तस्लीमा नसरीन समेत कई अन्य बांग्लादेशी लेखकों ने अपनी रचनाओं में बयां की है। बांग्लादेशी लेखक सलाम आजाद ने अपनी किताब बांग्लादेशे विपन्न अल्पसंख्यक और हिंदू संप्रदाय केनो देश त्याग कोरछे (बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं हिंदू) में जो आंकड़े दिए हैं वे भयावह तस्वीर पेश करते हैं। सलाम आजाद ने लिखा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1974 से 1991 के बीच प्रतिदिन औसतन 475 लोग यानी हर साल एक लाख 73 हजार 375 हिंदू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने पर बाध्य हुए। यदि उनका पलायन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की आबादी सवा तीन करोड़ होती।

1941 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 28 प्रतिशत थी, जो 1951 में 22 प्रतिशत, 1961 में 18.5 प्रतिशत, 1974 में 13.5 प्रतिशत, 1981 में 12.13 प्रतिशत, 1991 में 11.6 प्रतिशत, 2001 में 9.6 प्रतिशत और 2011 में घटकर 8.2 प्रतिशत हो गई। अभी हिंदुओं की आबादी सवा करोड़ है, किंतु आशंका जताई जा रही कि 2030-35 तक बांग्लादेश पूरी तरह अल्पसंख्यकों से खाली हो सकता है। ऐसा होने का मतलब है बांग्लादेश का हिंदू विहीन होना। इस बारे में सलाम आजाद लिखते हैं, 'बांग्लादेशी हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने के मकसद से ही उन पर अत्याचार किए जाते हैं। पिता के सामने बेटी और मां-बेटी के साथ दुष्कर्म

किया जाता है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के पास तीन ही रास्ते हैं-या तो वे आत्महत्या कर लें या मुसलमान बन जाएं या फिर पलायन कर जाएं। तीसरा विकल्प सहूलियत वाला है।' यही स्थिति पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की भी है।

बांग्लादेश में शत्रु संपत्ति संबंधी कानून भी अल्पसंख्यकों के लिए काल साबित हो रहा है। वास्तव में बांग्लादेश से हिंदुओं और बौद्धों के पलायन की सबसे बड़ी वजहों में एक यही कानून है। 1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था। इस कानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश में शत्रु संपत्ति अधिनियम वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन-जायदाद से बेदखल करने का औजार बना हुआ है। इस कानून की वजह से बांग्लादेश में रह रहे लाखों अल्पसंख्यकों को अपनी जमीन गंवानी पड़ी। 'डिप्रिवेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश लिविंग विथ वेस्टेड प्रॉपर्टी' किताब की प्रस्तावना में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम रब्बानी और ढाका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अबुल बरकत ने लिखा है, 'शत्रु संपत्ति कानून की वजह से देश के 1965 से 2006 के दौरान हिंदुओं की 26 लाख एकड़ जमीन दूसरों के कब्जे में चली गई। इस कानून के कारण चटगांव में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की 22 फीसद भूमि उनके हाथ से निकल गई।

1971 में बांग्लादेश बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान ने 'एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट' का नाम बदलकर 'वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट' कर दिया। संसद में उन्होंने कहा था, 'बांग्लादेश के निर्माण में भारत के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, अब जब बांग्लादेश और भारत आपस में बंधु हैं तो शत्रु संपत्ति कानून का कोई औचित्य नहीं।' 1975 में उनकी हत्या के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के कल्याण का स्वप्न टूट गया। अवामी लीग के बाद दो दशकों से अधिक समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जातीय पार्टी की सरकारें रहीं। उस दौरान वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों को उनकी अचल संपत्तियों से तेजी से बेदखल किया गया। जब 1996 में अवामी लीग सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2001 में 'वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट' का नाम 'वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट' कर दिया। बदले नाम वाले इस कानून का उद्देश्य बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को उनकी अचल संपत्तियां वापस दिलाना था, किंतु अक्टूबर 2001 में बांग्लादेश संसद के चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोबारा सत्ता में आई और प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार ने 'वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट' में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संशोधित किए गए संशोधन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2009 में अवामी लीग फिर सत्ता में आई और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने 'वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट' को पुनः प्रभावी बनाने का निर्णय किया। इस समय वेस्टेड प्रॉपर्टी रिटर्न एक्ट से जुड़े करीब 10 लाख अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के मुकदमें बांग्लादेश की अदालतों में लंबित हैं। इसके कारण अल्पसंख्यकों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे पहले की तरह सताए जा रहे। उनका योजनाबद्ध तरीके से उत्पीड़न इसीलिए किया जाता है ताकि वे अपनी घर-जमीन छोड़कर भागें तो उस पर कब्जा किया जा सके।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईमानदारी

ईमानदारी का अर्थ होता है-सैकड़ों-हजारों मनकों में भी हीरा की तरह चमकने-दमकने वाला मानवीय व्यक्तित्व। ईमानदारी मानवीय गुण है। बेईमानी शैतानियत है। जब व्यक्ति ईमानदारी का आदर्शमय पिंजड़ा तोड़कर बेईमानी का आदर्श विहिन खंजर हाथ में लेता है तो उसके घर से लक्ष्मी अपना स्थान रिक्त कर देती हैं। ईमानदारी ही जीवन का सार है। ईमानदारी महानता का धर्म है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है।

यह मानवीय नियम आदर्श की सीमा को सुशोभित करता है। अगर व्यक्ति इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो उसकी यश, कीर्ति का हनन होता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। उसके हृदय में ईमानदारी के समाप्त होते ही द्वेष, हिंसा का दुर्गुण छा जाता है। तब ईश्वरीय संरक्षण का अभाव हो जाता है। उसको ईश अवलंबन भी नहीं रह जाता है। व्यक्ति खुद ही बेइमानी से अपना व्यक्तित्व बिगाड़ता है और खुद ही ईमानदारी से बनाता है। इसमें ईश्वर का क्या गुण-दोष है? ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता पूर्ण रूप में दे रखी है। अगर आप ईश्वर के नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो इस संसार में ईश्वर की ओर से पारितोषिक के रूप में पग-पग पर उत्थान, सहयोग, प्रेम, यश, सम्मान प्राप्त होता रहेगा। ईश्वर ईमानदारी का तोहफा देने में तनिक भी कटौती नहीं करता है।

मानवीय मस्तिष्क सिर्फ क्षणिक फायदे के लोभ में बेईमानी की राह पर चलने की भूल करने से हिचकता नहीं है। इस कारण उसे दंड भुगतना पड़ता है। ऐसा ईश्वर अगर विधान न रचे तो उसकी गरिमा भी नष्ट हो जाएगी। मनुष्य की सुरक्षा और प्रकृति की शोभा को बरकरार रखने के लिए ईश्वर सबको ईमानदार बनने की प्रेरणा देता है, ताकि सबकी भलाई हो, सबका कल्याण हो। ईमानदारी के गुण के कारण ही मन में आनंद की क्षण-क्षण अनुभूति होती है। ईमानदारी का गुण जीवन के लिए पहरेदारी है। ईमानदारी का पहरा ही जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। विवेक को जागृत रखता है।

मुकेश ऋषि

स्वर्णरेखा की क्षीण होती जीवनरेखा

फिर से

खेती, पर्यटन और धार्मिक नजरिये से संभावनाओं से भरी स्वर्णरेखा नदी आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है

हर नदी के पास एक कहानी होती है। स्वर्णरेखा नदी के पास भी है। झारखंड की यह नदी, अपने नाम के मुताबिक ही सच में सोना उगलती है। यह किस्सा स्वर्णरेखा के पास लोकमानस में गहराई से रचा-बसा है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहां आकर रहे थे। स्वर्णरेखा के उद्गम का नाम रानीचुआं इसलिए पड़ा, क्योंकि एकबार जब इस निर्जन इलाके में रानी द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मारकर इसी स्थल से पानी निकाला था, जो आज भी मौजूद है। वैसे भी मिथक सच या झूठ के दायरे से वह थोड़े बाहर होते हैं। यह पता नहीं कि पांडु गांव, पांडवों के अज्ञातवास और अर्जुन के बाण से निर्मित रानीचुआं की कहानी कितनी सच है? लेकिन यह मिथक कतई नहीं है कि स्वर्णरेखा झारखंड की गंगा की तरह है और गंगा की तरह ही इसको देखना अब रोमांचकारी कम और निराशाजनक ज्यादा हो गया है।

स्वर्णरेखा नदी से सोना निकलता जरूर है, पर यह कोई नहीं जानता कि इसमें सोना आता कहां से है। स्वर्णरेखा नदी में स्वर्णकणों के मिलने के कारण इस क्षेत्र के स्वर्णकारों के लिए इस नदी की खास अहमियत है। किंवदंती है कि इस इलाके पर राज करने वाले नागवंशी राजाओं पर जब मुगल शासकों ने आक्रमण किया तो नागवंशी रानी ने अपने स्वर्णाभूषणों को इस नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसके तेज धार से आभूषण स्वर्णकणों में बदल गए और आज भी प्रवाहमान हैं। आज भी आप जाएं तो नदी में सूप लिए जगह-जगह खड़ी महिलाएं दिख जाएंगी। इलाके के करीब आधा दर्जन गांवों के परिवार इस नदी से निकलने वाले सोने पर निर्भर हैं।

395 किलोमीटर लंबी यह बरसाती नदी देश की सबसे छोटी अंतरराज्यीय (कई राज्यों से होकर बहने वाली) नदी है, जिसके बेसिन का क्षेत्रफल करीब 19 हजार वर्ग किमी है। यह रांची, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) और बालासोर (ओडिशा) से होकर बहती है। जानकारों का कहना है कि यह नदी अब सूखने लगी है और इसके उद्गम स्थल पर यह एक नाला होकर रह गई है। इस नदी में कम होते पानी की वजह से भूजल स्तर भी तेजी से गिरता जा रहा है। काटे जा रहे जंगलों की वजह से मृदा अपरदन भी बढ़ गया है।

इस नदी की बेसिन में कई तरह के खनिज हैं, पर इन सबने नदी की सूरत बिगाड़ दी। खनन और धातु प्रसंस्करण उद्योगों ने नदी को प्रदूषित करना भी शुरू कर दिया है। अब नदी के पानी में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के साथ-साथ रेडियोसक्रिय तत्वों की मौजूदगी भी है। खासकर खुले खदानों से बहकर आए अयस्क इस नदी की सांस घोंट रहे हैं। स्थिति यह है कि स्वर्णरेखा नदी का पानी जानवरों और मछलियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जानवरों और मछलियों के लिए पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 1.2 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, जबकि 7.0 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है। इसकी वजह से काफी संख्या में मछलियां नदी में मर रही हैं। इसके साथ ही साथ जानवरों को भी कई तरह की बीमारियां हो रही हैं।

(साभार : गुस्ताख ब्लॉग में मंजीत ठाकुर)

नैतिक शिक्षा की दरकार

दुष्कर्म पर नेताओं का दिखावटी आक्रोश शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगदीप एस छोकर ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार को महिला अपराधों में कमी के लिए बेहद आवश्यक बताया है। यह विचार से ही अव्यावहारिक कदम प्रतीत होता है, क्योंकि देखा जाए तो आज दिनोंदिन राजनीतिक दलों की आकांक्षा, कार्यशैली एवं उद्देश्यों में बदलाव नजर आ रहे हैं। ये अब लोकतंत्र की धूरी नहीं, बल्कि स्वार्थ सिद्धि के प्रमुख साधन बन गए हैं जो लोकलुभावन मुखौटे और राजनीति के माध्यम से केवल अपना हित साधते हैं। इसमें जनता के लिए नीति कम और राज करने की लालसा अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में भला कौन राजनीतिक पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। यह बात निराधार नहीं कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक प्रत्याशी समाज का प्रतिबिंब होता है जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में केवल इन प्रत्याशियों को राजनीति से बेदखल करना समस्या का मूल एवं अंतिम समाधान नहीं है। आकड़ें बताते हैं कि 17वीं लोकसभा चुनाव में 542 सदस्यों में से लगभग 233 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। ऐसे में इन अपराधों की मूल जड़ में जाना अति आवश्यक हो जाता है। अब्दुल कलाम कहा करते थे 'मनुष्य अपनी सोच से बढ़कर कुछ भी नहीं है'। नतीजतन यदि हमारी सोच अच्छी हो और उस पर नैतिकता का प्रभाव हो तो अवश्य ही अपराधों से बचा जा सकता है, क्योंकि अपराध हमारी विषाक्त मानसिकता की उपज है, जो कहीं न कहीं हमारी विकृत शिक्षा प्रणाली की भी देन है, जहां बच्चों के पाठ्यक्रम में नैतिक विषय को शामिल करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अतः समाधान यही है कि समाज में नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जाए।

मेलबाक्स

इसके लिए बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

बिन्नी कुमारी, सारण

आंदोलन में दिखे गांधीवाद

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत गांधी का देश है। आज के समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता सरकार और आम जनता दोनों के लिए बढ़ गई है। महात्मा गांधी ने सिखाया था कि विरोध करने के लिए सत्य, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह, अहिंसात्मक साधनों का क्या महत्व है। हम जनता को सरकार के किसी भी नीति एवं कानून के खिलाफ आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इन्हीं आंदोलनों से लोकतंत्र मजबूत होता है, सरकार की तानाशाही रुकती है और आम जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा पाती है। लेकिन लगता है कि हम आंदोलन के तरीके और गांधीवाद के सिद्धांत दोनों को भूल गए हैं, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में हिंसा हुई इस बात को सिद्ध करती है। हमें आंदोलन करने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध और आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से ठीक नहीं है। आम जनता को इस विरोध और आंदोलन से परेशान न करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई में देखने को मिला, वहां पर 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन और विरोध हुआ, लेकिन इस विरोध को आम जनता ने शांतिपूर्वक तरीके से किया और पुलिस पर पथराव करने के बजाय उन्होंने पुलिस का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इस कारण हम आंदोलन इस तरीके से करें जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों और आम जनता सरकार तक अपनी बात भी रख सके। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है और न ही सभ्यता प्रदर्शित होती है, इसलिए गांधी जी के बताए मार्ग पर चलना सबसे उचित है।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

दलित पुजारी

एक तरफ देश में नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह खबर पढ़कर सुकून मिलता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर का पुजारी कोई दलित हो सकता है। अगर राम मंदिर का पुजारी कोई दलित होता है तो यह एक सराहनीय एवं बेमिसाल कदम होगा। आज राष्ट्र को तोड़ने वाले की नहीं, जोड़ने वाले की ज्यादा जरूरत है। यूं भी आज अपने निजी स्वार्थों की खातिर तोड़ने एवं फूट डालने वाले ज्यादा हैं, लेकिन ऐसे अद्वितीय कदमों से जन-जन को जोड़ा जा सकता है।

mahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

गंभीर मसले पर बेतुकी बात

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

ममता बनर्जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी में हस्तक्षेप की मांग करना बहुत ही अनुचित है, क्योंकि नागरिकता की पहचान के सिलसिले में जो कानून वैधानिक रूप से अस्तित्व में आया है, वह मूल भारतीय नागरिक और गैर-भारतीय लोगों की पहचान के लिए है। संयुक्त राष्ट्र के प्राविधानों में भी यह व्यवस्था नहीं है कि कोई देश घुसपैठियों को नागरिकता देने के लिए बाध्यकारी है। कोई भी देश नागरिकता के नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गुरुवार को कोलकाता में रैली की अगुवाई करतीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आइएएनएस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर हैरानी में डालने वाला बेतुका बयान दिया है। ममता ने कहा है कि भाजपा में हिम्मत है तो वह सीएए और एनआरसी पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की निगरानी में जनमत संग्रह देश में कराए। यदि यह जनमत सरकार के विरुद्ध जाता है तो नरेंद्र मोदी सरकार इस्तीफा दे। इसी तरह के हस्तक्षेप की जम्मू-कश्मीर में जरूरत पाकिस्तान जता रहा है।

यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने जता दिया कि तीसरे पक्ष का दखल किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। सरकार का यह दो टूक रुख इसलिए जरूरी था, क्योंकि उसने नागरिकता कानून में जो संशोधन किया है, वे संविधान की परिधि में लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित हुए हैं, न कि थोपे गए हैं। हालांकि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों को यह एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसकी ओट में हाशिये पर पड़े ये दल भारतीय मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रख संजीवनी पाना चाहते हैं।

भारत में नागरिकता के अधिकार 'नागरिकता अधिनियम-1955' के माध्यम से तय किए गए हैं। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को मंजूर किया था, तब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पांच से नौ को तुरंत लागू कर दिया गया था। इसके पहले कौन भारतीय नागरिक है, इसकी पहचान चिन्हित नहीं थी। इसके पहले हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, इसलिए 'ब्रिटिश नागरिकता कानून' के तहत ब्रिटिश प्रजा थे। जो लोग सामंती राज व्यवस्था के अंतर्गत थे, उन्हें भी ब्रिटिश सरंक्षण प्राप्त नागरिकों का दर्जा प्राप्त था। देश बंटवारे के समय लाखों लोग इधर से उधर हुए, इसलिए नागरिकता निर्धारण की समस्या, बड़े संकट के रूप में सामने आई। लिहाजा नागरिकता की नियमावली को तय करने में दो वर्ष लगे। साफ है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर और उनके सहयोगियों ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय किए। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संसद नागरिकता के अधिकार को निर्धारित कर सकती है।

देश की आजादी से लेकर 1971 में बांग्लादेश बनने तक भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और युगांडा से बड़ी संख्या में लोग गैर-कानूनी ढंग से घुसे चले आए। इस संकट से निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में इस कानून में संशोधन किया गया। नतीजतन भारतीय नागरिकता प्राप्त करना और कठिन हो गया। इस कानून में सबसे अहम बदलाव वर्ष 2003 और 2005 में किए गए। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। एनआरसी असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए वजूद में लाई गई थी। इसका मकसद ही असम में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों व बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था। इसकी पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चली। असम की एक बड़ी आबादी को इस सूची में जगह नहीं मिली जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस पर विवाद खत्म होने से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन विधेयक ले आए और पूरे देश में एनआरसी का प्राविधान करने की बात की, जो वर्तमान बवाल का कारण बना है।

दरअसल एनआरसी में ऐसे मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर करने का प्राविधान है, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं। यदि ये घुसपैठिये बाहर हो जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल का सूपड़ा साफ हो सकता है। वैसे भी राज्य में 18 लोकसभा सीटें जीकर भाजपा ने तृणमूल की जड़ों में मट्ठा घोल दिया है, इसलिए ममता ने अपना वर्चस्व बचाए रखने की लड़ाई लड़ते-लड़ते संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत-संग्रह की बेतुकी मांग करने की भूल कर दी। दूसरी तरफ अस्तित्व खो रहे वामदल भी हिंसा की इस आंच में राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकने लग गए। इन दलों की शह पर देश में हिंसा और आगजनी का माहौल बना हुआ है। नागरिकता कानून के विरुद्ध जो याचिकाएं इसके खात्मे की मंशा से दायर की गई थीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून को संवैधानिक मानते हुए इसे घुसपैठियों की पहचान के लिए आवश्यक भी माना है।

इस मुद्दे पर मनमोहन सिंह की भूमिका समझ से परे है। एनआरसी लागू करने का काम सबसे ज्यादा उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है। मई 2005 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और आसू (संपूर्ण असम छात्र संगठन) के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें राजीव गांधी के समय 1985 में असम समझौते के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए एनआरसी को अद्यतन करने पर सहमति बनी। इसे भी जब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तब 'असम पब्लिक वर्क्स' नामक स्वयंसेवी संगठन ने शीर्ष न्यायालय में याचिका लगाकर मांग की, कि उन प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं, जिन्होंने भारतीय नागरिकता के प्रमाणित दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। इसके साथ ही, इसी याचिका में एनआरसी प्रक्रिया शुरू करने का निवेदन किया गया। यह पहला अवसर था, जब याचिका न्यायालय ने स्वीकार की और एनआरसी पर प्रक्रिया शुरू होने की खिड़की खोल दी।

किसी देश में वहां के लोगों को नागरिकता देने की दृष्टि से हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र कोई असरकारी भूमिका निभाने में असफल रहा है। इस संबंध में म्यांमार को उदाहरण के तौर पर देखें तो यहां से वर्ष 2016 में करीब 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को सेना ने बंदूक की नोक पर खदेड़ा जिनमें से सात लाख को बांग्लादेश ने उदारता बरतते हुए शरण तो दी, लेकिन नागरिकता नहीं दी। इस घटनाक्रम को घटे करीब चार साल हो रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एक भी रोहिंग्या की वापसी म्यांमार में नहीं करा पाया है। इस मामले और अन्य मामलों में कोई प्रभावी परिणाम नहीं दे पाने के कारण संयुक्त राष्ट्र को अप्रासंगिक संगठन माना जाने लगा है। लिहाजा ममता बनर्जी ने यह मांग करके जता दिया है कि वे राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बेहद कठिन दुविधा के दौर से गुजर रही हैं। यह बेतुका बयान उनकी राजनीतिक धार को कुंद कर सकता है।

बेकाबू न होने पाए अराजकता

डॉ. शिव कुमार राय
वरिष्ठ पत्रकार

नए भारत के निर्माण की बात हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के निवेशकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि भारत में निवेश सुरक्षित है, लेकिन मुट्ठी भर लोग किसी भी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को तहस-नहस करते हैं, यातायात व्यवस्था को बदहाल बना देते हैं।

कभी नागरिकता कानून के नाम पर तो कभी एनआरसी के नाम पर तो कभी किसी शैक्षणिक संस्थान में फीस बढ़ोतरी के नाम पर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। कभी इस तरह के आंदोलन या प्रदर्शन को भीड़ के मनोविज्ञान से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में चौंकाने वाली बात यह है कि हिंसक प्रदर्शन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं हैं। यह एक सुनियोजित साजिश है जिसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें शामिल हैं। ये लोग किसी मुद्दे की आड़ में मजहबी उन्माद फैलाने की कोशिश कर देश को अस्थिर करना चाहते हैं।

अविभाजित भारत में रहने वाले ऐसे लाखों लोग थे जो 1947 से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात करें तो यहां का संविधान उन्हें विशिष्ट धार्मिक राज्य बनाता है। इन मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदाय से जुड़े अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के पहले नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक किसी भी अवैध अप्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन कर इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का फैसला लिया है।

उपरोक्त तीनों देशों के अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो उन्हें अपने धर्म के पालन और उसमें आस्था रखने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनमें से बहुत से लोग भारत में शरण के लिए आए और अब ये लोग यहीं रहना चाहते हैं। इन लोगों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है तो कई लोगों के पासपोर्ट की अवधि भी खत्म हो गई है। नागरिकता कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि यह संशोधन मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संविधान के इस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हैं और वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और इस वजह से उन्हें धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार नहीं माना जा सकता। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि दूसरे समुदाय के आवेदनों पर अलग अलग मामले में विचार किया जाएगा।

इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शन और हिंसा पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि उपद्रवियों की संपत्ति जब्त कर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इन प्रदर्शनों पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने भी हाल ही में कहा था कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इन हालात को देखते हुए देश में सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम 1984 को और भी अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल चारों तरफ सीसीटीवी से लैस होने चाहिए ताकि प्रदर्शन के दौरान अगर कोई उपद्रवी वहां नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी पहचान की जा सके। प्रदर्शन और विरोध के नाम पर कोई भी गुट या संगठन, लोकतांत्रिक परंपराओं की दुहाई देकर गैर लोकतांत्रिक और राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर सकता।

खरी-खरी

संविधान के छाते में अभिव्यक्ति का तांडव

सुधीर कुमार चौधरी

संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान की है। हमें विरोध करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह इस विषय पर मौन है कि अभिव्यक्ति कैसे की जानी चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्ति के तरीकों पर प्रकाश ही नहीं डाला। शायद उन्हें यह कल्पना नहीं रही होगी कि आने वाली पीढ़ी अभिव्यक्ति के कैसे-कैसे तरीके इजाद कर लेगी। अब विरोध की अभिव्यक्ति विचार और स्वर से नहीं, आग और हिंसा से होती है। ज्वलनशील राजनीति इस आग का ईंधन बन जाती है। इसकी आग में बसें, रेल और अन्य वाहन भस्म किए जाते हैं। जितना ज्यादा विरोध, उतनी ज्यादा आग। जितनी ज्यादा आग, उतनी ज्यादा टीआरपी।

कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी जंगल में हांका लगा देते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। संविधान संकट में है। यह सुनते ही तमाम भेड़िये दौड़ पड़ते हैं। तथाकथित खतरे का मुकाबला करने के लिए सारे देशखोर इकट्ठा हो जाते हैं। इंसानी मांस की गंध इन्हें मदमस्त कर देती है। लाशों पर खड़े होकर ये विरोध का हुआं-हुआं शोर करते हैं और देश को धुआं-धुआं कर देते हैं। दहकती आग इनके कलेजों को ठंडक पहुंचाती है। निर्दोषों की चीख-पुकार इनका हौसला बढ़ाती है। विरोध की आग में भस्म हुई सार्वजनिक संपत्ति में इन्हें पौरुष का प्रमाण पत्र दिखता है।

अभिव्यक्ति अब प्रगतिशील हो चुकी है। सामान्यतः यह राजनीति की कोख से जन्मती है। अब इसमें आक्रामकता की बारूद भी घुल गई है। मर्यादा व नियंत्रण से इसका संबंध विच्छेद हो चुका है। यह जवाबदेही से मुक्त हो गई है। यह जब उन्माद के उफान पर होती है, तो मुद्दे गौण हो जाते हैं। यह मुद्दों की छाती पर पांव रख शान से आग की लपटें निहारती है। इसकी रगों में हिंसा दौड़ने लगती है। विध्वंस इसकी प्रकृति बन जाता है। काले धुएं में घिरी अभिव्यक्ति के अट्टहास से दिशाएं सहम उठती हैं। राजनीति इस पर गर्व कर मंद-मंद मुस्काती है। व्यवस्था की लाठी-गोली और आदमखोरों की शैतानी हवस के बीच निर्दोषों की चीत्कारें शून्य में गुम हो जाती हैं। अभिव्यक्ति की आग में संवेदनाएं स्वाहा हो जाती हैं। मानवता भून दी जाती है। अनुभूतियां रक्तरंजित हो जाती हैं। सहिष्णुता सुलग उठती है। विवेक विक्षिप्त हो जाता है। शायद प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यह सब जरूरी होता है।

ट्वीट-ट्वीट

नफरत, हिंसा, आगजनी और सड़कों पर कोहराम, हर एक माथे पर चिंता की लकीर, क्या यही हैं आपके अच्छे दिन?

आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

जो लोग लोकतंत्र में विरोध की स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्या उन लोगों को उस विरोध में जो जिम्मेदारियां कंधों पर होती हैं उसका अहसास है? पहले कायदे से विरोध करना तो सीख लें। उसके बाद पूछिएगा कि प्रदर्शन करने को क्यों नहीं मिल रहा?

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

मैं सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता हूं, लेकिन किसी को दोष देने के बजाय हमें इसकी मुख्य वजह पर फोकस करना चाहिए। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि वह असंतुष्टों की सुने, चर्चा करे। मैंने हमेशा देश को पहले रखा है और सबको ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ क्योंकि, कभी-कभी खुद के दांत भी, जीभ को काट लेते हैं।

अनुपम खेर@AnupamPKher

युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है ब्रह्मोस

शशांक द्विवेदी
डायरेक्टर,
मेवाड़ यूनिवर्सिटी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर से दो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को जमीन और हवाई प्लेटफार्म से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें अधिकांश उपकरण स्वदेशी थे। इसमें मिसाइल एयर फ्रेम, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को डीआरडीओ ने डिजाइन किया था। पहले जमीन पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल को मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में लॉन्च कॉम्प्लेक्स-3 से परीक्षण किया गया। मिसाइल का दूसरा प्रक्षेपण भारतीय वायु सेना द्वारा एसयू-30 एमकेआइ से किया गया।

ब्रह्मोस मिसाइल नौसेना और वायुसेना में पहले ही शामिल है और अब इसे थल सेना के बेड़े में भी शामिल किया जा सकता है। नए संस्करण का कई अहम उपकरण देश में ही विकसित किए गए हैं। वैसे ब्रह्मोस को भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ब्रह्मोस दुनिया में अपनी तरह की इकलौती क्रूज मिसाइल है जो सुपरसॉनिक स्पीड से दागी जा सकती है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के अलग-अलग संस्करण बनाए गए हैं। थल सेना, वायु सेना और नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ब्रह्मोस को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल माना जा रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार से लगभग तीन गुना ज्यादा है। दुश्मन की सीमा में घुसकर लक्ष्य भेदने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल इसी गति से हमला करने में सक्षम है।

ब्रह्मोस की रेंज लगभग 300 किमी है जिससे युद्ध के समय पड़ोसी देश में हर जगह प्रहार करना संभव नहीं है। भारत के पास नई जेनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल से अधिक

प्रतीकात्मक

रेंज की बैलेस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन ब्रह्मोस की खूबी यह है कि इससे खास टारगेट को तबाह किया जा सकता है। यह पाकिस्तान के साथ किसी टकराव की सूरत में गेम चेंजर साबित हो सकती है। बैलेस्टिक मिसाइल को आधी दूरी तक ही गाइड किया जा सकता है। वहीं क्रूज मिसाइल की पूरी रेंज गाइडेड होती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। यह बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान की तरह होगी जिसे बीच रास्ते में भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसे किसी भी एंगल से अटैक के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ब्रह्मोस से पहाड़ी इलाकों में बने आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया जा सकता है।

ब्रह्मोस एक सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और राडार से भी बची रहती है। इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से यानी कहीं से भी दागा जा सकता है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से तैयार हुई इस मिसाइल का जल और थल से पहले भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस तरह यह तय हो गया है कि ब्रह्मोस जल, थल और वायु से छोड़ी जा सकने वाली मिसाइल बन गई है। इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास मौजूद है। अधिकतम स्वदेशी उपकरणों से लैस ब्रह्मोस के नए संस्करण का इस्तेमाल थल सेना करती है।

थल सेना, वायु सेना और नौ सेना की जरूरतों के हिसाब से ब्रह्मोस को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का तीसरा सफल परीक्षण था जिसे भारतीय सेना की तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आवश्यकता के लिए विकसित किया जा रहा है।

इस कामयाबी के बाद भारत दुनिया में स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में भी सफल हुआ है। भारत इस मिसाइल के निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में लग गया है। एमटीसीआर का सदस्य बनने के बाद यह कार्य और आसान हो गया है। वियतनाम वर्ष 2011 से इस तेज गति की मिसाइल को खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। वह चीन से बचाव के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लेना चाहता है। इस अत्याधुनिक मिसाइल को बेचने के लिए भारत की नजर में वियतनाम के अलावा 15 अन्य देश भी हैं। वियतनाम के बाद फिलहाल जिन चार देशों से ब्रिक्री की बातचीत चल रही है उनमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली व ब्राजील हैं। शेष 11 देशों की सूची में फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड व संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। इन सभी देशों के साथ दक्षिण चीन सागर मसले पर चीन के साथ तनातनी चल रही है। दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस मिसाइल सर्वाधिक खतरनाक एवं प्रभावी शस्त्र प्रणाली है। यह ना तो राडार की पकड़ में आती है और ना ही दुश्मन इसे बीच में भेद सकता है। एक बार दागने के बाद लक्ष्य की तरफ बढ़ती इस मिसाइल को किसी भी अन्य मिसाइल या हथियार प्रणाली से रोक पाना लगभग असंभव है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

कुछ स्थानों पर बिगड़ते हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित करना सही है?

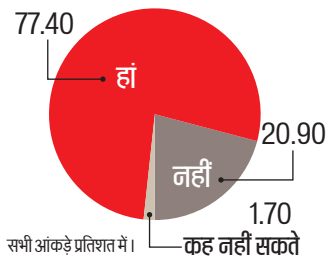

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नागरिकता संशोधन कानून का हिंसक विरोध राजनीतिक दुष्प्रचार का नतीजा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मनमोहन की मांग को किया गया चरितार्थ,
दंगे और फसाद का तब क्या है निहितार्थ?
तब क्या है निहितार्थ हो रहा क्यों हंगामा,
क्यों नेतागण आज रच रहे हैं यह ड्रामा??
विषय न जानें लोग हो रहा उनका दोहन,
तुम तो सच्ची बात आज बोलो मनमोहन!

- ओमप्रकाश तिवारी

चिंताजनक

थम नहीं रहे दुष्कर्म के मामले

केंद्र समेत राज्य सरकारों और अदालतों द्वारा तमाम तरह की सख्ती बरतने के बावजूद देश भर में दुष्कर्म के मामले थम नहीं रहे हैं, लिहाजा इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा

विजय कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

वाट्सएप पर एक आया एक वीडियो देख दिल रो पड़ा। एटा (उत्तर प्रदेश) में एक व्यक्ति अपनी 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को महिला अस्पताल जांच के लिए ले जा रहा है। उस व्यक्ति को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर भी उपलब्ध नहीं कराई गई। आरोप है कि लड़की को उसके 19 वर्षीय पड़ोसी लड़के ने अपने कमरे में घसीट लिया था और उसके साथ घंटों जबरन दुष्कर्म किया। लड़की ने बचने का प्रयास किया तो उसकी टांग टूट गई।

देश में निरंतर बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं में वीभत्सता की एक नई कड़ी जुड़ी नजर आ रही है। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दुष्कर्म के 32,559 मामले दर्ज हुए थे। इन घटनाओं ने सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतित कर दिया है। इसलिए उसने स्वतः ही 18 दिसंबर 2019 को यौन अपराधों की प्रतिक्रिया में आपराधिक न्याय व्यवस्था के मूल्यांकन हेतु संज्ञान लिया।

निर्भया कांड में एक दोषी की मौत की सजा की समीक्षा याचिका को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में देर से मिलने वाले न्याय ने जनता के मन में आंदोलन, खिन्नता और बेचैनी पैदा की है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की खंडपीठ ने सभी राज्यों व सभी उच्च न्यायालयों से सात फरवरी 2020 तक ऐसे मामलों में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इन रिपोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल संबंधी 12 पहलुओं (जिनमें 46 प्रश्न हैं) पर स्टेटस मांगा गया है, जैसे जांच, साक्ष्य एकत्र करना, फॉरेंसिक मेडिकल साक्ष्य, पीड़ित के बयान की रिकॉर्डिंग, ट्रायल की अवधि (दो माह होनी चाहिए), निर्भया फंड का उपयोग आदि।

जाहिर है इन आंकड़ों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट दुष्कर्मों को काबू में करने का मार्ग तलाशना चाह रहा है और यह भी जानना चाहता है कि निर्भया कांड के बाद जो आपराधिक कानून में संशोधन किया गया था, आखिर उसके इच्छित नतीजे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? यह काम तो देश की संसद का है, लेकिन वह ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करने की बजाय, जो घटना अधिक चर्चित हो जाए उस पर बस शोर मचाती है, जैसा हाल ही में हैदराबाद की घटना पर हुआ, जिसमें एक 27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक को सामूहिक दुष्कर्म के बाद जलाकर मार दिया गया था।

गौरतलब है कि निर्भया कांड के एक दोषी ने 2017 के निर्णय की समीक्षा का आग्रह किया था, जिसमें उसके लिए मौत की सजा की पुष्टि हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारों दोषियों की समीक्षा याचिकाएं ठुकरा दी गई हैं। पिछले वर्ष तीन अन्य की समीक्षा याचिकाएं ठुकराई गई थीं। अब इन दोषियों के पास फांसी से बचने का एकमात्र कानूनी विकल्प क्यूरेटिव याचिका है, जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट इन-चैंबर सुनता है या वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाएं।

यह अदालत दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चारों अपराधियों के लिए डेथ वारंट जारी करने का आग्रह किया गया है। अगर राष्ट्रपति के हाल के संबोधनों पर गौर किया जाए, जिनमें वह दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा की वकालत करते प्रतीत हुए, तो यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि चारों अभियुक्त दया याचिका से कुछ दिन पहले अपनी सांसें अवश्य बढ़ा लेंगे, लेकिन उनको राहत नहीं मिलेगी। इन्हें फांसी के फंदे पर लटकना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मृत्युदंड से दुष्कर्म के मामलों पर विराम लग जाएगा? कुछ दिन पहले बागपत की एक अदालत ने ट्रायल के पांच दिन में ही दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 18 दिसंबर को रामपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई, जिसने मई में छह वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी।

इस बीच भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को भी अदालत ने दोषी पाया है। लेकिन इससे भी दुष्कर्म की घटना में कमी नहीं आई है। अक्सर यह दलील दी जाती है कि मामले देर तक अदालतों में चलते रहते हैं, इसलिए देर से आए निर्णयों के कारण आशंकित अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं बैठ पाता। इस सिलसिले में निर्भया केस की मिसाल दी जाती है कि जनांदोलन के कारण यह हाई प्रोफाइल केस बना और सात साल हो गए हैं, फिर भी यह अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है, इसलिए कानून में डर का मूल्य नहीं रह जाता। ऊपर जो त्वरित निर्णयों की मिसालें दी गई हैं, उनसे भी कानून का खौफ नहीं बैठा है। इसका अर्थ यही है कि कमी कहीं और है, जहां अभी नजर नहीं जा पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, शायद उससे कोई रास्ता निकल आए।

यह सही है कि तारीख पर तारीख वाली मानसिकता पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता, लेकिन इस तथ्य पर गहन शोध की आवश्यकता है कि आखिर यौन हिंसा के मामलों में इतनी तेज वृद्धि क्यों हो रही है? इनको नियंत्रित करने के आखिर क्या तरीके हैं? इसमें सरकार व समाज की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए? कानून, जांच प्रक्रिया व अदालती प्रक्रिया में क्या सुधार व बदलाव लाए जाएं?

इस प्रकार के अन्य सवालों पर जब तक सही जवाब नहीं आएंगे, तब तक महिलाओं को घर व बाहर सुरक्षित रखना कठिन होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब सत्तारूढ़ दल और प्रशासनिक तंत्र पक्षपाती होते हुए एक प्रकार की हिंसा को होने देते हैं, अपराधियों को बचाते हैं तो अन्य प्रकार की हिंसाओं को रोकना भी कठिन हो जाता है। साथ ही सरकार का काम सरकार को ही करना चाहिए, अदालतों को नहीं।

इलस्ट्रेशन : अवधेश राजपूत

- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

2000 में 139.7 करोड़ लोग धूमपान करते थे दुनियाभर में। वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर 133.7 करोड़ रह गई। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सामने आई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 21 दिसंबर 2019

पेड़ों का मोल समझा तो बांटने लगे छांव

दिनेश शर्मा, चक्रधरपुर

30 साल में 30 हजार से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं कमल किशोर दास

नहीं कर सके पढ़ाई, लेकिन समाज को दे रहे पर्यावरण संरक्षण का सबक

झारखंड के चक्रधरपुर के ओटार गांव निवासी कमल किशोर दास अब 63 वर्ष के हो चुके हैं। गृहस्थ आश्रम में पहुंचने के बाद स्वाभाविक तौर पर बुजुर्ग अपने परिवार को छांव (छाया) देते हैं, लेकिन कमल अपने आसपास के इलाकों के हजारों लोगों के बीच पेड़ों की छांव बांट रहे हैं। तीन दशक पहले उनके मन में पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के प्रति चेतना का कमल खिला तो दिन-ब-दिन उसका आकार और दायरा बढ़ता ही चला गया। पौधरोपण का उनका जुनून ऐसा है कि 30 साल में 30 हजार से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, इनमें ज्यादातर अब पेड़ बन चुके हैं। प्रतिदिन सुबह वह अपने जुनून को मुकाम तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं और वापस लौटने से पहले कई पौधे लगा चुके होते हैं।

पर्यावरण संरक्षण

ट्री मैन के नाम से विख्यात कमल की कहानी थोड़ी अलग है। उनकी इच्छा खूब पढ़ाई करने की थी, लेकिन बचपन से ही आंखें कमजोर थीं। किताबों में दर्ज शब्द ठीक से नहीं दिखते थे। लिहाजा वह पढ़ाई नहीं कर सके। पर्यावरण संरक्षण का सबक मिला तो इतनी संतुष्टि मिली, मानो पढ़ाई पूरी हो गई। कमल बताते हैं कि युवावस्था में वह एक शवयात्रा के साथ श्मशान गए थे, जहां तेज गर्मी से सभी लोगों को परेशान होते देखा। लोग इधर-उधर पेड़ की छांव तलाशते नजर आए। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उस दिन से उन्होंने पौधरोपण करने की ठान ली, ताकि किसी को छाया के लिए भटकना ना पड़े, साथ ही पर्यावरण भी हरा-भरा और स्वास्थ्यकर बना रहे। आरंभ में उनके प्रयासों को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। कुछ लोग उपहास भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। आज वही लोग तारीफ करते हैं।

जहां भी खाली जमीन दिखी उसे हरा-भरा करने में जुट गए

कमल बताते हैं कि दर्जनों गांवों में उनके लगाए गए पौधे अब पेड़ बन चुके हैं। वह जहां भी खाली जमीन देखते हैं, उस पर पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। सरकारी और अनुपयोगी पड़ी जमीन पर भी वह अनुमति लेकर पौधरोपण में जुट जाते हैं। पौधों के बढ़ने तक लगातार उनकी देखभाल करते हैं। उनमें बाड़ भी लगाते हैं। चक्रधरपुर से होकर गुजरने वाली संजय नदी के वीरान पड़े तट पर उन्होंने हरियाली ला दी है। देसी प्रजाति के आम, नीम, पीपल, बरगद आदि पौधे लगाना उनकी प्राथमिकता होती है। कमल बताते हैं कि पौधों की देखभाल वह घर के सदस्य की तरह करते हैं। उनके इस अभियान में उनकी धर्मपत्नी शंखो देवी भी पूरा साथ देती हैं। चक्रधरपुर के थाना रोड, सोनुवा रोड, पदमपुर, थाना परिसर, वराहकाटा, आदि स्थानों पर कमल के लगाए गए पीपल, नीम, आम अर्जुन आदि के पौधे अब छायादार वृक्ष बन चुके हैं। कमल बताते हैं कि वह पेड़ों की पूजा करते हैं, उसका महत्व समझते हैं, इसलिए पेड़-पौधों और हरियाली का दायरा बढ़ाते रहना चाहते हैं। कोशिश है कि हर आयु के लोग इस अभियान में जुटें।

झारखंड के चक्रधरपुर के ओटार गांव निवासी पर्यावरणप्रेमी कमल किशोर दास पत्नी शंखो देवी के साथ। जागरण

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

चक्रधरपुर के सोनुआ रोड में कमल किशोर दास के लगाए गए पौधे अब बड़े पेड़ों के जंगल का रूप ले चुके हैं। जागरण

त्रेता युग की 'संजीवनी' को मिला नया जीवन

जागरण विशेष ▶ लेह-लद्दाख में मिलने वाला औषधीय गुणों से युक्त सोलो पौधा जीएनडीयू ने किया संरक्षित

सोलो का टिश्यू प्लांट किया तैयार, रेडिएशन के प्रभाव को भी खत्म करने में है सक्षम

हरीश शर्मा, अमृतसर

लेह-लद्दाख में सैनिकों और स्थानीय लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले सोलो पौधे को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (जीएनडीयू) के बायो टेक्नोलॉजी विभाग ने नया जीवन दिया है। बायो टेक्नोलॉजी विभाग ने लेह-लद्दाख में पाए जाने वाले इस सोलो नामक पौधे का टिश्यू प्लांट (बेबी ट्यूब प्लांट) तैयार किया है। इसका वैज्ञानिक नाम रोडियोला है।

इसके गुणों के कारण ही यह धारणा है कि शायद यही वह संजीवनी बूटी है, जिसका जिक्र रामायण में है। इसका उपयोग ऑक्सीजन की कमी होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने, कम दबाव वाले क्षेत्रों में रहने और बम या बायोकेमिकल से पैदा हुए रेडिएशन के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। यह बूटी शरीर को सीधे ऑक्सीजन ही नहीं देती, बल्कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देती है। इससे कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में भी सैनिक आराम से रह लेते हैं। चिंता की बात यह है कि यह बूटी भारत से लुप्त होने को है। मुख्य रूप से सोलो की तीन प्रजातियां हैं। सोलो कारपो (सफेद), सोलो मारपो (लाल) और सोलो सेरपो (पीला)। सफेद सोलो का मुख्य रूप से औषधीय उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है।

माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जीवित रहेगा टिश्यू प्लांट : जीएनडीयू के बायो टेक्नोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रताप कुमार ने बताया कि इस पौधे को तैयार करने के लिए लैब में लेह-लद्दाख जैसा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा गया। धूल रहित लैब में पौधे को करीब तीन साल तक पोषक तत्व दिए जाते रहे। यह पौधा भारत के अलावा साइबेरिया में भी पाया जाता हैं। अगर लद्दाख में यह पौधा पूरी तरह से लुप्त भी हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी लैब में यह सुरक्षित होगा। जीएनडीयू में तैयार इस पौधे की क्षमता लद्दाख में पाए जाने वाले पौधे से बेहतर है। इस रिसर्च को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी सराहा है। इसे जीएनडीयू ने भारत सरकार के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च (डीआइएचएआर) को सौंप दिया है।

2016 में मिला था प्रोजेक्ट : डॉ. प्रताप कुमार ने बताया कि लेह स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने 2016 में उन्हें यह प्रोजेक्ट सौंपा था। प्रोजेक्ट के तहत सोलो पौधे का कृत्रिम रूप तैयार करने का लक्ष्य मिला था। जीएनडीयू अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में लेह-लद्दाख से अधिक नजदीक है, इसलिए इसे यह प्रोजेक्ट मिला। मान्यता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए थे तब इसी बूटी के जरिये उन्हें बचाया जा सका था। डॉ. प्रताप कुमार बताते हैं कि अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि यह संजीवनी बूटी है या नहीं, लेकिन इसके औषधीय गुणों के कारण ही मान्यता है कि वह संजीवनी बूटी यही पौधा रहा होगा।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

बायो टेक्नोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. प्रताप कुमार (बाएं) अपने छात्रों डेवेन डोल्कर (मध्य में) और बलदेव सिंह के साथ सोलो का टिश्यू प्लांट दिखाते हुए। जागरण

सोलो पौधा जागरण

इस तरह होता है सोलो का इस्तेमाल

सोलो के पत्ते तुलसी के पत्ते की तरह चबाया जाता है। इसकी चाय भी बनती है। लद्दाख निवासी चिंता, थकान और अवसाद के उपचार को सोलो पौधे का साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

लद्दाख में की जा सकेगी खेती

लद्दाख का ही वातावरण सोलो पौधे के अनुकूल है। यह 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर पैदा होता है। टिश्यू प्लांट के जरिये लद्दाख में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। अभी तक यह पौधा खुद ही उगता है।

पानीपत के कालीन से सजेंगे यूरोप के गिरजाघर

पवन शर्मा, पानीपत

हरियाणा के पानीपत जिले के रेशमी कालीन इस साल यूरोप के देशों के गिरजाघरों की सजावट में भी चार चांद लगाएंगे। यहां से करीब डेढ़ महीने पहले ही समुद्री मार्ग से कालीन की खेप उन देशों के लिए रवाना कर दी गई थी, जहां से ऑर्डर मिले थे। वहीं कुछ देशों से मिले अर्जेंट ऑर्डर वायु मार्ग से पहुंचाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक मांग हस्तनिर्मित कालीन की रही। इससे उत्साहित शहर के कालीन कारोबारियों को उम्मीद है कि यूरोपीय देशों से मिले शानदार रिस्पांस की बदौलत एक बार फिर टेक्सटाइल कारोबार को रफ्तार मिलेगी।

पानीपत की 100 से अधिक इकाइयों में तैयार कालीन के कद्रदान यूं तो पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन ईसाई बहुल देशों में क्रिसमस और नव वर्ष पर कुछ बरसों में इनकी मांग बढ़ रही है। क्रिसमस और नए साल पर ज्यादातर गिरजाघरों में कारपेट बदलने की परंपरा है। बतौर गिफ्ट भी कालीन का आदान-प्रदान किया जाता है। इसी का फायदा भारतीय कालीन कारोबारियों को मिल रहा है। पानीपत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के भदोही और आगरा से भी साल-दर-साल यूरोपीय देशों में कालीन का निर्यात बढ़ा है।

हरियाणा कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान अनिल मित्तल बताते हैं कि सितंबर से ही यूरोप के देशों में क्रिसमस और नव वर्ष के लिए कालीन और अन्य टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात शुरू हो गया था। इनमें सबसे ज्यादा मांग हस्तनिर्मित कालीन की रही। उन्हें खुशी है कि सीजनल काम के बहाने ही सही, कम से कम अच्छे ऑर्डर तो मिले।

स्थानीय गिरजाघरों में भी तैयारी तेज : पानीपत के गिरजाघरों में भी क्रिसमस की तैयारी तेजी पर है। मॉडल टाउन स्थित करीब 60 वर्ष पुराने जॉन वेस्ले मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर फादर चार्ल्स डेविड कहते हैं कि यकीनन, यह जानकर बहुत गर्व होता है कि इस खास मौके पर पानीपत के कालीन केवल भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। पानीपत में भी चर्च को सजाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत प्रेयर हॉल में भव्य रेड कारपेट बिछाने की योजना है। इस बाबत, जल्द चर्च कमेटी से विचार-विमर्श किया जाएगा।

कहां किसकी मांग : विदेशी कद्रदान अपनी-अपनी पसंद के अनुरूप भारतीय कालीन और अन्य टेक्सटाइल उत्पादों का चयन करते हैं। मसलन, तकरीबन पूरे यूरोप में ऊन से बने और हस्तनिर्मित कालीन की अच्छी मांग है। अमेरिका में कॉटन निर्मित उत्पादों को तरजीह मिलती है। कुछ समय से चीन और टर्की से भी भारतीय कालीन उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी चुनौती मिल रही है।

पानीपत में हैंडमेड कालीन देखते ग्राहक। जागरण आर्काइव

बड़ा केंद्र है पानीपत

लंबे समय से पूरी दुनिया में पानीपत के कालीन कारोबार की धाक है। पानीपत क्लस्टर 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। यहां से तकरीबन 3000 करोड़ का निर्यात होता है। घरेलू बाजार में भी पानीपत की लगभग 1000 करोड़ की भागीदारी है। कालीन के अलावा, पानीपत दरी, मैट, टेपस्टरी, बेड कवर और अन्य हैंडलूम उत्पादों का भी निर्यात करता है। चीन व टर्की के मशीनी माल की मांग लगातार बढ़ने के बावजूद अपने परंपरागत हस्तनिर्मित कौशल के चलते पानीपत के उत्पाद भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं।

एनीमेशन से श्रीराम के व्यक्तित्व को जानेगी नई पीढ़ी

प्रवीण तिवारी, अयोध्या : नई पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के विराट व्यक्तित्व का दर्शन कराने के लिए देशभर के शैक्षिक संस्थानों में एनीमेशन फिल्में और धारावाहिक दिखाए जाने की योजना है। इसका प्रारूप गत दिनों अवध-मिथिला सम्मेलन में बना था। यह सब नई पीढ़ी में संस्कार रोपने के साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति के वैभवशाली अतीत व मूल्यों से बखूबी परिचित कराने के लिए हो रहा है। इसके लिए एनीमेटेड फिल्म व धारावाहिकों का 50 एपीसोड तैयार किया जा चुका है।

अवध विवि के कुलपति प्रो.मनोज दीक्षित व थिंक इंडिया की कोशिश से संपन्न हुए सम्मेलन में न सिर्फ इस पर चर्चा हुई, बल्कि योजना भी बनी। प्रस्ताव के तथ्यों व विषयवस्तु से सभी को अवगत कराया गया। इसके लिए महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त देशभर के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसे साकार करने के लिए इंडिया थिंक काउंसिल और एक अन्य फाउंडेशन 21 नोट्स बेंगलुरु तैयार है। धारावाहिक व फिल्मों का प्रदर्शन इन्हीं संस्थानों के जरिए विद्यालयों में होगा। इस दौरान पौराणिक कथाओं, भारतीय विरासतों एवं ऐतिहासिक मूल्यों की तथ्यपरक जानकारी साझा की जाएगी।

पाक में पोलियो ने बढ़ाई देश की चिंता

रोहित जंडियाल, जम्मू

- पड़ोसी देश में इस साल भी आए मामले, वायरस इधर आने का सता रहा डर
- जब तक पाकिस्तान में रहेगा पोलियो तब तक यहां पिलाई जाती रहेगी खुराक

पाकिस्तान में इस साल फिर पोलियो के मामले सामने आने से भारत विशेषकर जम्मू-कश्मीर की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को यह भय सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान से पोलियो का वायरस इधर न आ जाए। इसी को देखते हुए इस साल फिर से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान अगले साल जनवरी से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।

जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य भागों की तरह ही कई सालों से पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है। भारत को पहले से ही पोलियो उन्मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, मगर पड़ोसी देश पाकिस्तान में लगातार पोलियो के मामले दर्ज हो रहे हैं। इस कारण भारत की चिंता अभी भी बरकरार है। इसी कारण अभी तक पल्स पोलियो अभियान जारी है।

जम्मू-कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के साथ लगता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ सटे होने के कारण हर समय भय रहता है कि कहीं पोलियो का वायरस पाकिस्तान से यहां न आ जाए। इसी को देखते हुए यहां का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हर समय सतर्क रहता है।

19 से अभियान, सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष जोर : परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. अरुण शर्मा का कहना है कि जब तक पड़ोसी देश में पोलियो के मामले आ रहे हैं, तब तक यहां पर पल्स पोलियो अभियान जारी रहेगा। सीमांत क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में अगर बाहर का कोई भी बच्चा है तो उसे भी उस दिन वैक्सीन दी जाती है ताकि कोई भी बच्चा बिना वैक्सीन के न रहे। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी से तीन दिन के लिए अभियान चलाया जाएगा। पहले दिन बूथ स्तर पर अभियान होगा। दो दिन घर-घर जाकर उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो कि पहले दिन बूथ पर नहीं जा सकेंगे।

हर साल 20 लाख के करीब बच्चों को दी जाती है वैक्सीन

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही जगहों पर यह पहला पल्स पोलियो अभियान होगा। यहां हर साल करीब बीस लाख बच्चों को खुराक पिलाई जाती है। इसके लिए हजारों कर्मचारियों के अलावा गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों की भी मदद ली जाती है। इस साल भी इसके लिए तैयारी चल रही है।

बर्फीले स्थानों पर चुनौती

इस साल समय से पहले ही कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और उनका मुख्य शहरों से संपर्क कटने के कारण इन स्थानों पर अभियान चलाना चुनौती होगा। इसके लिए कई क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से भी वैक्सीन भेजी जाएगी। डॉ. अरुण का कहना है कि यहां की भौगेलिक स्थिति ऐसी है कि हर अभियान चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हर साल शत-प्रतिशत बच्चों को दवा पिलाई जाती है। बर्फ वाले स्थानों पर एडवांस में ही वैक्सीन भेज दी जाती है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

लखनऊ की पुरानी तस्वीर, बार-बार की जा रही है वायरल

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: देशभर में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक पुरानी फोटो को कुछ लोग वायरल करते हुए दावा कर रहे हैं कि तस्वीर दिल्ली पुलिस की है। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो चुके हैं। फोटो की पड़ताल करने पर विश्वास न्यूज ने पाया कि यह दावा फर्जी है। तस्वीर में दिख रहे आइपीएस अफसर का नाम डीके ठाकुर है।

पड़ताल: विश्वास न्यूज ने सबसे पहले वायरल तस्वीर को येनडेक्स टूल में अपलोड करके एनालिसिस किया। हमें पता चला कि यह तस्वीर कभी दिल्ली तो कभी कश्मीर में अत्याचार के नाम पर पहले भी वायरल हो चुकी है। आखिरकार हमें कैच न्यूज की वेबसाइट पर यह तस्वीर मिली। 14 फरवरी 2017 को प्रकाशित खबर के मुताबिक, 9 मार्च 2011 को अखिलेश यादव को अमौसी एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद लोहिया वाहिनी के प्रमुख आनंद भदौरिया को यूपी विधानसभा के घेराव के वक्त तत्कालीन लखनऊ के डीआइजी ध्रुवकांत ठाकुर ने जमीन पर गिराकर पीटा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ठाकुर को नोटिस भी जारी किया था।

इसके बाद हमने दैनिक जागरण के लखनऊ के अपराध संवाददाता ज्ञान मिश्रा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि तस्वीर 2011 की है। फोटो में दिख रहे अफसर डीके ठाकुर हैं। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि वायरल तस्वीर को उस वक्त स्थानीय फोटोग्राफर प्रमोद अधिकारी ने क्लिक किया था। इसके बाद विश्वास न्यूज ने प्रमोद अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने हमें कंफर्म किया, वायरल तस्वीर वर्ष 2011 की है। तस्वीर में जमीन पर गिरे हुए आनंद भदौरिया हैं, जो अभी सपा से एमएलसी हैं। जबकि अफसर का नाम डीके ठाकुर हैं। वर्तमान में ध्रुवकांत ठाकुर एटीएस के एडीजी हैं। उन्होंने विश्वास न्यूज को बताया कि तस्वीर उन्हीं की है। यह बात काफी पुरानी है। अंत में हमने फेसबुक यूजर अबू तल्हा अब्दाल की सोशल स्कैनिंग की। हमें पता चला कि इनके अकाउंट को 300 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। यह दिल्ली और जामिया में हो रहे प्रदर्शन को लेकर लगातार फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं।

क्या है वायरल पोस्ट में?

फेसबुक यूजर अबू तल्हा अब्दाल ने 16 दिसंबर को एक तस्वीर अपलोड करत हुए लिखा, इस बुजुर्ग पुलिस वाले को देखिए, यह अपने घरवालों से अपने बीवी बच्चों से कैसे आंखें मिलाते होंगे, अपनी बहादुरी का कौनसा किस्सा सुनाते होंगे, शेम ऑन दिल्ली पुलिस।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 923

अनदेखी

राज्य गठन के 19 साल बाद भी लैंसडौन पर ही निर्भर करता है यहां का पर्यटन, और भी हैं स्थान, लेकिन अनदेखी के चलते नहीं जुड़ पा रहे पर्यटकों से

लैंसडौन के भरोसे कोटद्वार क्षेत्र का पर्यटन

अजय खंतवाल, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

आसपास तमाम पर्यटन स्थल होने के बावजूद आज तक उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र से पर्यटकों का जुड़ाव नहीं हो पाया। राज्य गठन के 19 साल बाद भी पर्यटन नगरी लैंसडौन का मोह ही पर्यटकों को कोटद्वार लाता है। क्षेत्र में पहुंचने वाले करीब 70 फीसद पर्यटक लैंसडौन, शेष 30 फीसद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने के लिए ही इधर का रुख करते हैं।

कोटद्वार व आसपास के क्षेत्र में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है, लेकिन कभी भी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वीकेंड पर पर्यटक यहां आते तो हैं, लैकिन सिर्फ लैंसडौन घूमने के बहाने। लैंसडौन में पर्यटकों के पास घूमने को भुल्ला लेक, सेंट मेरी चर्च, टिप-इन-टॉप जैसे विकल्प हैं, जबकि कोटद्वार क्षेत्र के पर्यटन स्थलों में जरूरी सुविधाएं न होने से पर्यटक वहां जाने से परहेज करते हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर कहते हैं कि कोटद्वार क्षेत्र में पर्यटन विकास को कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। कण्वाश्रम का विकास इनमें एक है। कोशिश है कि पर्यटक लैंसडौन से बाहर निकलकर कोटद्वार क्षेत्र का भ्रमण भी करें।

लैंसडौन (पौड़ी) से 30 किमी दूर स्थित ताड़केश्वर धाम। जागरण

कोटद्वार स्थित कार्बेट टाइगर रिजर्व का हल्दूपड़ाव वन विश्राम गृह, जहां वन्य जीव प्रेमी अक्सर पहुंचते हैं। जागरण

पर्यटन विकास को बनी योजनाएं
पौड़ी-खिर्सू-लैंसडौन पर्यटन सर्किट
टिफ-इन-टॉप से जयहरीखाल के बीच रोप-वे निर्माण
जयहरीखाल में हर्बल गार्डन, लैंसडौन में ट्रैकिंग रूट व बर्ड वाचिंग प्वाइंट का विकास
टिफ-इन-टॉप में दूरबीन की स्थापना

वन प्रेमियों का स्वर्ग हल्दूपड़ाव

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) में पड़ने वाला हल्दूपड़ाव क्षेत्र अनूठी जैवविविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब कोटद्वार में सीटीआर का रिसेप्शन सेंटर खुलने के बाद डे-विजिट के लिए यहां पहुंचना आसान हो गया है।

वर्षवार कोटद्वार क्षेत्र में पहुंचे पर्यटक		
वर्ष	भारतीय	विदेशी
2019	355480	10560 (अब तक)
2018	119742	4314
2017	101533	4865
2016	118388	4060
2015	87393	3311

तेजस की तरह दौड़ेगी मालगाड़ी

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

विकास

- 100 बोगी लेकर डब्ल्यूएजी 12 इंजन 160 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ सकेगा
- मुरादाबाद रेल मंडल में अंतिम ट्रायल, सहारनपुर में बनाया लोको शेड

100 बोगी वाली लांग हॉल मालगाड़ी को तेजस की तरह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने की तैयारी है। भारतीय रेल ने मेक इन इंडिया आधुनिक इंजन डब्ल्यूएजी 12 तैयार किया है, जिसकी क्षमता 12 हजार हार्स पॉवर है। यह इलेक्ट्रिक इंजन 100 बोगी वाली मालगाड़ी को 160 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से खींच सकता है। इस इंजन को रखने के लिए सहारनपुर में शेड बनाया है। प्रवर मंडल विद्युत अभियंता (टीआरडी) जीतेंद्र कुमार ने बताया कि इंजन का ट्रायल करने व आरडीएसओ तक पहुंचाने का कार्य मुरादाबाद रेल मंडल प्रशासन को सौंपा गया है। रेल मंडल में इंजन का ट्रायल कराया जाना है।

12 हजार हॉर्स पावर की क्षमता का डब्ल्यूएजी 12 तैयार : मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रेल वंदे भारत व तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन व कोच का निर्माण कर चुका है। दोनों को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। देश में अभी तक छह हजार हार्स पॉवर के डब्ल्यूएजी 6 इंजन की क्षमता 100 बोगी को लेकर चलने की है। रेल कारखाना मधेपुरा ने 12 हजार हॉर्स पावर की क्षमता का डब्ल्यूएजी 12 तैयार किया है। इंजन का अंतिम ट्रायल रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) को करना है। ट्रायल में सफल होने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-2021 तक 120 इंजन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस इंजन से लौह अयस्क, खाद्यान्न व कोयला आदि कम समय में देश के एक से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सकता है। इस इंजन से लंबी ट्रेनों को भी तेजस से अधिक गति पर चलाया जा सकता है।

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 21 दिसंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

सेहत और स्वाद से भरपूर 'अरसा'

अरसा...यह नाम सुनकर आप भ्रमित न हों। हम किसी समय की बात नहीं कर रहे हैं, यह तो उत्तराखंड की बेहद खास मिठाई है। स्वाद ऐसा कि एक बार खा लें तो इसकी मिठास भूल नहीं पाएंगे। स्वाद और सेहत से भरपूर इस पकवान की खासियत यह है कि इसे गरमागरम खाएं या एक महीने बाद स्वाद में कोई फर्क नहीं मिलेगा। महाकौथिग में अरसा आपके मुंह में कुछ ऐसी ही मिठास घोल देगा।

नई पीढ़ी चख सकेगी स्वाद : यह ऐसी मिठाई है जो पहाड़ी लोगों के बीच रिश्ते बनाने का काम करती है। खासकर गढ़वाल क्षेत्र में लोग इसका खूब आनंद लेते हैं। अब उत्तराखंड के निवासी इसका स्वाद भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को इस पारंपरिक व्यंजन से जोड़ने के उद्देश्य से ही महाकौथिग में दिल्ली के पांच सितारा होटल के शेफ रोहन नेगी इसे परोसने की तैयारी में हैं।

अरसालु बन गया अरसा : शेफ रोहन बताते हैं कि अरसा को पहले अरसालु कहते थे, वो कैसे? दरअसल इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। जगदगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा गढ़वाल में भी कई ऐसे मंदिर हैं, जिनका निर्माण शंकराचार्य ने ही करवाया था। इन मंदिरों में पूजा करने के लिए दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को रखा जाता है। कुछ जानकार कहते हैं कि नौवीं सदी में दक्षिण भारत से ये ब्राह्मण जब गढ़वाल आए तो अपने साथ एक मिठाई अरसालु लेकर आए थे। चूंकि लंबे समय तक रखने पर भी खराब नहीं होती थी, इसलिए वो पोटली भर-भरकर अरसालु लाया करते

अरसा मिठाई

थे। धीरे-धीरे इन ब्राह्मणों ने स्थानीय लोगों को भी इसे बनाने की कला सिखाई। और इस तरह गढ़वाल पहुंचकर अरसालु बन गया अरसा। इसे बनाने के लिए गढ़वाल में गुड़ इस्तेमाल होता है, जबकि कर्नाटक में खजूर गुड़ का प्रयोग किया जाता है। धीरे-धीरे ये गढ़वाल की लोकप्रिय मिठाई बन गई।

स्वाद और सेहत से भरपूर : अब बताता हूं इसे बनाने का तरीका, जो बहुत खास है। शेफ रोहन कहते हैं कि चावल को साफ कर उसे अच्छी तरह धोने के बाद तीन दिनों के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। भिगोने के बाद इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि 24 घंटे बाद उसका पानी बदलना है। तीन दिन बाद चावल को पानी से निकाल कर सूती कपड़े के ऊपर सुखा लेंगे। पानी सूख जाने के बाद उसे मिक्सर में दरदरा पीसते हैं। चावल के उस दरदरे आटे में गुड़, दही और घी को मिलाकर अच्छी तरह गूंथ लिया जाता है।

अब इस आटे को गीले कपड़े से ढककर 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इस आटे में तिल डालकर फिर गूंथा जाता है और छोटी-छोटी लोई बना कर मनचाहे शेप में ढाला जाता है। एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर घी गरम कर अरसा की गोलियों को सुनहरा होने तक उसमें तलते हैं। चाहें तो आप इन्हें गरम-गरम खाएं या फिर सप्ताह भर बाद...न स्वाद बदलेगा न सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सौरभ पांडेय

भांग की चटनी से लेकर डुबुक तक का स्वाद

महाकौथिग में भांग की चटनी, डुबुक, बाल मिठाई और झेंगोर की खीर जैसे पकवानों का स्वाद भी ले सकेंगे। यहां अल्मोड़ा की खास बाल मिठाई लोगों को कुमाऊंनी जायके का आनंद देगी। साथ ही उत्तराखंड का विशेष जलेबा (बड़ी जलेबी) भी मिल सकेगा। इन्हें भी शेफ तैयार करेंगे।

सामाजिक धरोहर

गांव का कौथिग बन गया महाकौथिग

उत्तराखंड का अध्यात्म, सौंदर्य, परिवेश, संस्कृति जनजीवन...आप भी...गढ़वाल रीति परंपरा के महाकौथिग को याद तो करते होंगे? रीति-संस्कृति परंपरा...एक अद्भुत संगम...देवो की भूमि कहते हैं जिसे। पहाड़ों से उतर एक छोटा सा उत्तराखंड पश्चिम के आंचल में ही आ बसा है। तभी तो आज सप्ताह भर तक महाकौथिक सजता है। कैसे दिल्ली-एनसीआर में रचा बसा...पला बढ़ा और सजा है उत्तराखंडी समाज बता रहे हैं सौरभ पांडेय :

इंदिरापुरम स्थित रामलीला मैदान में आयोजित महाकौथिग में नंदा देवी की पूजा करती महिलाएं। जागरण आर्काइव

दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने के लिए जैसे ही यूपी गेट क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ते हैं तो आपको बाएं तरफ बड़ी-बड़ी इमारतें दिखनी शुरू हो जाएंगी। बडे-बडे दिशा सूचक लगे नजर आएंगे जो आपको इंदिरापुरम के विभिन्न खंडों की ओर इंगित करते हैं। आप सोच रहे हैं यह सब क्यों बता रहे हैं, दरअसल यही रास्ता एनसीआर में बसे छोटे से उत्तराखंड की ओर भी ले जाता है। जहां रहने वाले भले नौकरी दिल्ली-गुरुग्राम में करें लेकिन उत्तराखंडी समाज की अनुभूति उन्हें यहीं होती है। यही कोई दो दशक पहले की तो बात है जहां आज इंदिरापुरम में बसावट दिखाई देती है वहां कभी जंगल होता था। इंदिरापुरम निवासी पूर्व पार्षद और वर्तमान में महाकौथिग कार्यकारिणी के अध्यक्ष केवल लखेड़ा बताते हैं कि करीब बीस साल पहले मैं रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था। वर्ष 2002 में इंदिरापुरम आकर अपना रियल एस्टेट का काम शुरू किया। काम तो शुरू हो गया लेकिन पहाड़ और गांव से बिछड़ने की एक टीस हमेशा मन को कचोटती रही। उस समय इंदिरापुरम के न्याय खंड इलाके में गिने चुने परिवार ही रहते थे। त्योहार आते और चले जाते लेकिन अक्सर गढ़वाली और कुमाऊंनी संस्कृति की याद उन्हें सताती रहती।

बहुत काम आई वो डायरी : बताते हैं मैं हमेशा अपने साथ एक डायरी लेकर चलता था। दिनभर जगह-जगह लोगों से मुलाकात होती थी। उन दिनों मोबाइल का ऐसा चलन नहीं होता था, तो क्या करता था जिससे भी मुलाकात करता उसका मोबाइल नंबर अपनी डायरी में दर्ज कर लेता था। इसमें उत्तराखंड परिवार वालों के नंबर को एक जगह ही लिखता था। देखते ही देखते यह सूची लंबी होती चली गई। फिर जनवरी 2005 में अचानक महसूस हुआ कि उत्तराखंडी संस्कृति को साथ लेकर उत्तरायणी पर्व (मकर संक्रांति) मनाना चाहिए। पर्व में गाजे-बाजे के साथ यात्रा निकाली जाती है। मैंने डायरी उठाई और लोगों से संपर्क साधना शुरू किया। इस दौरान मेरी मुलाकात वैशाली निवासी एडवोकेट शशि प्रकाश धस्माना और

केबल लखेड़ा।

उनके परिवार से भी हुई। योजना बनी लेकिन उस साल तो पर्व पर यात्रा नहीं निकाली जा सकी लेकिन साल 2006 में इंदिरापुरम में उत्तरायणी पर्व पर भव्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में करीब 300 परिवार एक साथ जुटे। बस यहीं से शुरुआत हुई और कारवां बढ़ता गया।

हर त्योहार बनने लगा खास : केवल के अनुसार इसके बाद उनका परिवार लगातार बढ़ता गया। होली हो या दीवाली हर त्योहार में उत्तराखंडी परिवारों का साथ मिलने लगा। अब नया साल भी उत्तराखंडी डोल दमाऊ के साथ मनाया जाने लगा। इसी दौरान पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था का निर्माण हुआ। संस्था उत्तराखंडी समाज के लोगों को जोड़कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने लगी। धीरे-धीरे न्यायखंड इंदिरापुरम में गढ़वाली रामलीला की भी शुरुआत हुई जो मिनी उत्तराखंड बनने की दिशा में एक बड़ा सांस्कृतिक कदम साबित हुई। रामलीला के गढ़वाली और कुमाउंनी के संवाद लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ते। बीते कई सालों से लगातार इस रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला के माध्यम से न सिर्फ उत्तराखंडी परिवारों के बच्चों को अपनी भाषा बल्कि अपनी संस्कृति और सद्भावना से जुड़ने का भी मौका मिलता है। मुझे गर्व होता है कि मैं नौ साल से आयोजित हो रहे महाकौथिग का हिस्सा हूं। अभी तक हमारी टीम इस महाकौथिग यानी मेले को दिल्ली-एनसीआर के स्तर का बड़ा मेला बना चुकी है। महाकौथिग टीम का लक्ष्य है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके।

500 परिवार थे पूरे इंदिरापुरम में : आज इंदिरापुरम की आबादी करीब पांच लाख है। जब मैं यहां आया था तो सिर्फ इंदिरापुरम के न्याय खंड में ही फ्लैट बने थे। इनमें महज 500 परिवार ही रहते थे। ज्ञान खंड, अहिंसा खंड, शक्तिखंड आदि में तो लंबी-लंबी झाड़ियां और पेड़ होते थे, जंगल सा लगता था। आए दिन सुनसान जगहों पर लूट की वारदातें होती थीं। ऐसे में लोगों को जोड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य यह भी था कि वे एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकें।

ताकि न छूटे गांव की संस्कृति : इंदिरापुरम से पार्षद और उत्तराखंड के कई संगठनों से जुड़ी

लग रहा है न मानो हम उत्तराखंड के उसी महाकौथिग में हैं, जिसकी कमी दिल्ली-एनसीआर में आने के बाद सबसे ज्यादा कचोटती थी। वही संस्कृति... वही नृत्य और परंपरा...हालांकि यह झलक पिछले वर्ष आयोजित महाकौथिग की है। इस बार भी आपको ऐसा ही सौंदर्य...संपन्न... संस्कृति से समृद्ध मेला नजर आएगा। जागरण आर्काइव

मीना भंडारी।

मीना भंडारी करीब 17 साल पहले इंदिरापुरम में रहने आईं थीं। आसपास बमुश्किल 15-20 परिवार रहते थे। न्यायखंड एक दो और तीन सभी में मिलाकर 500 से 700 परिवार रहते थे। ज्यादातर लोगों का आपस में संपर्क भी नहीं था। जिस इंदिरापुरम में आज गगनचुंबी इमारतें हैं वहां पूरा जंगल था। दूर-दूर तक लोगों का नामोनिशान तक नहीं होता था। त्योहार के समय में अक्सर मुझे और मेरे पति को महसूस होता था कि गांव और अपनी पहाड़ की संस्कृति छूट रही है। त्योहार मनाए तो जाते थे लेकिन घर में ही रहकर। यहां तक की होली जैसे त्योहार पर भी आसपास के लोगों से मिलना नहीं हो पाता था। फिर पता चला कि इंदिरापुरम के अलावा वैशाली, बृज विहार, शालीमार गार्डन आदि इलाकों में काफी संख्या में पहाड़ी परिवार रहते हैं।

इसके बाद मेरी मुलाकात राजेंद्र चौहान और उनके परिवार से हुई। केवल लखेड़ा का साथ मिल गया और सभी ने मिलकर उत्तराखंडी समाज को एकजुट करने व संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने का काम शुरू किया।

आती थी गांव के कौथिग की याद : हर साल गर्मियों की छुट्टियों में पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने गांव जाती थी। वहां पर छोटे-छोटे कौथिग (मेला) लगते हैं। मीना बताती हैं कि हम उत्तराखंड समाज के लोगों के साथ मिलते तो अक्सर यह बातें होतीं कि किस तरह गांव के कौथिग में ढोल दमाऊ के साथ नृत्य होता है। किस तरह से तरह-तरह के उत्तराखंडी पकवान बनाए जाते हैं। हर बार लोग यही बात करते कि क्यों न इंदिरापुरम में भी एक कौथिग हो जिससे बच्चे भी उनकी अपनी पहाड़ी संस्कृति को साथ लेकर चलें।

फिर घर-घर पहुंचाया : आखिर 2011 में वह दिन आ ही गया जब लोगों ने आपसी सहयोग से महाकौथिग करने का निर्णय लिया। सभी ने छोटी-छोटी रकम दी और उत्तराखंडी कलाकार, पकवान, पहनावे आदि के स्टॉल लगाए। अब जरूरत थी इस महाकौथिग को सफल बनाने की। इसके दायरे को और बढ़ाने की। इसके लिए इंदिरापुरम, वैशाली, शालीमार गार्डन, बृज विहार आदि इलाकों में घर-घर जाकर लोगों को महाकौथिग के लिए बुलावा दिया। जिस तरह चुनाव प्रचार किया जाता है उसी तरह लोगों को महाकौथिग से जोड़ा गया। मीना कहतीं हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि कौथिग महज आठ साल में इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे और इस प्रयास को सराहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत व कई अन्य मंत्री भी इस उत्सव में दिल्ली-एनसीआर के मिनी उत्तराखंड में शिरकत करेंगे।

गीतों से आती है गांव की याद : गीतों में जो गाया, धरातल पर साकार कर दिखाया जहां एक और महाकौथिग दिल्ली-एनसीआर के उन मेलों में शुमार हो गया है जहां रोजाना 30-35 हजार लोग आते हैं और पहाड़ी संस्कृति से रूबरू होते हैं। वहीं इस सफलता के पीछे एक उत्तराखंड की एक बड़ी कलाकार का नाम भी जुड़ा है। वह हैं कल्पना चौहान। कल्पना बताती हैं कि उनके गीतों में सबसे पहला गीत था 'बेडू पाको बारह मासा' जिसका अर्थ है बेडू पूरे 12 माह पकते हैं। अक्सर उत्तराखंड के विशेष जायके जैसे मूला, गहत की दाल आदि का जिक्र आता है। ये सब गीतों में गाकर लोगों को उससे जोड़ती थीं, गांव की...पहाड़ी संस्कृति की जायके की याद दिलातीं। लेकिन मन में यह टीस रहती कि क्यों न ऐसा कुछ हो जिससे हमारे बच्चे भी इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखें...यहीं अपने पहाड़ के गांवों संगम को महसूस कर सकें। आज गर्व होता है कि महाकौथिग के माध्यम से वह सब साकार हो रहा है।

कल्पना चौहान।

शून्य से लाख तक का सफर, बन गया हमसफर : महाकौथिग टीम के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक राजेंद्र चौहान महाकौथिग को अपना हमसफर मानते हैं। कहते हैं कि करीब 20 साल पहले जब दिल्ली-एनसीआर में उत्तराखंडियों की संख्या बहुत कम थी तब मुझे लगता था कि यहां उत्तराखंड समाज को एक पहचान मिलनी चाहिए। जब देखते थे कि परिवार के बच्चों को गढ़वाली कुमाऊंनी भाषा नहीं आती तो दिल में बस यही आता कि क्यों बच्चे अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। इसके बाद महाकौथिग टीम बनी और अब महाकौथिग हमसफर बन गया है।

जुड़े हैं सभी उत्तराखंडी लोक कलाकार : उत्तराखंड के सबसे हिट गीत बेडू पाको बारह मासा गाने वाली कल्पना चौहान महाकौथिग की संस्थापक सदस्य हैं तो अन्य कलाकार इससे दूर रहें यह संभव ही नहीं। उत्तराखंड के सभी लोक कलाकार इससे जुड़े हैं और हर साल यहां आकर प्रस्तुति भी देते हैं।

लोक गायक रजनीकांत सेमवाल, गजेंद्र राणा, लता तिवारी, लोकेश कैंतुरा, कमल आर्या, मीना खत्री, हेमा नेगी करासी, धूम सिंह रावत, हरिमंदा, माया उपाध्याय, जितेंद्र तोमकयाल, अमित मस्तु बड़ोनी, सुनील थपलियाल और निधि राणा बीते कई साल से महाकौथिग से जुड़े हुए हैं।

गंगा आरती में दिखेगी हरिद्वार-ऋषिकेश की झलक

21 दिसंबर यानी आज इंदिरापुरम के शक्तिखंड स्थित रामलीला मैदान में जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लोक प्रस्तुतियों के बीच महाकौथिग का उद्घाटन करेंगे। वहीं हरिद्वार की प्रसिद्ध गंगा आरती भी इस बार महाकौथिग का हिस्सा बनेगी।

- 22 दिसंबर रविवार को शाम पौने आठ बजे इस भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। 101 दीपों से मां गंगा की आराधना की जाएगी।
- 23 दिसंबर को उत्तराखंड के श्रीनगर का प्रसिद्ध उत्सव ग्रुप भी दुर्पदा की लाज नामक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है।
- 24 दिसंबर को दिव्यांग कलाकार देश के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जो देश के लिए सरहद पर बलिदान हो गए।
- 25 दिसंबर को उत्तराखंड फोक म्यूजिक अवार्ड का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
- 26 दिसंबर को सामूहिक नृत्य व संगीत प्रतियोगिता होगी।
- 27 दिसंबर को कृषि एवं स्वरोजगार काउंसलिंग से लोगों को जोड़ा जाएगा।
- 28 दिसंबर को उत्तराखंडी कवि सम्मेलन में प्रियंका मेहर, दीपक मेहर आदि कवि अपनी प्रस्तुति देंगे।
- 29 दिसंबर को खेलकूद प्रतियोगिता के साथ महाकौथिग का समापन होगा।

गंगोत्री धाम की थीम

महाकौथिग की टीम ने इस बार खुद को गंगा सफाई अभियान से जोड़ते हुए गंगोत्री धाम रखी है। महाकौथिग के सह कोषाध्यक्ष सौरभ धस्माना ने बताया कि गंगा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की लाइफलाइन है। ऐसे में लोगों को इसकी सफाई के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसे देखते हुए यह थीम चुनी गई है। स्टेज के पीछे गंगोत्री धाम का विशाल कटआउट दिखाई देगा। इसके साथ स्टॉलों में भी इसकी झलक दिखाई देगी। पिछले साथ यह थी जागेश्वर धाम रखी गई थी, जबकि 2017 में यह बद्रीनाथ धाम थी।

इतिहास संजोए सैनिकों की जन्मभूमि गांवड़ी

शहर के गांव

भागदौड़ और चकाचौंध भरी शहरी जिंदगी, क्षण भर सांस लेने की भी किसी को फुर्सत नहीं, लेकिन इसी दिल्ली में एक गांव ऐसा भी है जहां युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी साथ बैठकर हंसी-ठिठोली करते हैं, देश-दुनिया की बातों पर विमर्श करते हैं, जहां की मिट्टी में आज भी परंपराओं की खुशबू बरकरार है। जो 450 वर्ष पुराने इतिहास को आज भी अपने भीतर समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं गांवड़ी गांव की। इस गांव में प्रवेश करते ही यहां की सांस्कृतिक धरोहरों से साक्षात्कार होता है। चौधरी भूले राम कहते हैं कि राजनीति के साथ-साथ धार्मिक आस्थाओं में भी इस गांव की अपनी खास पहचान है। यह गांव कई वीर सैनिकों की जन्मभूमि भी है। पहले तो लोग यहां खेती पर ही निर्भर थे, लेकिन अब युवा पढ़-लिखकर पायलट, वकील, डॉक्टर और शिक्षक बन रहे हैं। कुछ तो राजनीति के क्षेत्र में भी नाम कर रहे हैं। यहां गुर्जर, पंडित, नाई, बनिया, जोगी, वाल्मीकि व अन्य समुदाय के लोग मिलजुल रहते हैं।

अलग है पहचान : 16वीं शताब्दी में बसा गांवड़ी गांव पहले यमुना खादर के पास था, लेकिन बाढ़ के खतरे के कारण इस गांव को यमुना से पुनर्वासित कर दिया गया। अब यह घोंडा विधानसभा क्षेत्र में है। गांव के निवासी बदले राम बैंसला की मानें तो 1992 तक यहां खेती हुआ करती थी। लोग पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यमुना खादर वाले क्षेत्र में खेती करते हैं। गांव का नाम 'गांवड़ी' कैसे पड़ा, इस पर राम प्रसाद नंबरदार कहते हैं कि पूर्वजों ने ही नाम रखा था। गांव शब्द से ही इसका नाम गांवड़ी पड़ा था। नत्थू व दयाराम नाम के गुर्जरों ने इस गांव को बसाया था उनके वंशज आज भी इसी गांव में रहते हैं।

वहीं चौधरी अंतराम कहते हैं गांव के लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाया है। गांव के निवासी महक सिंह व रेखा रानी पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं, जबकि वर्तमान में राजकुमार बल्लन पार्षद व पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं तो श्रीदत्त शर्मा विधायक हैं। श्रीदत्त शर्मा के पिता पंडित याद राम दिल्ली व एनसीआर के लोकप्रिय गायक थे। वे हरियाणवी गीत गाया करते गाते थे। सन् 1936 से लेकर आजादी के दौर तक रेडियो पर लोग उनके गाने बड़े शौक से सुनते थे। गुर्जर विकास परिषद के अध्यक्ष चौधरी बृजपाल प्रधान ने कई वर्षों से दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो गांव के अन्य लोग भी इस मुहिम में उनके साथ हैं।

शिव मंदिर है ऐतिहासिक धरोहर : मान सिंह कहते हैं कि जब गांव बसा था तब यहां चार बड़े कुएं हुआ करते थे, लेकिन अब केवल दो ही कुएं बचे हैं, जिनमें से एक कुआं आज भी जीवित है। वहीं गांव में 100 साल पहले स्थापित प्राचीन शिव मंदिर भी है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में एक कुआं भी है जो अब सूख चुका है। केशवती ने बताया कि यहां 300 वर्ष पुराना भूमिया ग्राम देवता का मंदिर है। इस मंदिर में हर वर्ष सावन में विशाल भंडारा होता है। हर रविवार को गांव के लोग मिलकर पूजा करते हैं। होली व दीवाली में भी बड़े स्तर पर पूजा का आयोजन होता है। गांव के एक समाज सेवी थे हंसराज उनके नाम पर यहां एक पार्क बना हुआ है।

विश्वयुद्ध में लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों की जन्मभूमि : टेकचंद मुखिया कहते हैं कि गांव के लोग आजाद हिंद फौज व विश्वयुद्ध का हिस्सा रह चुके हैं। यहां के निवासी लाला नाई दूसरे विश्वयुद्ध में शहीद हो गए थे। उनके साथ देवी सिंह, राम लाल, हरिया, काले राम, सुंदर, राम स्वरूप ने भी दूसरे विश्वयुद्ध में भाग लिया था। इतना ही नहीं गांव के लोगों ने मुगलों से भी लोहा लिया था। दया राम गुर्जर ने गांव के लोगों के साथ मिलकर लाल किले पर हमला किया था। उस समय शाहजहां दिल्ली के राजा थे।

आज भी नहीं भूले अपनी संस्कृति : भले ही आज लोगों के घरों में मार्बल के फर्श डल गए हों, लेकिन रोटी बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का ही उपयोग किया जाता है। विजय लक्ष्मी कहती हैं लोग अपने घरों की छत पर मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और चूल्हे की ही रोटी खाते हैं। महिलाएं मिलजुल कर खाना पकाती हैं। पहले लोग पशुपालन और खेती करते थे। इतना ही नहीं, लोगों को घुड़सवारी का भी खूब शौक था। पुरुषों का पारंपरिक लिबास धोती-कुर्ता व मुंडासा (पगड़ी) है। महिलाएं पहले घाघरा-चोली व ओढ़नी पहनती थीं, लेकिन अब वे सलवार सूट पहनती हैं।

-रितु राणा

सर्द दोपहरी में हंसी ठिठोली करते हुए परिवार के साथ चूल्हे पर रोटियां सेकने का अपना अलग ही आनंद है। गांवड़ी की महिलाएं आज भी इसी तरह मिलजुल कर खाना पकाती हैं। जागरण

गांवड़ी गांव स्थित भूमिया ग्राम देवता का मंदिर। जागरण

पानीपत से आगे, सूरजमल की कहानी

दो सप्ताह पहले रिलीज हुई हिंदी फिल्म पानीपत के कारण जाट राजा सूरजमल का ऐतिहासिक चरित्र दोबारा चर्चा में आ गया। उल्लेखनीय है कि फिल्म कथानक में उनके सही चरित्र चित्रण न किए जाने को लेकर काफी असंतोष भी दिखा। जबकि पानीपत की लड़ाई (वर्ष 1761) में ऐन मौके पर सदाशिव भाऊ के व्यवहार से बेजार होकर अपनी सेना सहित मैदान से हटने वाले सूरजमल का उदात्त मानवीय चरित्र युद्ध के पश्चात घायल मराठा सेना और स्त्रियों को सुरक्षा और शरण देने से उजागर हुआ। नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक 'महाराजा सूरजमल' में लिखा है कि पानीपत युद्ध से बचे हुए एक लाख मराठे बिना शस्त्र, बिना वस्त्र और बिना भोजन सूरजमल के राज्य-क्षेत्र में पहुंचे। सूरजमल और रानी किशोरी ने प्रेम और उल्लास से उन्हें ठहराया और उनका आतिथ्य किया। हर मराठे सैनिक या अनुचर को खाद्य सामग्री दी गई। घायलों का तब तक उपचार किया गया, जब तक कि वे आगे यात्रा करने योग्य न हो गए।

अंग्रेज इतिहासकार ग्रांट डफ ने मराठे शरणार्थियों के साथ सूरजमल के बर्ताव के बारे में लिखा है कि जो भी भगोड़े उसके राज्य में आए, उनके साथ सूरजमल ने अत्यंत दयालुता का बर्ताव किया और मराठे उस अवसर पर किए गए जाटों के व्यवहार को आज भी कृतज्ञता तथा आदर के साथ याद करते हैं। फादर वैंदेल, और्म की पांडुलिपि के अनुसार, (पानीपत की लड़ाई के परिणामस्वरूप) सूरजमल उन अनेक महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामी बन गया, जो इससे पहले पूरी तरह मराठों के प्रभाव-क्षेत्र में थे। चंबल के इस ओर उसके सिवाय अन्य किसी का शासन नहीं था और गंगा की ओर भी लगभग यही स्थिति थी।18 वीं शती तक मुगल शासन की यह स्थिति हो गई थी कि दिल्ली में बादशाहत कमजोर पड़ने से सारे देश में सत्ता की छीन झपट आरंभ हो गई थी। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह राग-रंग-रस में इतना मग्न रहता था कि परदेश से नादिरशाह और अहमद शाह के रेले आते और किले और नगर को लूटकर जाते रहे, देश और प्रजा का कुछ भी होता रहा, वह तो अपनी लालपरियों के आगोश में मस्त रहा।इतिहास के अनुसार, ब्रज प्रदेश पर अब्दाली का आक्रमण दो बार हुए। पहला आक्रमण 26-27 फरवरी 1757 को जहान खां अफगानी के सेनापतित्व में हुआ था, फिर नजीम खां आया था और दूसरी बार का आक्रमण पंद्रह दिन बाद स्वयं अब्दाली के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन चाचा वृन्दावन दास की लंबी कविता 'श्री हरिकला बेला' के अनुसार वर्ष 1757 और वर्ष 1761 में तीन वर्ष के अंतराल में वे आक्रमण किए गए थे। उल्लेखनीय है कि अंतिम आक्रमण के बाद कवि ने 'हरिकला बेला' की रचना भरतपुर में सुजान सिंह सूरजमल के शासनकाल में की थी।

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

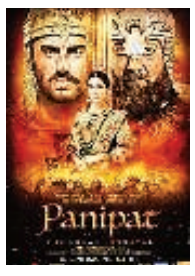

उत्तर मुगल काल में नादिरशाह का आक्रमण दिल्ली तक और उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी अब्दाली का आक्रमण मथुरा-वृंदावन तक हुआ था। उन दोनों को यहां हमले के लिए आमंत्रित किया गया था। असली बात यह थी कि ब्रज प्रदेश का जाट राजा सूरजमल और दक्षिण के मराठे दिल्ली पर निगाह लगाए हुए थे और जो अपने को दिल्ली का वंशागत मालिक समझते थे, वे इन शक्तियों से घबराए हुए थे।अहमदशाह अब्दाली को विशेष रूप से सूरजमल जाट की बढ़ती शक्ति और प्रभाव से टक्कर लेने के लिए बुलाया गया था। उसका वश सूरजमल पर तो चला नहीं, मथुरा-वृंदावन की लूटपाट और हिंदुओं के सिरों की मीनारें बनाकर ही वह लौट गया। ऐसे में अब्दाली के सूरजमल को कुचल डालने के बुलावा की बात बेअसर ही रही और उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ पाया।

जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ही सूरजमल का सितारा चमका। जयपुर राज्य में ईश्वरी सिंह और माधोसिंह के बीच सात वर्षों तक उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। इस दौरान ही सूरजमल उभरा क्योंकि न तो विलास भवन में बैठे मुगल बादशाह को उस ओर ध्यान देने की फुर्सत थी और न अंतपुर के षड्यंत्रों में फंसे जयपुर नरेश के पास समय था। बल्कि मराठों के आक्रमण से अपनी रक्षा करने बगरू की लड़ाई (1748) माधोसिंह को समझाने-बुझाने के लिए ईश्वरी सिंह को ही सूरजमल की आवश्यकता पड़ गई थी। उस आवश्यकता ने सिद्ध कर दिया कि जयपुर की तुलना में भरतपुर की शक्ति कम नहीं थी, बल्कि बढ़ने लगी थी। उसकी शक्ति बढ़ने का एक और प्रमाण यह है कि दिल्ली के शाह आलम के वजीर सफदरजंग ने भी अपने पठान विरोधी अभियान में सूरजमल की सहायता मांगी थी। बाद में सफदरजंग और सूरजमल ने मिलकर दिल्ली को खूब लूटा और नष्ट कर डाला। अब्दाली के जाने के बाद सूरजमल मुगल बादशाह का अटल शत्रु बन गए थे और जयपुर के सहायक हो गए थे। ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के बाद जब माधोसिंह जयपुर का राजा बन गया, तब उसके भाई प्रताप सिंह के लिए भी आड़े वक्त में वही शरणदाता सिद्ध हुए थे।

जेट को समाधान प्रक्रिया के लिए मिले और तीन महीने

मुंबई, प्रेट्र : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसलएटी) ने बंद पड़ी प्राइवेट विमानन कंपनी जेट एयरवेज की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने की अवधि 90 दिन बढ़ा दी है। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों और संस्थाओं की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने एनसीएलटी के मुंबई बेंच से कंपनी की कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस (सीआइआरपी) पूरी करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। वजह यह थी कि दक्षिण अमेरिका के सिनर्जी ग्रुप ने अपनी तैयारी पूरी करने के लिए ज्यादा वक्त मांगा था।

हम कारोबारियों के लिए जोखिम उठाना बेहद जरूरी है। भारत में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है और इकोनॉमी मजबूत है।
– अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता रिसोर्सेज

सेंसेक्स	41,681.54 ▲ 7.62	निफ्टी	12,271.80 ▲ 12.10	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,894 ▲ ₹109	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 45,786 ▲ ₹338	$ डॉलर	₹ 71.12 ▲ ₹0.09	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 66.25

हमसे पहले इकोनॉमी की तबाही का तमाशा देख रहे थे कुछ लोग : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एसोचैम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के अपने प्रयासों को उद्योग जगत से साझा किया। उन्होंने कहा कि बीते पांच वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि कठिन लक्ष्य भी रखे जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। पहले लोग सिर्फ इकोनॉमी की तबाही का तमाशा देख रहे थे।

मोदी ने उद्योगों के हित में उठाए गए कदमों पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'उद्योग जगत के हित में उठाए जाने वाले हर फैसले पर सवाल उठाना ही कुछ लोगों ने अपना दायित्व समझ लिया है। जब 2014 से पहले के बरसों में अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उस समय अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग किस तरह तमाशा देखते रहे, यह देश को नहीं भूलना चाहिए।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आप अच्छी तरह जानते हैं कि पांच-छह साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि इकोनॉमी में डिसिप्लीन लाने का प्रयास किया है। हम भारत को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के दो महत्वपूर्ण पिलर पर खड़ा कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के तमाम उपायों से लेकर जीएसटी तक, आधार लिंक्ड पेमेंट से लेकर डीबीटी तक अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्नाइज और स्पीड अप करने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं।' उन्होंने बीते पांच वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सरकार के कामों का भी जिक्र किया जिनके चलते भारत 190 देशों की सूची में 142वें स्थान से आज 63वें स्थान पर आ गया है। मोदी ने कहा कि सरकार ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिये कंपनियों को बेहतर एक्जिट रूट दिया।

उद्योग जगत से देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'संकल्प से सिद्धि के इसी सकारात्मक और पारदर्शी माहौल में आपके लिए भी अवसरों का विस्तार हो रहा है। आपका हौसला पहले से बेहतर हो, वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन भी पहले से बेहतर हो, इसके लिए सरकार हर तरह से उद्योग जगत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया का बाजार हमारे सामने है। पूरी दुनिया को टक्कर देने का साहस हमारे भीतर है। आपका संकल्प और आपका सामर्थ्य पांच ट्रिलियन डॉलर के भारत के सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।'

उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनी एक्ट में छोटी गलतियों के लिए आपराधिक कार्रवाई करने वाले प्रावधानों को खत्म कर उद्योगों को राहत दी। अब भी यह प्रक्रिया जारी है। इस साल से टैक्सपेयर और आयकर विभाग के बीच ह्यूमन इंटरफेस को खत्म किया है। अब देश फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने श्रम सुधारों की दिशा में उठाए गए साहसिक कदमों का भी ब्योरा दिया।

बोले मोदी

- अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के पिलर पर खड़ा करने की कोशिश
- संकल्प से सिद्धि के इस माहौल में उद्योग जगत के लिए भी पैदा हो रहे विकास के अवसर

उद्योग संगठन एसोचैम के सालाना समारोह में पोस्टल टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संगठन के अधिकारीगण। प्रेट्र

उद्योगों को इकोनॉमी के प्रति शंकाओं से निकलना होगा : वित्त मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा है कि उसे इकोनॉमी को लेकर अपने संदेहों के घेरे से निकलना होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट और उसके बाद जो निर्णय किए, उनके असर दिखने शुरू हो गए हैं। वित्त मंत्री ने छोटे और मझोले उद्योगों से भी कहा वे अपनी कर्ज संबंधी दिक्कतों को लेकर किसी भी सरकारी बैंक की मदद ले सकते हैं।

उद्योग संगठन एसोचैम की सालाना बैठक में उद्योगपतियों के साथ एक परिचर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सिस्टम बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। कुछ कड़े निर्णय किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ये उद्योग के अनुकूल हों। पिछले पांच वर्ष में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों ने भारत को पूरी दुनिया में नई पहचान दी है। इंडस्ट्री भी इस बदलाव का हिस्सा बनी है।

सीतारमण ने इंडस्ट्री को 'हो पाएगा या नहीं' वाली शंका की स्थिति से बाहर आने को कहा है। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता वाले इस मूड के साथ काम नहीं करना चाहिए। इससे बाहर निकलिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के ज्यादातर संकेतक, खासतौर पर माइक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर मजबूत हो रहे हैं। महंगाई की दर नियंत्रण में है, एफडीआइ का प्रवाह मजबूत बना हुआ है। विदेशी मुद्रा के भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। सरकारी बैंकों में भी पेशेवर तरीके से काम होने लगा है।

इंडस्ट्री से भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने को आह्वान करते हुए सीतारमण ने कहा कि वह विनिवेश में हिस्सा ले और सरकारी कंपनियों के लिए बोली लगाए। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी कारोबार बंद हो। सरकार कानूनी और प्रशासनिक बदलावों के जरिये उन्हें फिर से शुरू करने के प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। नकदी की समस्या को दूर करने के साथ-साथ बैंकों को पेशेवर बनाने, गैर-बैंकिंग कंपनियों को मदद करने, रियल एस्टेट से जुड़ी समस्याओं के खात्मे और एमएसएमई के लिए कर्ज की दिक्कत को दूर करने जैसे कई कदम गिनाए, जिन्हें सरकार ने पिछले छह महीने में उठाया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया है ताकि उद्योगों और करदाताओं को परेशानी से बचाया जा सके।

- वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री से किया निवेश का आग्रह
- कहा – सुधार के उपायों का दिखने लगा असर

फैसला ▶ आनंद महिंद्रा छोड़ेंगे कार्यकारी चेयरमैन पद, बने रहेंगे कंपनी के निदेशक बोर्ड में

बड़े बदलाव की ओर महिंद्रा ग्रुप

सीईओ के नए सृजित पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी एमडी पवन गोयनका को

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिंद्रा ग्रुप ने अपने शीर्ष प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि आनंद महिंद्रा एक्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे। वे अगले वर्ष अप्रैल से नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी के निदेशक बोर्ड का हिस्सा बने रहेंगे। कंपनी ने एमडी के पद पर पवन कुमार गोयनका की दोबारा नियुक्ति की है और उन्हें सीईओ के नव-सृजित पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

ग्रुप द्वारा किए बदलाव की घोषणा पर आनंद महिंद्रा ने कहा कि इस योजना से कंपनी के प्रबंधन में टैलेंट की गहराई की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी संस्कृति, मूल्यों, प्रशासन और प्रभावी कामकाज के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि नई भूमिका में वे कंपनी के मूल्यों और शेयरधारकों के हितों की रखवाली करते रहेंगे। महिंद्रा ने कहा कि वे कंपनी के इंटरनल ऑडिट पर नजर बनाए रहेंगे। इसके साथ ही वे कंपनी बोर्ड के माध्यम से भी प्रशासनिक कामकाज की देखरेख करेंगे।

आनंद महिंद्रा ने 2012 में केशुब महिंद्रा के रिटायरमेंट के बाद कंपनी के चेयरमैन का पद संभाला था। महिंद्रा ग्रुप सॉफ्टवेयर से लेकर एयरोस्पेस तक के कारोबार में सक्रिय है। आनंद महिंद्रा के कार्यकाल में ग्रुप ने घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान कंपनी ने सैंगयोंग मोटर्स, रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस, प्यूगो मोटरसाइकिल्स जैसे सफल अधिग्रहणों को अंजाम दिया।

आनंद महिंद्रा फाइल फोटो

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस करते हुए कंपनी ने सीईओ का नया पद सृजित किया है। निकट भविष्य में फोर्ड इंडिया के साथ मिलकर कंपनी इस क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही है। कंपनी की महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और ऑटो मोबिलिटी सर्विसेस को मिलाकर मोबिलिटी सर्विस सेक्टर स्थापित करने की योजना है।

ग्रुप में ऐसे बढ़ा गोयनका का पद

गोयनका वर्ष 1993 में जनरल मैनेजर के रूप में कंपनी से जुड़े थे। उन्होंने अमेरिका के डेट्रॉएट स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में अपना कामकाज संभाला था। गौरतलब है कि कंपनी के सफल एसयूवी ब्रांड स्कॉर्पियो के विकास में गोयनका की प्रमुख भूमिका रही है।

ऐसे परवान चढ़ेगा बदलाव

- अप्रैल 2021 में गोयनका की सेवानिवृत्ति के बाद अनीश शाह कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे
- शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ के रूप में जुड़ेंगे
- वर्तमान सीएफओ वीएस पार्थसारथी नवगठित मोबिलिटी सर्विस सेक्टर की कमान संभालेंगे

महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को प्रबंधन में फेरबदल की खबरों के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में करीब एक परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 0.79 परसेंट की गिरावट के साथ 530.80 रुपये पर बंद हुए। इंट्रा-डे में यह 1.25 परसेंट तक लुढ़क गए थे। वहीं एनएसई में भी कंपनी के शेयरों को 0.85 परसेंट गिरावट का सामना करना पड़ा।

सवा पांच लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग से जुड़े डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन (डीसीसी) ने 5.23 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 8,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने बताया कि डीसीसी ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। हमें उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल में स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 टेलीकॉम सर्किल में 8,305.75 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का रिजर्व प्राइस 5,22,850 करोड़ रुपये बनता है।

ट्राई ने शुरू में 4.9 लाख करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस की सिफारिश की थी। परंतु बाद में दूरसंचार विभाग ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस तथा भारती एयरटेल के आठ सर्किल में लाइसेंस अवधि समाप्त होने से हासिल स्पेक्ट्रम को भी शामिल कर लिया। इससे रिजर्व प्राइस बढ़ा। अंशु प्रकाश ने बताया कि सफल बोलीदाता कंपनियों को एक गीगाहर्ट्ज (1,000 मेगाहर्ट्ज) से कम फ्रीक्वेंसी बैंड वाले स्पेक्ट्रम के लिए 25 प्रतिशत, जबकि उससे ऊपर के स्पेक्ट्रम के लिए 50 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा।

भारत का आर्थिक परिदृश्य मजबूत : फिच रेटिंग्स

नई दिल्ली, आइएएनएस: तमाम चुनौतियों के बावजूद मध्यम अवधि के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक समान श्रेणी के अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के लिए लंबी अवधि की आइडीआर (फॉरेन-करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग) 'बीबीबी माइनस' बरकरार रखी है। एजेंसी का कहना है कि आर्थिक वृद्धि को लेकर भारत का परिदृश्य स्थिर बना हुआ है। मध्यम अवधि में इसका रेटिंग बैलेंस 'बीबीबी' श्रेणी के अन्य देशों के मुकाबले बहुत मजबूत है।

एजेंसी ने ऊंचे सार्वजनिक कर्ज के मुकाबले विशाल विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बताई। इसकी बदौलत सरकार वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी और कम प्रति व्यक्ति जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) जैसी ढांचागत समस्याओं से निपटने में सक्षम होगी।

फिच ने कहा है, 'जीडीपी वृद्धि के मामले में स्पर्धी देशों के मुकाबले भारत के लिए हमारा आउटलुक अब भी मजबूत है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की माली हालत पतली होने और उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर पड़ने जैसे कुछ घरेलू कारणों से ऐसा हुआ है।'

फाइल फोटो

- कहा – विशाल विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय इकोनॉमी की बड़ी ताकत
- एजेंसी ने लंबी अवधि की आइडीआर बीबीबी माइनस बरकरार रखी

विकास दर अनुमान घटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान एक प्रतिशत घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया। इससे पहले एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5.6 प्रतिशत की गति से विकास का अनुमान लगाया था। हालांकि, एजेंसी ने यह उम्मीद भी जताई है कि धीरे-धीरे हालात सुधरेंगे और अगले वित्त वर्ष में विकास दर 5.6 और 2021-22 में 6.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार होगा भारत : प्रधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बन जाएगा। अभी भारत अमेरिका व चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया में ऊर्जा की औसत खपत 1.3 फीसद की रफ्तार से हर वर्ष बढ़ रही है लेकिन भारत में ऊर्जा की खपत 4.5 फीसद की रफ्तार से बढ़ रही है।

उद्योग चैंबर फिक्की के सालाना समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि सबसे बड़े ऊर्जा बाजार होने की वजह से भारत को ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी अपनी अलग नीति बनानी होगी जिसमें पारंपरिक के साथ ही गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का एक बेहतर मिश्रण होना चाहिए।

प्रधान ने कहा कि जिस हिसाब से देश में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उसे देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा निवेश भी करने की जरूरत होगी। खासतौर पर गैस आधारित उद्योगों में 100 अरब डॉलर का नया निवेश अगले कुछ वर्षों में होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी धीरे धीरे काफी बढ़ रही है। सरकार की नीति भी यही है कि गैस पर हमारी निर्भरता सबसे ज्यादा हो।

केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस व स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बीच में) फिक्की की सालाना बैठक में उद्योग संगठन की नई प्रेसिडेंट डॉ. संगीता रेड्डी व निवर्तमान प्रेसिडेंट संदीप सोमानी के साथ। जागरण

सारा फोकस निजी निवेश बढ़ाने पर हो : गीता गोपीनाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. गीता गोपीनाथ ने भारत के मौजूदा सुस्ती से उबरने के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह बताई है कि हर हाल में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। देश के प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की के सालाना समारोह में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए गोपीनाथ ने माना कि पिछली तीन तिमाहियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का आंकड़ा उनके अनुमान से भी ज्यादा है। उनके मुताबिक इस दौरान जो विकास दिखा है, वह सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में इजाफे की वजह से हुआ है। लेकिन आगे भी सरकारी व्यय की रफ्तार बनी रह सकती है, इसको लेकर संशय है। ऐसे में विकास को गति देने के लिए निजी निवेश बढ़ाना ही उपाय है।

गोपीनाथ का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि आइएमएफ अगले महीने भारत की इकोनॉमी को लेकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट जारी करेगा। इसमें चालू वित्त वर्ष और अगले दो वित्त वर्षों के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान भी लगाया जाएगा। आरबीआइ ने इससे पहले चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 4.5 प्रतिशत रह जाने की बात कही है। यह लगातार छठी तिमाही है जब विकास दर घटी है। विकासशील देशों में भारत कई वर्षों तक विकास दर के मामले में पहले स्थान पर था, लेकिन अब पांचवे स्थान पर फिसल गया है। सरकार लगातार मंथन कर रही है कि विकास दर को किस तरह से पटरी पर लाया जाए।

आइएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि हर अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि नीतियों में लगातार बदलाव किए जाएं। नीतियों के स्थायित्व के बगैर निवेशक समुदाय आगे फैसला नहीं कर सकता। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या भारत एक मैन्यूफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो उनका जवाब था कि निर्यात को बढ़ाए बगैर यह संभव नहीं है। अभी तक नए वैश्विक माहौल में जिस तरह से नई सप्लाई चेन बन रही है उससे भारत अलग होता दिख रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. गीता गोपीनाथ की फाइल फोटो।

आइएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के सुझाव

1. निजी निवेश का प्रोत्साहन हो प्राथमिकता
2. ग्रामीण मांग में जान फूंकने के लिए और प्रयास जरूरी
3. सुधार जारी रहें, मगर नियमों व नीतियों में हो स्थिरता

बिजनेस सेंटिमेंट्स सुधारना जरूरी

डॉ. गोपीनाथ ने कहा कि निजी निवेश बढ़ाने के लिए बिजनेस सेंटिमेंट्स को बेहतर करने की जरूरत होगी। वर्ष 2014-15 में जब यह सरकार सत्ता में आई तो बिजनेस सेंटिमेंट काफी मजबूत था। लेकिन उसके बाद से इसमें कमी आने लगी। कारोबारी जगत में उदासीनता के लिए वित्त की समस्या एक बड़ी वजह है। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अलग-अलग समस्याओं से जूझ रही हैं। सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। नए दिवालिया कानून का उदाहरण देते हुए डॉ. गोपीनाथ ने कहा कि इसे ज्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

तरीका

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया वादा, सरकार करेगी बदले की कार्रवाई, विदेश व्यापार नीति की तैयारियों में निर्यात संगठनों से की गोयल ने मुलाकात

निर्यात-बाधक देशों की पहचान करें कारोबारी : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय निर्यात पर कई देशों द्वारा लगाई जा रही अड़चनों से परेशान निर्यातकों को सरकार ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से ऐसे देशों की पहचान करने को कहा है, ताकि सरकार बदले की कार्रवाई कर सके। उन्होंने इंडस्ट्री को आश्वस्त किया कि सरकार इन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।

बुधवार को उद्योग संगठनों फिक्की और एसोचैम की सालाना बैठकों में हिस्सा लेते हुए गोयल ने कहा कि इन कदमों के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि भारत वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। उन्होंने कहा कि निर्यात की पूरी वैल्यू चेन की समस्याओं का निदान आवश्यक है। गोयल ने फिक्की के सम्मेलन में कहा, 'हमारी सरकार किसी एक कंपनी की दिक्कतों को दूर करने में विश्वास नहीं रखती। हम समस्याओं के मूल का विश्लेषण और उसके स्थायी समाधान की दिशा में काम करते हैं।' उन्होंने आगे कहा कि सभी पक्षों को सरकार को बताना होगा कि कौन सा देश शुल्क से इतर अन्य बाधाओं या विकल्पों का इस्तेमाल कर उनके निर्यात को बाधित कर रहा है। 'हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है और आवश्यकता हुई तो उन देशों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई की जाएगी।'

इससे पूर्व गुरुवार को विदेश व्यापार नीति की तैयारियों के सिलसिले में गोयल ने निर्यात परिषदों और संगठनों के साथ मैराथन बैठक की। पांच घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में 37 निर्यात संवर्धन परिषदों, फियो और तीन कमोडिटी बोर्ड ने हिस्सा लिया।

बैठक में सीबीआइसी की तरफ से चिन्हित 'रिस्की एक्सपोर्ट्स' का मुद्दा भी उठा। ऐसे निर्यातकों को वित्तीय संसाधन जुटाने में दिक्कत आ रही है। वाणिज्य मंत्री ने बैठक के दौरान ही विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी संगठनों व परिषदों से 31 दिसंबर तक ऐसे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट भेजने को कहा ताकि वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत में इस मुद्दे को विस्तार से उठाया जा सके। बैठक में आसियान समेत अन्य देशों के साथ हुए एफटीए और अन्य समझौतों पर भी चर्चा हुई।

पीयूष गोयल फाइल फोटो

- गोयल पहले भी कह चुके हैं कि कारोबार के मामले में भारत अन्य देशों के साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार करेगा
- आरसेप को बताया चीन-भारत का मुक्त व्यापार समझौता

ईपीसी की संख्या सीमित करने का सुझाव

गोयल ने बैठक में निर्यात संवर्धन परिषदों की संख्या को तार्किक बनाने पर भी जोर दिया ताकि काम के दोहराव से बचा जा सके। वाणिज्य मंत्री ने बड़े निर्यातकों को फियो का सदस्य बनने की सलाह दी। गोयल ने सुझाव दिया कि छोटी निर्यात परिषदों को उन्हीं के क्षेत्र में काम कर रही बड़ी परिषदों में अपना विलय कर देना चाहिए।

बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी से पॉजिटिव बने रहे शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में उछाल के बल पर शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान एसबीआइ, आइसीआइसीआइ बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 7.62 अंकों की बढ़त के साथ 41,681.54 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंट्रा-डे के दौरान यह 41,809.96 तक पहुंचने में सफल रहा था। एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 12.10 परसेंट की तेजी आई। यह 12,271.80 के रिकॉर्ड स्तर पर स्थिर हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.23 परसेंट की तेजी दर्ज की गई। एसबीआइ, यस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, आइसीआइसीआइ बैंक और भारतीय एयरटेल के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। वहीं वेदांता, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आइटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

जानकारों के मुताबिक बजट में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद के चलते सत्र की शुरुआत में बाजार की रफ्तार तेज रही। लेकिन फिच रेटिंग्स द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान में कटौती के बाद बाजार के उत्साह में कमी आई। इसके अलावा विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में भरोसा बनाए रखने की वजह से भी निवेशकों का हौसला बना रहा। एशिया के अन्य बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। शंघाई, टोक्यो के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। वहीं हांगकांग और सियोल के बाजार बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। वाल स्ट्रीट में ट्रेड-डील का उत्साह बना हुआ है।

- लगातार चौथे सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स
- भारतीय शेयर बाजारों पर मेहरबान हैं विदेशी निवेशक

बदल रही सऊदी अरब की तस्वीर

महिलाओं पर सख्त प्रतिबंधों और तंगदिली के लिए बदनाम रहा सऊदी अरब अब तेजी से बदलाव की राह पर जाता दिखाई दे रहा है। महिलाओं को हाल के दिनों में ड्राइविंग की अनुमति देकर रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियां तोड़ चुका है। अब राजधानी रियाद के बाहरी इलाके बनबन में इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक महोत्सव की इजाजत देकर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इस महोत्सव में सऊदी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर शिरकत की और संगीत का भरपूर आनंद उठाया। इस उदारवादी नजरिए के लिए क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान को श्रेय दिया जा रहा है। एएफपी

साइंस फाउंडेशन के नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतवंशी को चुना

- एनएसएफ के अगले निदेशक होंगे सेतुरमन पंचनाथन
- आइआइटी मद्रास और आइआइएस-बेंगलुरु से पढ़ाई कर चुके हैं पंचनाथन
- विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देती है एनएसएफ

भारतवंशी कंप्यूटर वैज्ञानिक सेतुरमन पंचनाथन की फाइल फोटो। साभार : एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी वैज्ञानिक सेतुरमन पंचनाथन (58) को प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) का अगला निदेशक चुना है। पंचनाथन फ्रांस के कोर्डोवा की जगह लेंगे। एनएसएफ निदेशक के तौर पर कोर्डोवा का छह साल का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है। बता दें कि एनएसएफ एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह का ही एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआइए) है।

व्हाइट हाउस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के निदेशक केल्विन ड्रोगेमीयर ने बताया, 'कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉ. पंचनाथन का शोध-अनुसंधान के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। इसी को ध्यान में रखकर उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।' अपनी नियुक्ति पर पंचनाथन ने कहा कि वह सम्मनित महसूस कर रहे हैं। पंचनाथन ने 1981 में मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक के बाद 1984 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएस) से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1986 में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री लेने के साथ ही 1989 में कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पंचनाथन वर्तमान में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) में एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुख्य अनुसंधान और नवाचार अधिकारी हैं। वह इसी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कॉग्निटिव यूबिकिटस कंप्यूटिंग के संस्थापक निदेशक भी हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सीनेट अविलंब महाभियोग चलाए

- डेमोक्रेट पर बगैर सुबूत, बिना सफाई मांगे फैसला करने का आरोप

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के उच्च सदन सीनेट से खुद पर अविलंब महाभियोग चलाने की मांग की है। कहा है कि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट सांसदों ने बचाव के लिए उन्हें न तो वकील दिया, न कोई गवाह पेश किया, कुछ नहीं किया। इसलिए अब वह सीनेट से पूछ रहे हैं कि वे कैसे महाभियोग चलाएंगे। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन समेत सात संभावित उम्मीदवारों ने एक साथ ट्रंप पर हमला बोला है, लेकिन वे आपस में ही उलझते नजर आए।

बुधवार को प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ दो आरोप- सत्ता के दुरुपयोग और संसदीय जांच को बाधित करने के आरोप तय हुए थे। इसके बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले सदन ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। अब यह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। यहां कुल 100 सीटों में 53 पर रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है। वरिष्ठ सीनेटर मिच मैककॉनेल के महाभियोग को लेकर आए बयान के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर सही प्रक्रिया न अपनाए जाने की आशंका जताई है। माना जा रहा है कि सीनेट में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव जनवरी में पेश होगा। ट्रंप ने ट्वीट में कहा, मामले में कोई सुबूत नहीं है। वे (डेमोक्रेट) उसे दिखा नहीं पाए। वे मुझे हटाना चाहते हैं। मैं भी मामले की जल्दी सुनवाई चाहता हूं। अमेरिका के इतिहास में एंड्यू जॉनसन और बिल क्लिंटन के बाद ट्रंप ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग चल रहा है। अमेरिका के संविधान के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन महाभियोग को लेकर खुद भी अपनी पूरी प्रक्रिया चला सकता है। लेकिन राष्ट्रपति तभी सत्ताच्युत होंगे जब सीनेट के दो तिहाई सदस्य (67) महाभियोग के पक्ष में मतदान करेंगे।

तुलसी गबार्ड की हो रही आलोचना : उधर, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड की बुधवार को प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ आए महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग से अनुपस्थित रहने के कारण आलोचना हो रही है। गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हवाई से सांसद हैं।

न्यूज गैलरी

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी (बाएं) और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो। एपी

ईरानी राष्ट्रपति ने जापान के पीएम से मुलाकात की

टोक्यो : अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी शुक्रवार को जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो से मिलने टोक्यो पहुंचे। किसी ईरानी राष्ट्रपति का बीते दो दशक में जापान का यह पहला दौरा है। टोक्यो पहुंचने पर रूहानी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते आर्थिक पाबंदियों का सामना कर रहे ईरान और अमेरिका के बीच जापान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। (एएफपी)

पाकिस्तान में पोलियो के 111 मामले सामने आए

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में इस साल पोलियो संक्रमण के कुल 111 मामले सामने आ चुके हैं। देश के पोलियो उन्मूलन विभाग ने जानकारी दी कि बीते बुधवार को अलग-अलग प्रांतों से संक्रमण के सात नए मामले प्रकाश में आए हैं। अफगानिस्तान और नाइजीरिया के साथ-साथ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पोलियो का प्रकोप अभी भी जारी है। पाकिस्तान में 2012 से लेकर अब तक पोलियो उन्मूलन अभियान से जुटे 68 लोगों की हत्या हो चुकी है। (प्रेट्र)

हंबनटोटा पोर्ट की सुरक्षा अपने हाथ में रखेगा श्रीलंका

कोलंबो : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा है कि चीन द्वारा निर्मित हंबनटोटा पोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा उनका देश अपने हाथ में ही रखेगा। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राजपक्षे ने कहा कि बंदरगाह के वाणिज्यिक पहलू को लेकर चीन के साथ 99 साल के करार को तो वे नहीं बदलने जा रहे, लेकिन इसकी सुरक्षा का सारा दायित्व श्रीलंका खुद संभालेगा। श्रीलंका इस मुद्दे पर चीन के साथ बातचीत करने को तैयार है। (आइएएनएस)

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से तीन की मौत

सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग से तीन लोगों की मौत की खबर है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मरने वालों में दो स्वयंसेवी शामिल हैं। घटना साउथ ऑस्ट्रेलिया प्रांत की है। आग की चपेट में आने से करीब एक दर्जन लोगों के घायल होने की भी सूचना है। देश के जंगली इलाकों में पिछले महीने से आग की विभीषिका जारी है। (आइएएनएस)

मानवाधिकार मामला ▶ यूरोपीय संघ की संसद ने बीजिंग पर बोला जोरदार हमला

उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर चीनी अफसरों पर लगाया जाए प्रतिबंध

कहा- चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड में नहीं हुई है कोई उल्लेखनीय प्रगति

स्ट्रासबर्ग, एएफपी: यूरोपीय संघ की संसद ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ किए जा रहे बर्ताव पर बीजिंग पर जोरदार हमला बोला है। संसद ने इसके लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने का आह्वान किया है। संसद के सदस्यों ने गुरुवार को स्वीकार किए गए एक संकल्प पत्र में कहा कि यूरोपीय यूनियन द्वारा अब तक अपनाए गए तरीकों से चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में इस तरह के प्रतिबंधों को लगाए जाने पर विचार करना चाहिए।

यूरोपीय संघ की संसद ने एक बयान में कहा, 'यूरोपीय संसद के सदस्य अपील करते हैं कि अगर उचित और प्रभावी माना जाए तो शिनजियांग प्रांत में बुनियादी अधिकारों के गंभीर दमन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाए और उनकी संपत्ति फ्रीज की जाए।' बयान में आगे कहा गया है कि संसद चीन की सरकार से आग्रह करती है कि वह बिना किसी आरोप, मुकदमे या दोषसिद्धि के मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की प्रथा को तुरंत खत्म करे और इल्हाम तोहती समेत हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करे। बता दें कि तोहती को इस साल के सखारोव पुरस्कार से नवाजा गया है।

बुधवार को यूरोपीय संसद ने जेल में बंद उइगर बुद्धिजीवी तोहती की बेटी को यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ संसद द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सोवियत भौतिक विज्ञानी आंद्रे सखारोव की स्मृति में प्रदान किया जाता है। दरअसल, चीन ने लगभग 10 लाख उइगर अल्पसंख्यकों (अधिकांश मुस्लिम) को हिरासत शिविरों में बंद कर रखा है जिसके चलते उसे अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

बीजिंग ने शुरुआत में तो ऐसे शिविरों के अस्तित्व से इन्कार किया था, लेकिन अब उसका कहना है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस तरह के जातीय अल्पसंख्यकों को हिरासत शिविर (चीन इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहता है) में रखना आवश्यक है।

हांगकांग और मकाउ पर चीनी राष्ट्रपति ने दुनिया को चेताया

मकाउ, रायटर : चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने प्रशासनिक क्षेत्रों हांगकांग और मकाउ को लेकर दुनिया को आगाह किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन (इयू) का नाम लिए बगैर खरी-खरी सुनाते हुए चिनफिंग ने कहा कि चीन अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में विदेशी ताकतों को दखल की कभी इजाजत नहीं देगा। चीनी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया, जब हाल ही में अमेरिका ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया है। ब्रिटेन और ईयू भी हांगकांग पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।

राष्ट्रपति चिनफिंग ने यह सख्त संदेश शुक्रवार को यहां चीन को मकाउ सौंपे जाने की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में दिया। इस मौके पर मकाउ में चीन समर्थित नई सरकार को शपथ भी दिलाई गई। मकाउ के नए मुख्य कार्यकारी के तौर पर हो लाट सेंग (44) ने शपथ ली। चीन के इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए सेंग का चयन गत अगस्त में किया गया था। चिनफिंग ने कहा, 'मुझे हांगकांग और मकाउ के चीन में वापसी को महत्व देना चाहिए। इन दोनों विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों का मसला पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला है। इसमें विदेशी ताकतों का कोई काम नहीं है। हम किसी भी बाहरी ताकत को दखल की इजाजत नहीं देंगे।'

1999 में चीन को सौंपा गया था मकाउ

20 दिसंबर, 1999 को मकाउ चीनी शासन के दायरे में आया था। इससे पहले इस क्षेत्र पर पुर्तगाल का शासन था। जबकि 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग इस शर्त के साथ को चीन सौंपा था कि वह इस क्षेत्र की स्वायत्तता को बनाए रखेगा। हांगकांग जून से विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है।

उत्तर दिशा से हुआ था सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला

सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको में हमले से क्षतिग्रस्त हुआ शेड। फाइल/रायटर

वाशिंगटन, रायटर: अमेरिका ने कहा है कि 14 सितंबर को सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमला उत्तर दिशा की तरफ से किया गया था। हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मलबे के विश्लेषण से इसके संकेत मिलते हैं। यह नई जांच अमेरिका की उस बात की पुष्टि करती है, जिसमें उसने हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया था।

अपनी जांच संबंधी अंतरिम रिपोर्ट में वाशिंगटन ने कहा है कि निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाने से पहले ड्रोन उत्तर-पश्चिम में लगभग 200 किमी (124 मील) दूर एक स्थान तक गया था। मानवरहित यान (यूएवी) के अधिकतम 900 किलोमीटर की दूरी तय करने से पता चलता है कि हमला सरकारी तेल कंपनी अरामको के अब्कैक स्थित सबसे बड़े तेल शोधन संयंत्र के उत्तर से किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में तेल ठिकाने पर किए गए ड्रोन हमले और ईरान द्वारा निर्मित मानवरहित विमान आइआरएन-05 यूएवी में बहुत सी समानताएं मिली हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हथियारों के मलबे के विश्लेषण से यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिर हमला किस निश्चित जगह से किया गया। बता दें कि 14 सितंबर को सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुए हमलों के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने हमलों की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि हूती विद्रोहियों का समर्थन करने वाले ईरान ने हमलों में अपनी किसी भूमिका से इन्कार किया था।

पाक के प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हो रहा है दुष्प्रचार

- मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने के बाद आलोचना से आहत हैं सेवानिवृत्त होने जा रहे आसिफ सईद खोसा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वह अपनी स्वच्छ अंतरात्मा के साथ सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देशद्रोह के मामले में पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने के बाद उनके और न्यायपालिका के खिलाफ दुष्प्रचार छेड़ दिया गया है।

शुक्रवार मध्य रात्रि को सेवानिवृत्त होने जा रहे 64 वर्षीय खोसा ने कहा कि न्यायपालिका और उन्हें आलोचना में घसीटा जा रहा है। विशेष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को छह साल पुराने देशद्रोह के मामले में मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई थी। उन्हें 2007 में संविधान को निष्प्रभावी बनाने के लिए यह सजा सुनाई गई है।

इस सजा के बाद देश की ताकतवर सेना और इमरान खान सरकार न्यायपालिका से नाराज हो गई है। कानून मंत्री फारोह नसीम ने गुरुवार को कहा कि जिस न्यायाधीश ने फैसला लिखा वह मानसिक रूप से बीमार है और उसे काम करने से रोका जाना चाहिए।

ब्रिटेन में शिक्षित खोसा ने कहा, 'न्यायपालिका और मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू हुआ है। आरोप निराधार और गलत हैं। हम अपनी शक्ति की सीमाएं जानते हैं और यह भी जानते हैं कि सच हमेशा कायम रहता है।'

अपने सम्मान में जुटे कोर्ट के कर्मचारियों से निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'मैंने 100 फीसद काम करने का प्रयास किया, अपने कर्तव्य से परे जाकर करने का प्रयास किया, कभी कुछ बोला नहीं, जो भी कहा अपनी कलम के माध्यम से कहा, कभी अकारण फैसला नहीं रोका और इस सार्वजनिक सेवा को अपने जीवन के बेहतरीन साल देने के बाद आज मैं अपना यह परिधान अपनी उस अंतरात्मा के साथ उतारने जा रहा हूं जो एकदम साफ है।'

दुष्कर्म के खिलाफ आवाज

दुष्कर्म और महिला हिंसा को लेकर भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में आवाजें उठने लगी हैं। यह तस्वीर दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सैंटियागो की है, जहां फैमिनिस्ट समूह 'लास्टीसिस' के विशेष अभियान 'ए रेपिस्ट इन योअर वे' के अंतर्गत हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ए रेपिस्ट इन योअर वे एक गीत है, जो इन दिनों दुष्कर्म व महिला हिंसा के विरोध के लिए प्रतीक बन गया है। यह गीत सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। एएफपी

दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं शरीफ

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिल की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। एक मेडिकल जांच में यह पता चला है। शरीफ के निजी चिकित्सक डॉ. अदनान खान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया, लंदन स्थित हेयरफिल्ड हॉस्पिटल में हुई मेडिकल जांच में नवाज शरीफ की हृदय संबंधी गंभीर बीमारी का पता चला है। इसे लेकर अगले स्तर की जांच भी होनी है। बीमार पूर्व पीएम रक्त में प्लेटलेट्स की कमी की समस्या से पहले ही जूझ रहे हैं।

नवाज शरीफ। फाइल

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शरीफ को इलाज के लिए बीते 19 नवंबर को लंदन लाया गया था। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद शरीफ की हालत ज्यादा खराब होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलाज के लिए उन्हें जमानत मिली थी।

कार्रवाई

फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने उठाया कदम, गूगल एड्स पेज पर अस्पष्ट विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप

गूगल पर लगाया 1184 करोड़ का जुर्माना

पेरिस, रायटर : फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने गूगल एड्स पेज पर अस्पष्ट विज्ञापनों के प्रसारण और प्रतियोगिता के प्रतिकूल आचरण के मामले में सर्च इंजन पर 150 मिलियन डॉलर (करीब 1184.78 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। गूगल ने इस मामले में अपील दाखिल करने की बात कही है।

फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश गूगल, फेसबुक, एपल और अमेजन आदि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की उच्चस्तरीय जांच करते हैं। इसी साल सितंबर में गूगल चार साल से चल रहे राजकोषीय धोखाधड़ी के मामले को खत्म करने के लिए फ्रांस के प्राधिकार को करीब एक अरब रुपये देने को तैयार हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल खोज परिणामों के साथ व गूगल एड्स (ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म) पर प्रवर्तकों के विज्ञापन दिखाए जाने के मामले में सख्त जांच का सामना कर रहा है। फ्रांस प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के प्रमुख इसाबेल डी सिल्वा ने प्रेस वार्ता में कहा कि ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार के मामले में गूगल बाजार में 90 फीसद की हिस्सेदारी रखता है।

- इससे पहले कंपनी एक दूसरे मामले में करीब एक अरब रुपये जुर्माना देने को हुई थी तैयार

प्रतीकात्मक

इसी साल जनवरी में फ्रांसिसी डाटा सुरक्षा के निगरानीकर्ता ने यूरोपीय यूनियन की गोपनीयता नीति के उल्लंघन के मामले में गूगल पर 50 मिलियन यूरो (करीब 395 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था। उसने कहा था कि गूगल ने गोपनीयता भंग की और विज्ञापनों के मामले में जरूरत के बावजूद संबंधित से सहमति नहीं ली।

अमेरिका में जनगणना के दौरान अफवाहों पर प्रतिबंध लगाएगा फेसबुक

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : अमेरिका में अगले साल पहली बार होने वाली ऑनलाइन जनगणना को लेकर फेसबुक ने अपनी नीति तैयार की है। उसने जनगणना के दौरान अफवाहों को रोकने तथा नई विज्ञापन नीति अमल में लाने का फैसला किया है। इस दौरान वह ऐसा कोई विज्ञापन नहीं चलाएगा, जिसमें जनगणना का विरोध किया गया हो या उसमें न शामिल होने की अपील की गई हो। फेसबुक की अमेरिकी नीति के उपाध्यक्ष केविन मार्टिन व उत्पाद प्रबंधन निदेशक एस. चक्रवर्ती ने कहा, 'हमें फेसबुक पर जनगणना संबंधी पोस्ट व विज्ञापन को लेकर सतर्क होना होगा। हम देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गणना का समर्थन करते हैं।'

सीरिया में हुई बमबारी तुर्की सीमा की तरफ भागे हजारों लोग

बेरुत, रायटर : रूसी सैन्य बल और सीरियाई सेना की तरफ से की गई भीषण बमबारी के बाद विद्रोहियों के दबदबे वाले उत्तर-पश्चिम सीरिया से हजारों की संख्या में लोग तुर्की सीमा की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों व राहत दल के सदस्यों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मारात अल नुमान से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया। इसके कारण वहां वाहनों की लंबी कतार देखी गई। मारात अल नुमान विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। वहां रूसी और तुर्की सेना अकसर एयर स्ट्राइक समेत अन्य हमले करती रहती है।

बचाव दल ने बताया कि पिछली रात एयर स्ट्राइक में इलाके के एक गांव के 11 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार, आवासीय इलाकों में हुए हमलों में इस साल अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं।

26.7 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा ऑनलाइन लीक : रिपोर्ट

- ज्यादातर अमेरिकी यूजर हुए प्रभावित, लीक जानकारियों में यूजर आइडी, फोन नंबर व पूरा नाम शामिल

लंदन, आइएएनएस : फेसबुक यूजर के डाटा लीक का एक और बड़ा मामला सामने आया है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली ब्रिटेन की कंपनियों ने गुरुवार को दावा किया कि 26.7 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा वेब पर सार्वजनिक हो चुका है। इनमें फेसबुक यूजर की आइडी, फोन नवंबर और पूरा नाम शामिल है। डाटा लीक से प्रभावित ज्यादातर यूजर अमेरिकी हैं।

तकनीकी शोध करने वाली ब्रिटिश कंपनी कंपेरिटेक और सुरक्षा मामलों में शोध करने वाली बॉब डियाचेंको का मानना है कि वियतनाम के साइबर अपराधी इन डाटा का इस्तेमाल करते हुए अवैध स्क्रैपिंग या फेसबुक एपीआइ के दुरुपयोग जैसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तेजी के साथ किसी भी वेब पेज पर उपलब्ध डाटा को कॉपी करने के काम को स्क्रैपिंग कहा जाता है। यही नहीं, डाटा बेस पर उपलब्ध सूचनाओं के जरिये यूजर को एसएमएस फर्जीवाड़ा या फर्जी योजनाओं का शिकार बनाया जा सकता है।

डाटा लीक का नया मामला उस समय प्रकाश में आया है जब कैंब्रिज अनालिटिका घोटाले के कारण खो चुके विश्वास को फेसबुक दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 26.7 करोड़ फेसबुक यूजर का डाटा सार्वजनिक होने के मामले का पता लगाने के बाद डियाचेंको ने आइपी एड्रेस का प्रबंधन करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता को सूचित किया, ताकि इन्हें वेब से हटाया जा सके। हालांकि, यह डाटा डाउनलोड के तौर पर एक हैकर फोरम पर पोस्ट किया जा चुका है।

यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार का डाटा सार्वजनिक हुआ है। इसी साल सितंबर में 41.9 करोड़ डाटा लीक हुए थे, जिनमें फेसबुक यूजर की आइडी और फोन नंबर शामिल थे।

ये भी जानिए

वेस्टइंडीज के पास 17 साल बाद भारत को उसके घर में वनडे सीरीज में हराने का मौका है। रविवार को विराट की टीम ऐसा करने से पोलार्ड सेना को रोकेगी।

एक नजर में

डोपिंग के कारण यूक्रेन के भारोत्तोलक का स्वर्ण छिना

लुसाने: यूक्रेन के भारोत्तोलक ओलेक्सी टोरोखी से डोपिंग के आरोप में 2012 ओलंपिक में जीता उनका स्वर्ण पदक छीन लिया गया। 33 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने 105 किलोवर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। उनके मूत्र के नमूने में टेस्टोटेरोन पाया गया। उन पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ओलंपिक 2012 में ईरान के नवाब नासिरशेलाल को इस वर्ग में रजत और पोलैंड के बार्टोमियेज बोंक को कांस्य पदक मिला था। (एएफपी)

उम्र धोखाधड़ी में पकड़े गए 51 जूनियर एथलीट

नई दिल्ली: एथलेटिक्स में उम्र धोखाधड़ी का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले महीने त्रिपुरा में आयोजित राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर मीट में 51 उम्र धोखाधड़ी में पकड़े गए हैं जबकि 169 अन्य सत्यापन परीक्षण से बचने के लिए भाग गए। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर मीट में 494 जिलों के रिकॉर्ड 4500 लड़के और लड़कियां अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग में भाग लेने आए थे। इस मीट का आयोजन 24 से 26 नवंबर के बीच किया गया था लेकिन उम्र सत्यापन के आधार भारी संख्या में खिलाड़ियों को ज्यादा उम्र का पाया गया। (प्रेट्र)

2017 में डोपिंग के मामले बढ़े

मोंट्रियल: विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2017 में अंतरराष्ट्रीय खेलों में डोपिंग के मामले 2016 की तुलना में 13 फीसदी बढ़ गए। वाडा ने कहा कि 2017 में डोपिंग के 1804 मामले दर्ज किए गए जबकि 2016 में इनकी संख्या 1595 थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में दर्ज मामले 114 देशों और 93 खिलाड़ियों के थे। इटली के सर्वाधिक 171 खिलाड़ी डोपिंग के दोषी पाए गए जबकि फ्रांस के 128 और अमेरिका के 103 खिलाड़ी दोषी रहे। ब्राजील के 84 और रूस के 82 खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए। चीन, भारत, बेल्जियम, स्पेन और दक्षिण अफ्रीका में भी डोपिंग के मामले पाए गए। बॉडीबिल्डिंग में सबसे ज्यादा 266 और एथलेटिक्स में 242 खिलाड़ी दोषी रहे। (एएफपी)

अभिनव की आसान जीत

बेंगलुरु: फरीदाबाद से संबंध रखने वाले गोल्फर अभिनव लोहान ने एक शॉट की बढ़त के साथ बेंगलुरु गोल्फ चैंपियनशिप में शुक्रवार को खिताबी जीत दर्ज की। गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ एवं कंट्री क्लब में खेलने वाले 30 वर्षीय लोहान ने कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन (केजीए) के कोर्स पर चार अंडर 68 के साथ अपने कुल स्कोर को 13 अंडर 275 पहुंचाया और चार दौर के बाद खिताबी जीत दर्ज की। वहीं चंडीगढ़ के करणदीप कोच्चर (71) कुल का कुल स्कोर 12 अंडर-276 रहा जो इस टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। (प्रेट्र)

नई चयन समिति के लिए सीएसी का गठन दो दिनों में : गांगुली

बीसीसीआइ अध्यक्ष ने कहा तीन साल होगा नई चयन समिति का कार्यकाल

खेल संवाददाता, कोलकाता: नई चयन समिति के लिए क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का गठन अगले दो दिनों में किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन नई समिति उसी दिन करेगी। नई चयन समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा। सौरव ने कहा कि सीएसी का गठन सिर्फ एक बैठक के लिए किया जाएगा, जो चयनकर्ताओं का चयन करेगी। पुरुषों की टीम के मुख्य कोच का चयन कपिल देव की अगुआई वाली पूर्व समिति पहले ही कर चुकी है।' गौरतलब है कि वर्तमान चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद व एक सदस्य गगन खोड़ा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जतिन परांजपे, शरणदीप सिंह और देवांग गांधी का अभी एक-एक साल का कार्यकाल बाकी है, हालांकि अटकलें हैं कि उन्हें रिटेन नहीं किया जाएगा।

कोलकाता में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ● प्रेट्र

एनसीए ही करेगा बुमराह की फिटनेस का मूल्यांकन: पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ की अगुआई वाली नेशनल क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के फिटनेस का मूल्यांकन करने से इन्कार करने की खबरों के बीच सौरव ने साफ तौर पर कहा कि हरेक क्रिकेटर को फिटनेस टेस्ट के लिए एनसीए के ही जरिये जाना होगा। एनसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय क्रिकेटरों के लिए पहला और अंतिम केंद्र है। दादा ने आगे कहा कि हम एनसीए में सर्वोत्तम लोगों को चाहते हैं और वहां खिलाड़ियों के लिए सबकुछ आरामदायक चाहते हैं। खिलाड़ी सालभर विभिन्न जगहों पर खेलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एनसीए के फिजियो मुंबई में जसप्रीत की मदद करें।' खबर है कि एनसीए ने बुमराह के फिटनेस टेस्ट के आवेदन को खारिज कर दिया है क्योंकि उन्होंने एनसीए के फिटनेस ट्रेनरों की जगह प्राइवेट ट्रेनर की मदद की है। सौरव ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हमने एनसीए को और संगठित करने के लिए राहुल द्रविड़ को एनसीए की कमान सौंपी है। हम उनकी भूमिका बढ़ाएंगे। मैंने इस बाबत उनसे और एनसीए के अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की है।'

दादा फिर बने कप्तान: सौरव भले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से काफी पहले संन्यास ले चुके हों लेकिन फंटासी एकादश में उन्होंने खुद को ही कप्तान की जगह पर रखा है। कोच की भूमिका भी वे ही निभाएंगे। सौरव के फंटासी एकादश में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत शामिल हैं।

धौनी खुद लेंगे अपने संन्यास पर निर्णय

कोलकाता: सौरव ने कहा कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को पता है कि उनके लिए सर्वोत्तम क्या है। संन्यास लेने का फैसला उनका अपना होगा और वे खुद लेंगे। आइपीएल के पिछले सत्र में खराब अंपायरिंग पर सौरव ने कहा कि अंपायरों से गलती हो ही सकती है। हर किसी से होती है इसीलिए हम नया सिस्टम लेकर आए हैं, जिसके तहत नो बॉल पर निगरानी मैदान के बाहर (थर्ड अंपायर के जरिए) रखी जाएगी। इससे इस समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

अभ्यास की जगह मस्ती में व्यस्त टीम

कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच कटक में आखिरी वनडे होगा, फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेल रही है। दो मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम गुरुवार को ही भुवनेश्वर पहुंच गई थी लेकिन उसने शुक्रवार को कोई अभ्यास नहीं किया। टीम शनिवार को यहीं से कटक के बाराबती स्टेडियम में अभ्यास करने जाएगी। दोनों ही टीमें भुवनेश्वर के होटल में रुकी हुई हैं।

शुक्रवार को टीम ने अभ्यास की जगह मस्ती की। इस दौरान कप्तान विराट कोहली ने टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ खाली समय की दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। दोनों तस्वीरों में विराट ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ली है। विराट द्वारा पोस्ट की गई इन तस्वीरों में खिलाड़ी अपने खाली समय में कूल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। विराट ने इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि एक खाली दिन और दोपहर में लड़कों के साथ वही करते हुए जो हमें चाहिए। इसके साथ ही विराट ने हंसते हुआ इमोजी भी बनाया है। इन तस्वीरों में कुछ खिलाड़ी होटल गार्डन में धूप सेंक रहे हैं तो वहीं कुछ खिलाड़ी पूल बाथ के बाद नाश्ता ले रहे हैं। विराट की पहली सेल्फी में केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल नजर आ रहे हैं तो दूसरी सेल्फी में विराट के साथ ऋषभ पंत, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्रा सिंह चहल नजर आ रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार को ट्विटर पर फोटो साझा की जिसमें वह टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं ● ट्विटर

आइपीएल नीलामी में अपनी टीम से खुश हैं विराट: भारत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के भी कप्तान कोहली ने शुक्रवार को कहा कि वह आइपीएल नीलामी के दौरान अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा चुने गए खिलाड़ियों को लेकर खुश हैं। गुरुवार को कोलकाता में आयोजित आइपीएल नीलामी में आरसीबी ने क्रिस मॉरिस, आरोन फिंच, केन रिचर्डसन और डेल स्टेन सहित आठ खिलाड़ियों को खरीदा था। कोहली ने कहा कि हमने जिन खिलाड़ियों को चुना है, उससे मैं काफी खुश हूं और नए सत्र का इंतजार कर रहा हूं। हमने टीम के संयोजन और संतुलन पर काफी चर्चा की है। यह हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत की तरह लग रहा है। मेरा मानना है कि लीग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपको आक्रामक क्रिकेट खेलकर इसका लुत्फ उठाना होगा। टीम के क्रिकेट संचालन के निदेशक माइक हेसन ने कहा कि नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी की योजना उन खिलाड़ियों को खरीदने की थी, जो मौजूदा टीम के साथ अच्छा संयोजन बना सकें। हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं, जो घरेलू और बाहर के मैचों में सही संतुलन बनाने के साथ किसी भी परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करें। जिस तरह से नीलामी हुई उससे मैं बहुत खुश हूं। आरसीबी ने अब तक 12 संस्करणों में आइपीएल का खिताब नहीं जीता है। वे 2009 और 2011 दोनों में क्रमशः डेक्कन चार्जर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स से फाइनल में हारकर उपविजेता रहे थे।

किंग्स इलेवन पंजाब ने गुरुवार को 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था ग्लेन को, बीबीएल में 39 गेंदों पर 83 रन की पारी खेली

आइपीएल नीलामी के अगले ही दिन दिखा मैक्सवेल का तूफान

मेलबर्न, प्रेट्र: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने शुक्रवार को बिग बैश लीग (बीबीएल) में मेलबर्न स्टार्स के लिए 39 गेंदों पर शानदार 83 रन की तूफानी पारी खेली। एक दिन पहले ही गुरुवार को उन्हें आइपीएल नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ब्रेक लेने के बाद नीलामी के लिए लौटे मैक्सवेल ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें टी-20 क्रिकेट में सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। उन्होंने सात चौकों और पांच छक्कों की पारी खेली। 31 साल के इस बल्लेबाज ने अपने सबसे तेज अर्धशतक (23 गेंद) का रिकॉर्ड भी बराबर किया, जिसकी बदौलत उनकी टीम यहां मैट्रिकॉन स्टेडियम में ब्रिसबेन हीट के खिलाफ सात विकेट पर 167 रन बनाने में सफल रही।

किंग्स इलेवन पंजाब ने मैक्सवेल की इस शानदार पारी की ट्विटर पर प्रशंसा की, जो तीन साल बाद इस फ्रेंचाइजी में लौटे हैं। मैक्सवेल को द बिग शो के नाम से भी जाना जाता है और किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'ए बिग शो फ्रॉम द बिग शो' यानी 'मैक्सवेल का बेहतरीन प्रदर्शन'। जबाव में ब्रिसबेन हीट की टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 145 रन पर सिमट कर 22 रन से मैच गंवा बैठी।

ग्लेन मैक्सवेल ● ट्विटर

तांबे बोले, 48 साल की उम्र में 20 साल वाली ऊर्जा लाऊंगा: उनकी उम्र भले ही 48 साल हो, लेकिन मुंबई के लेग स्पिनर प्रवीण तांबे खुद को 20 वर्ष से अधिक का नहीं मानते और उनका कहना है कि वह आइपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) टीम में अपना पूरा अनुभव और ऊर्जा लेकर आएंगे।

आइपीएल नीलामी में जब युवाओं पर बोली नहीं लगी तब राजस्थान रॉयल्स के इस पूर्व लेग स्पिनर को केकेआर ने उनके आधार मूल्य 20 लाख रुपये में खरीदा। तांबे ने कहा, 'मैं आज भी इस मानसिकता के साथ खेलता हूं जैसे मैं 20 साल का युवा हूं। मैं अपना सारा अनुभव और ऊर्जा टीम में लेकर आऊंगा। मैं सकारात्मकता लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं टीम के साथ रहा तो ऐसा कर सकता हूं।' वह उम्र को बाधा नहीं मानते। उन्होंने कहा, 'लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। मुझे जो भी भूमिका मिलेगी, मैं अपनी ओर से शत-प्रतिशत देने की कोशिश करूंगा। मुझे कुछ साबित नहीं करना है। यदि ऐसा होता तो इतने लंबे समय तक नहीं खेल पाता।' डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेल शिक्षक के रूप में काम करने वाले तांबे ने कहा, 'मेरे परिवार ने इतने साल मेरा साथ दिया। वे मेरी हौसलाअफजाई करते रहे। केकेआर ने मुझमें कुछ तो देखा होगा जो मेरा चयन किया। मैं केकेआर टीम प्रबंधन का शुक्रगुजार हूं। मैं बदले में उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं।'

इरफान ने यूसुफ को ढांढस बंधाया: आइपीएल-2020 की नीलामी में किसी टीम द्वारा नहीं खरीदे जाने के बाद यूसुफ पठान को उनके छोटे भाई अनुभवी तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ढांढस बंधाया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे ऊर्जावान ऑलराउंडरों में से एक माने जाने वाले यूसुफ को आइपीएल के अगले संस्करण के लिए किसी टीम ने नहीं खरीदा। इसके बाद इरफान ने अपने भाई की हौसलाअफजाई की। उन्होंने ट्वीट किया, 'इस तरह की छोटी घटनाएं आपके करियर को परिभाषित नहीं कर सकतीं। आपका करियर शानदार रहा है। आप सही मायने में मैच विजेता रहे हैं। हम आपसे प्यार करते हैं लाला।' यूसुफ का आधार मूल्य एक करोड़ रुपये था, लेकिन 174 आइपीएल मैच खेलने वाले इस खिलाड़ी को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। यूसुफ ने अपने करियर में 2241 रन बनाए हैं और 42 विकेट भी लिए हैं।

लिन के ट्वीट पर बोले बुमराह, नेट पर मेरा सामना करना पड़ेगा: ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन ने आइपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस द्वारा उन्हें उनके आधार मूल्य दो करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद एक ट्वीट के जरिये अपनी खुशी जाहिर की है। इस धाकड़ कंगारू खिलाड़ी की खुशी की पांच वजहों में से एक वजह यह है कि अब उन्हें इस सत्र में जसप्रीत बुमराह का समाना नहीं करना पड़ेगा।

केकेआर के पास बैकअप के ज्यादा विकल्प नहीं : गंभीर

नई दिल्ली: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि उनकी पूर्व आइपीएल टीम केकेआर के पास बैकअप के ज्यादा विकल्प नहीं हैं और टीम प्रबंधन को खिलाड़ियों की नीलामी में ऑलराउंडरों पर बोली लगानी चाहिए थी। गंभीर ने कहा कि अगर टीम को समग्र रूप में देखें तो आंद्रे रसेल, इयोन मोर्गन या सुनील नरेन का कोई विकल्प नहीं है। मोर्गन को चोट लगने पर टीम के पास मध्यक्रम का कोई बल्लेबाज नहीं है। केकेआर को 2012 और 2014 में खिताब दिला चुके गंभीर ने कहा कि पैट कमिंस के चोटिल होने पर लॉकी फग्यूर्सन हैं, लेकिन शीर्षक्रम में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कमिंस अपने दम पर कुछ मैच जिताकर अपनी कीमत को सही साबित करेंगे।

बुमराह की प्रगति पर है मुंबई इंडियंस की नजर : जयवर्धने

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने शुक्रवार को कहा कि जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट से सही तरह से उबर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि यह भारतीय तेज गेंदबाज अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की आगामी सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज से वापसी करेगा। बुमराह पिछले दिनों भारतीय टीम के नेट अभ्यास के दौरान गेंदबाजी करते देखे गए थे। उन्होंने पीठ के स्ट्रेस फ्रैक्चर से लगभग पूरी फिटनेस हासिल कर ली है। बुमराह की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'यह अच्छा है कि उन्होंने (बुमराह) अभ्यास शुरू कर दिया है। वह विशाखापत्तनम में गेंदबाजी कर रहे थे। मुंबई इंडियंस के सदस्य उनकी प्रगति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हार्दिक भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। मैं काफी खुश हूं। उम्मीद है कि वह श्रीलंका के खिलाफ (जनवरी के शुरू में) या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वह कितनी तेजी से उबर पाते हैं।

गर्मी ने बढ़ाया टोक्यो ओलंपिक का बजट

ओलंपिक

- बजट 90 हजार करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना
- आयोजकों ने गर्मी और उमस से बचाव के लिए कई योजनाएं बनाई

टोक्यो, एएफपी: टोक्यो ओलंपिक 2020 का बजट 12.6 अरब डॉलर (करीब 90 हजार करोड़ रुपये) के आसपास रहने की संभावना है। आयोजकों ने ओलंपिक का अंतिम बजट पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि गर्मी से बचने के उपायों के कारण कुल बजट में इजाफा हुआ है।

अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस बजट में मैराथन और पैदल चाल की मेजबानी साप्पोरो को दिए जाने के कारण इन स्पर्धाओं का बजट इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इसकी लागत वहन करने को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) से विवाद चल रहा है। घरेलू प्रायोजन और टिकटों की बिक्री से आमद 30 अरब येन (लगभग 19.5 अरब रुपये) बढ़ी है। इसके साथ ही यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के बजट में बढ़ोतरी हुई है जिसमें गर्मी से निपटने के उपाय शामिल है। करीब 27 अरब येन (लगभग 17.5 अरब रुपये) का आपात बजट भी रखा गया है जो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होगा। आयोजकों ने गर्मी और उमस से बचाव के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें पानी का छिड़काव और सड़कों पर ऊष्मा रोकने वाली पुताई शामिल है। इससे पहले लास एंजिल्स ने 2028 ओलंपिक के लिए 6.9 अरब डॉलर (करीब 50 हजार करोड़ रुपये) के बजट का ऐलान करते हुए कम लागत में सफल खेलों के आयोजन का वादा किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का बजट 7.6 अरब डॉलर (करीब 75 हजार करोड़ रुपये) है।

आइओए की एजीएम में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर होगी चर्चा: भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) 30 दिसंबर को होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर चर्चा करेगा। इस बैठक में आइओए इस बात पर फैसला लेगी कि वह 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर सरकार से बात करनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा इस एजीएम में निशानेबाजी को हटाए जाने के बाद 2022 बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार पर भी मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। आइओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबानी पेश करनी है या नहीं इसको लेकर सदस्यों को ही फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि पहले हम आम सभा की स्वीकृति हासिल करेंगे और फिर हम सरकार की ओर रुख करेंगे।

अंडर-19 विश्व कप लेकर आना...

2020 आइसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार को ग्रुप फोटो खिंचवाते भारतीय टीम के खिलाड़ी। 17 जनवरी से नौ फरवरी तक आयोजित होगा विश्व कप ● प्रेट्र

जू. द्रविड़ का दोहरा शतक

नई दिल्ली, आइएएनएस: पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ भी अपने पिता जैसी लंबी-लंबी पारियां खेलने लगे हैं। जूनियर द्रविड़ अभी 14 साल के हैं और इन दिनों वह कर्नाटक राज्य संघ (केसीए) की जूनियर लीग में खेल रहे हैं। इस लीग में खेले गए एक मैच की दो पारियों में समित द्रविड़ ने 295 (201 और 94*) रन बनाए हैं।

दायें हाथ के बल्लेबाज समित इन दिनों केसीए के टूर्नामेंट में वाइस प्रेसिडेंट की टीम से खेल रहे हैं और उनकी टीम का यह मैच धारवाड़ जोन के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने पहली पारी में दोहरा शतक जमा दिया। समित की इस पारी में उनके पिता की बल्लेबाजी की झलक देखने को मिली। समित ने 201 रन बनाने के लिए 250 गेंदों का सामना किया, जिसमें 22 चौके शामिल हैं। उन्होंने इस मैच की दूसरी पारी में नाबाद 94 रन भी बनाए। समित ने 26 रन देकर तीन विकेट भी अपने नाम किए। धारवाड़ को सिर्फ एक बार ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उसकी पूरी टीम 124 रन पर ऑलआउट हो गई। समित की बदौलत उनकी टीम ने पहली पारी में सात विकेट के नुकसान पर 372 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में टीम ने एक विकेट खोकर 180 रन बनाए। अंत में यह मुकाबला ड्रॉ समाप्त हुआ।

समित द्रविड़ ● ट्विटर

मीराबाई ने जीता स्वर्ण

पदक वितरण के दौरान स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू (मध्य) ● ट्विटर

दोहा, प्रेट्र: पूर्व विश्व चैंपियन भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू ने छठे कतर इंटरनेशनल कप के 49 किलो ग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत के पदकों का खाता खोला।

चानू ने इस ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में 194 किग्रा का वजन उठाकर पीला तमगा हासिल किया। ये अंक टोक्यो ओलंपिक की अंतिम रैंकिंग के समय उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। हालांकि चानू का यह प्रदर्शन उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ से कम रहा। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 201 किलो है। वह स्नैच और क्लीन एंड जर्क में एक ही बार स्पष्ट वजन उठा सकीं। उसने स्नैच में 83 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो वजन उठाया। चानू चोट की वजह से विश्व चैंपियनशिप और एशियन गेम्स से बाहर रही थीं।

रंगास्वामी को आचरण अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया

नई दिल्ली, प्रेट्र: पूर्व भारतीय महिला कप्तान और क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) की सदस्य शांता रंगास्वामी को उनके खिलाफ लगे हितों के टकराव के आरोपों पर सफाई देने के लिए 28 दिसंबर को बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डीके जैन के सामने पेश होने के लिए कहा गया। सीएसी में शामिल कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और रंगास्वामी ने सितंबर में जैन से हितों के टकराव का नोटिस मिलने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता द्वारा शिकायत दायर करने के बाद यह नोटिस दिया गया था। इस हफ्ते के शुरू में कपिल और गायकवाड़ को क्रमशः 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को प्रस्तुत होने के लिए कहा गया था। रंगास्वामी की सुनवाई 28 दिसंबर को गायकवाड़ के साथ रखी गई है। कपिल और गायकवाड़ की तरह रंगास्वामी को भी स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

फुटबॉल क्लब विश्व कप के फाइनल में आज भिड़ेंगी दोनों टीमें, जुर्जेन क्लोप के सामने होगी जॉर्ज जीजस की टीम की कड़ी चुनौती

लिवरपूल का रास्ता रोकने की तैयारी में फ्लेमिंगो

दोहा, एएफपी: मैनेजर जुर्जेन क्लोप का इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के साथ चार साल का सफर बदलाव के दौर से गुजरा है जिन्हें शनिवार को क्लब विश्व कप के फाइनल में ब्राजीली क्लब फ्लेमिंगो से भिड़ना है। हालांकि लिवरपूल के विरोधी क्लब फ्लेमिंगो के मैनेजर जॉर्ज जीजस को इतिहास रचने में महज कुछ महीनों का समय लगा है। अब फ्लेमिंगो अपने शानदार दौर को जारी रखते हुए क्लब विश्व कप के खिताबी मुकाबले में लिवरपूल का रास्ता रोकने की तैयारी में है। लिवरवूल ने मोंटेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है।

जॉर्ज जीजस को पिछले जून में रियो डि जेनेरियो आधारित क्लब फ्लेमिंगो का मैनेजर नियुक्त किया गया था। तब 65 वर्षीय इस मैनेजर की नियुक्ति पर ब्राजील में कई लोगों की भौहें तन गईं थीं। उन्होंने फ्लेमिंगो को कोपा लिबर्टाडोरेस का खिताब दिलाकर बहुत जल्दी ही अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। उनके कार्यकाल में फ्लेमिंगो को लीग में कुल 29 में से दो मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी है। उसने क्लब विश्व कप के सेमीफाइनल में कतरी क्लब अल हिलाल को 3-1 से हराया था। लिवरपूल के खिलाफ मुकाबले को लेकर जॉर्ज जीजस ने कहा कि यह मेरे करियर का सबसे अहम मुकाबला है। यह फ्लेमिंगो के शानदार सत्र को यादगार बनाने में मदद करेगा। यह मेरे करियर के अब तक का सबसे बड़ा फाइनल होगा।

अधिकार के लिए होड़: फीफा को 24 टीमों के नए क्लब विश्व कप के वित्तीय अधिकार हासिल करने के लिए नौ आवेदन हासिल हुए हैं। कई लीगों की वजह से पूरे साल कार्यक्रम बेहद व्यस्त हैं लेकिन इसके बावजूद पहली बार 24 टीमों के बीच 2021 में चीन में होने वाले इस आयोजन के लिए अधिकार हासिल करने की होड़ मची हुई है।

सिटी के सामने लीसेस्टर की चुनौती: चेल्सी इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में अपने पूर्व मैनेजर जोस मौरिन्हो के क्लब टॉटनहम से डर्बी मुकाबले में रविवार को भिड़ना है लेकिन उससे पहले ईपीएल में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज लीसेस्टर सिटी की टीम मैनचेस्टर सिटी से भिड़ेगी। लीसेस्टर के खिलाफ शनिवार को होने वाले इस मुकाबले में जीत के साथ सिटी तालिका में शीर्ष पर काबिज लिवरपूल की अनुपस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वहीं आर्सेनल की टीम एवर्टन से शनिवार को ही भिड़ेगी।

बार्सिलोना के पास शीर्ष पर बने रहने का मौका

मैड्रिड: पिछले 17 वर्षों में पहली बार रीयल मैड्रिड के खिलाफ एल क्लासिको का मुकाबला ड्रॉ खेलने के बावजूद स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना के पास सत्र के पहले हाफ को शीर्ष पर रहते हुए समाप्त करने का मौका है। बार्सिलोना की टीम शनिवार को अलावेस से भिड़ेगी जहां जीत उसे शीर्ष पर बनाए रखेगी। बार्सिलोना के लिए मौजूदा सत्र उतार-चढ़ाव भरा रहा है। मौजूदा सत्र में बार्सिलोना पहले ही तीन हार झेल चुका है। हालांकि उसकी गलतियों का फायदा रीयल मैड्रिड जैसे उसके विरोधी टीमें उठाने में असफल रही हैं।

लिवरपूल के खिलाफ होने वाले क्लब विश्व कप फाइनल से पहले अभ्यास सत्र के दौरान अपने मैनेजर जॉर्ज जीजस (दायें) के साथ चर्चा करते फ्लेमिंगो के गेब्रियल बारबोसा ● एपी

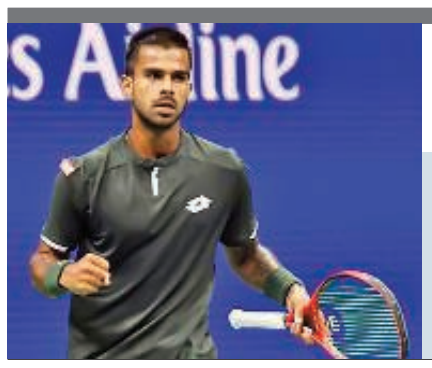

ओलंपिक में जगह बनाने के लिए शीर्ष-80 में आने का लक्ष्य

चेन्नई, प्रेट्र : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कहा कि वह एटीपी रैंकिंग में शीर्ष-100 खिलाड़ियों में जगह बनाने का लक्ष्य बनाए हुए हैं और इसके बाद वह ओलंपिक कोटा हासिल करने की मुहिम में शीर्ष-80 में पहुंचने की कोशिश करेंगे। नागल ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, 'पहले मैं शीर्ष-100 में जगह बनाने की कोशिश करूंगा और फिर शीर्ष-80 में जगह बनाना पर लक्ष्य निर्धारित करूंगा ताकि ओलंपिक में जगह बना सकूं।'

देश में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए सरकार को घरेलू लीगों में निवेश करने की जरूरत है।
– विष्णु वर्धन, भारतीय टेनिस खिलाड़ी

अफरीदी के पंजे ने कराई पाकिस्तान की वापसी

दूसरा टेस्ट ▶ श्रीलंका की पहली पारी 271 रन पर सिमटी

शाहीन ने करियर में पहली बार झटके पांच विकेट

कराची, एएफपी : श्रीलंका के पहली पारी में बढ़त लेने के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट करियर में पहली बार एक पारी में पांच विकेट झटकते हुए श्रीलंका के खिलाफ यहां दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपनी टीम की वापसी की उम्मीद जगाई। 19 साल के इस तेज गेंदबाज ने 77 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्हें दूसरे छोर से नई गेंद के अपने जोड़ीदार मुहम्मद अब्बास (4/55) का अच्छा साथ मिला, जिसके चलते उन्होंने श्रीलंका की टीम को पहली पारी में 271 रन पर रोक दिया। हालांकि, पाकिस्तान की पहली पारी 191 रन पर सिमटी थी। इस तरह श्रीलंका को 80 रन की अहम बढ़त हासिल हुई।

दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में बिना नुकसान के 57 रन बना लिए थे और वह पहली पारी के आधार पर अब सिर्फ 23 रन पीछे है, जबकि उसके सभी 10 विकेट बाकी हैं। सलामी बल्लेबाज आबिद अली 32 और शान मसूद 21 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। मैच में अभी तीन दिन का खेल और होना है। दोनों टीमों के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जिससे दोनों टीमों के बीच इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होड़। यह टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, जिसमें नौ टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसकी तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें जून 2021 में फाइनल में भिड़ेंगी।

इससे पहले दिनेश चांदीमल ने 74 रन और नौवें नंबर के बल्लेबाज दिलरुवान परेरा ने 48 रन बनाकर श्रीलंका को मुकाबले में बनाए रखा। सुबह 80 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद चांदीमल ने धनंजय डिसिल्वा (32) के साथ छठे विकेट के लिए 67 रन और निरोशन डिकवेला (21) के साथ सातवें विकेट के लिए 37 की साझेदारी निभाई। इसके बाद चांदीमल और परेरा ने आठवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। चांदीमल को पार्ट टाइम स्पिनर हैरिस सोहेल ने चलता किया। वह एक गेंद को कट करने की कोशिश में बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच दे बैठे और आठवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। उन्होंने 143 गेंदों की पारी में 10 चौके जड़े।

पहले सत्र को ढाई घंटे का कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान का दबदबा रहा। श्रीलंका ने अपनी पहली पारी सुबह तीन विकेट पर 64 रन से आगे बढ़ाई। इसके बाद अब्बास और अफरीदी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अब्बास ने रात्रि पहरी लसित एंबुलडेनिया को 13 रन के स्कोर पर स्लिप में कैच कराया। बायें हाथ के गेंदबाज अफरीदी ने भी 13 के स्कोर पर एंजेलो मैथ्यूज को चलता किया। पहले टेस्ट में शतक जड़ने वाले डिसिल्वा ने संभल कर बल्लेबाजी की, जिससे श्रीलंका की टीम भोजनकाल तक छह विकेट पर 170 के स्कोर तक पहुंच सकी। परेरा ने नौवें विकेट के लिए विश्वा फर्नांडो के साथ कीमती 36 रन जोड़े। अफरीदी ने तीन गेंदों के अंदर अंतिम दो विकेट लेकर श्रीलंका की पारी का अंत किया।

संक्षिप्त स्कोर

पाकिस्तान (पहली पारी) : 191 (59.3 ओवर)
श्रीलंका (पहली पारी) : 271 (85.5 ओवर)
दिनेश चांदीमल : 74 रन (143 गेंद, 10 चौके)
शाहीन शाह अफरीदी : 26.5-5-77-5
मुहम्मद अब्बास : 27-9-55-4
पाकिस्तान (दूसरी पारी) : 57/0 (14 ओवर)
आबिद अली : 32 रन (42 गेंद, 04 चौके)

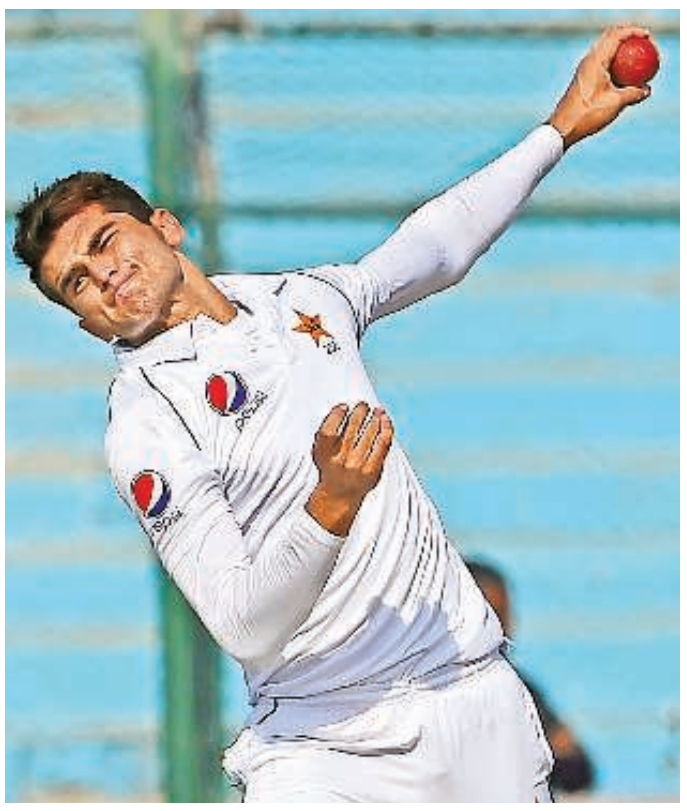

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को गेंदबाजी करते पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। एएफपी

दिल्ली की करारी शिकस्त

रणजी ट्रॉफी

ओंगोले (आंध्र प्रदेश), प्रेट्र : रणजी ट्रॉफी के इस सत्र में दिल्ली के खराब प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पहले मैच में केरल के खिलाफ बमुश्किल हार टालने वाली दिल्ली की टीम को ग्रुप-ए में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपने दूसरे मैच के चौथे व अंतिम दिन शुक्रवार को नौ विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच में आंध्र प्रदेश के मध्यम गति के गेंदबाजों केवी शशिकांत (5/38 व 5/41) और चिपुरापल्ली स्टीफन (2/72 व 5/91) ने शानदार प्रदर्शन किया।

पहली पारी में 215 रनों पर आउट होने वाली दिल्ली के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर सके। ललित यादव (55) के अर्धशतक के अलावा अन्य बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सका। इसके चलते दूसरी पारी में भी उसकी टीम 169 रनों पर आउट हो गई। आंध्र प्रदेश ने पहली पारी में ही 368 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के साथ ही दिल्ली की मुश्किल पहले ही बढ़ा दी थी। आंध्र को दूसरी पारी में 17 रन का लक्ष्य मिला, जो उसने एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। आंध्र की पहली पारी में शतक जड़ने वाले रिकी भुई (144) को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

उत्तराखंड की पारी से लगातार दूसरी हार : उत्तराखंड को रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में अपने लगातार दूसरे मुकाबले में पारी की हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में जम्मू-कश्मीर के हाथों पारी व 253 रन से हारने वाली उत्तराखंड की टीम को ग्रुप-सी के अपने दूसरे मुकाबले में अंतिम दिन शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के हाथों पारी व 65 रनों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, छत्तीसगढ़ की यह इस सत्र में पहली जीत है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ के लिए अजय मंडल ने बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने मैच में कुल आठ विकेट (3/17 व 5/60) लेने के अलावा पहली पारी में आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक (नाबाद 241) जड़ा था। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

उत्तराखंड की पहली पारी 120 रन पर सिमटी थी। जवाब में छत्तीसगढ़ ने पहली पारी सात विकेट 520 रनों पर घोषित कर 400 रनों की बढ़त हासिल की थी। अंतिम दिन उत्तराखंड ने अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 174 रन से आगे बढ़ाई और पूरी पारी 132.4 ओवर में 335 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में तन्मय श्रीवास्तव (58), दीक्षांशु नेगी (69) और सौरभ रावत (61) ने अर्धशतक जड़े, लेकिन वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। इस जीत के साथ छत्तीसगढ़ का घरेलू मैदान पर हार का सिलसिला भी खत्म हो गया। इस जीत से छत्तीसगढ़ को सात अंक मिले, जबकि उत्तराखंड को कोई अंक नहीं मिला।

जम्मू-कश्मीर ने महाराष्ट्र को 54 रन से हराया : यहां हुए ग्रुप-सी के रणजी मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने मेजबान महाराष्ट्र की टीम को 54 रनों से मात दी। जम्मू-कश्मीर की पहली पारी 209 रनों पर सिमटी थी, जिसके जवाब में महाराष्ट्र अपनी पहली पारी में 109 पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर ने 263 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, जिससे महाराष्ट्र को मैच जीतने के लिए 364 रन का लक्ष्य मिला। दूसरी पारी में महाराष्ट्र के बल्लेबाज बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। महाराष्ट्र की ओर से रितुराज गायकवाड़ (71), मुर्तजा ट्रंकवाला (54) और दिग्विजय देशमुख (83) ने उम्दा पारियां खेलीं, लेकिन वो उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकीं। जम्मू-कश्मीर की ओर से दूसरी पारी में मुहम्मद मुदस्सर और उमर नजीर ने चार-चार विकेट झटके। उमर नजीर ने पहली पारी में भी पांच विकेट लिए थे। इस तरह मैच में नौ विकेट लेने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से जम्मू-कश्मीर को छह अंक मिले।

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच मैच ड्रॉ : उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच शुक्रवार को अंतिम दिन रणजी मुकाबला बिना ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ। पहली पारी में आर्यन जुयाल (109) के शानदार शतक और मुहम्मद सैफ (80) के अर्धशतक की बदौलत उत्तर प्रदेश ने 281 रनों का स्कोर बनाया। कर्नाटक ने देवदत्त पडिक्कल (74) और श्रेयस गोपाल (38) के अर्धशतकों की मदद से पहली पारी में 321 रन बनाकर बढ़त हासिल की। कर्नाटक की पहली पारी के दौरान उत्तर प्रदेश के गेंदबाज सौरभ कुमार ने छह विकेट चटकाए। उत्तर प्रदेश ने अलमास शौकत के नाबाद 103 रन से दूसरी पारी तीन विकेट पर 204 रन पर घोषित की। इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान मैच ड्रॉ करने पर सहमत हो गए। कर्नाटक को पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन और उत्तर प्रदेश को एक अंक मिला।

उत्तर प्रदेश का मजबूत प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर

कूच बिहार ट्रॉफी

- **उत्तर प्रदेश की पहली पारी 247 रन पर हुई खत्म**
- **पंजाब की टीम ने 102 रन पर ही गंवा दिए अपने छह विकेट**

अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में केके सिंह के 88 रन की बदौलत उत्तर प्रदेश की पूरी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 67.2 ओवर में 247 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जवाब में पंजाब ने 19 ओवरों में छह विकेट पर 102 रन बना लिए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पंजाब के फतहवीर 20 और अंशुल नेगी एक रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं।

चार दिवसीय मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी उत्तर प्रदेश की टीम की शुरुआत खराब रही। उनके सलामी बल्लेबाज सक्षम 36 गेंदों पर 5 रन और हर्ष त्यागी 37 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए जबकि अंश यादव खाता भी नहीं खोल पाए। समीर रिजवी ने 31 गेंदों पर 26, ऋतुराज शर्मा ने 64 गेंदों पर 16, आदित्य शर्मा ने 51 गेंदों पर 38 रनों का योगदान दिया। कृतिज्ञा केके सिंह ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 85 गेंदों पर 88 रन बनाए। पूर्णांक त्यागी व ऋषभ बंसल जीरो पर चल बने जबकि कुणाल त्यागी एक ही रन बना सके। वहीं सूर्यकांत चौहान ने नाबाद 43 रन बनाए। पंजाब की ओर से गेंदबाज दीपांशु चड्डा ने छह और हर्षदीप व अंशु नेगी ने क्रमशः 2-2 विकेट हासिल किए।

जवाब में पंजाब की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पुखराज मान 33 गेंदों पर 20 और अंशु चौधरी 16 गेंदों पर 16 बनाकर पवेलियन लौट गए। जसकरनवीर सिंह ने 8, सलिल अरोड़ा ने दो, अभय चौधरी ने 26 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के लिए गेंदबाज पुर्णांक त्यागी ने तीन, कुणाल त्यागी ने दो और सूर्याकांत ने एक विकेट हासिल किया।

बेस और ओवरटन इंग्लैंड की टीम में

क्रिकेट डायरी

लंदन, एएफपी : डोमिनिक बेस और क्रेग ओवरटन दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए इंग्लैंड के तीन बीमार गेंदबाजों के विकल्प के तौर पर टीम के साथ जुड़ेंगे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को बताया कि समरसेट के दोनों गेंदबाजों को स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफ्रा आर्चर और जैक लीच के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। ये तीनों गेंदबाज बीमारी के कारण शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ शुरू हुए अभ्यास मैच का हिस्सा नहीं थे।

ईसीबी के मुताबिक, 'स्पिनर डोमिनिक बेस और तेज गेंदबाज क्रेग ओवरटन को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। दोनों शनिवार को जोहानिसबर्ग में टीम के साथ जुड़ेंगे।' पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे और टी-20 सीरीज होगी।

बॉक्सिंग डे टेस्ट से बाहर हुए बावुमा

जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम के बल्लेबाज तेंबा बावुमा मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के साथ होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने ट्वीट के जरिये इसकी पुष्टि की है। ट्वीट में लिखा गया है, 'बल्लेबाज तेंबा बावुमा पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल सकेंगे। उन्हें ग्रेड 1 हिप फ्लेक्सर मसल स्ट्रेन है। गुरुवार को हुए स्कैन में इस चोट का पता चला।' सीएसए ने कहा है कि बावुमा टीम के कैंप में बने रहेंगे और मेडिकल स्टाफ की सलाह पर रिहैब शुरू करेंगे। उनके मैदान पर सात से 10 दिनों में वापसी की उम्मीद है।

कैलिस की नियुक्ति पर खादा ने जताई खुशी

दुबई : दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा ने जैक कैलिस को उनकी टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे खेल के लिए अच्छा फैसला बताया है।

पिछले कुछ सप्ताह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट (सीएसए) कई बड़े उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है और कई पूर्व खिलाड़ियों को टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैलिस के अलावा मार्क बाउचर को टीम का कोच बनाया गया है, जबकि चार्ल लैंगवेल्ट को गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को भी सीएसए का अंतिम निदेशक नियुक्त किया गया है। रबादा ने कहा, 'जैक कैलिस जैसे व्यक्ति का साथ होना आश्चर्यजनक है। वह खेल के महान खिलाड़ी हैं। ऐसा ही मार्क बाउचर के साथ है। चार्ल लैंगवेल्ट की वापसी भी शानदार है। मैं उनके साथ काम करने का लुत्फ उठाऊंगा। वे इस स्तर पर बहुत लंबे समय तक खेले हैं।'

विविध

टायर किलर से आतंकवादियों के मंसूबों पर ब्रेक

अजब सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा

आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने को भारतीय सेना हर वक्त चौकन्ना है। दो दशकों में हुए आतंकवादी हमलों से सबक लेते हुए सरकार ने आतंक व नक्सलवाद से निपटने के लिए जवानों को आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा उपकरणों से लैस किया है। ग्रेटर नोएडा के एक्सपोमार्ट में लगे सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी में कई उपकरण ऐसे हैं, जिनसे देश की सीमा पर खड़े जवानों के हाथ न केवल मजबूत हुए है, बल्कि आतंकवाद के मंसूबों पर भी ब्रेक लगा रहे है।

नई दिल्ली स्थित प्वाइंट ब्लैंक रेंज प्राइवेट लिमिटेड की टार्च, टायर किलर, मेटल डिटेक्टर समेत कई उपकरण सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। कंपनी के एमडी वाइपी मदन ने बताया कि इकाई 1991 से सुरक्षा उपकरण बना रही है। 1997 में सेना से करार हुआ था। इसके बाद से सुरक्षा उपकरण जवानों के हाथों को मजबूत किए हुए है। फ्रांस के नीस में हुए एक आतंकी हमले के बाद उन्होंने देश में इस तरह के आतंकी हमले की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए एक टायर किलर (पोर्टेबल रोड ब्लाक) भी तैयार किया है। इसका वजन बेहद कम है। एक व्यक्ति ही टायर किलर को अकेला उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। कम वजन का होने के चलते टायर किलर सेना के जवानों की पहली पसंद है। आतंकवादियों के वाहनों की गति पर विराम लगाने में टायर किलर सेना के लिए कारगर साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि विपरित दिशा में सड़कों पर वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए कई राज्यों की पुलिस भी टायर किलर का सहारा ले रही है। दरअसल, गलत दिशा में आ रही गाड़ियों के टायर पंक्चर कर देगी। कंपनी की टार्च भी सेना के प्रयोग में लाई जा रही हैं। कंपनी के एमडी के मुताबिक कई टार्च ऐसी हैं, जिनके प्रयोग से रात को डेढ़-दो किमी दूर खड़े व्यक्ति को आसानी से देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोमार्ट में चलरही प्रदर्शनी में सुरक्षा उपकरण को दिखाते प्वाइंट ब्लैंक रेंज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी वाइपी मदन। राजेश गौतम

क्या होते हैं टायर किलर

टायर किलर वाहनों के लिए एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर काम करता है। टायर किलर में उभरे बड़े-बड़े कांटे गाड़ियों के पहियों में घुस जाएंगे और पंक्चर कर देंगे। देश के कई राज्यों में पुलिस भी अपराधियों के वाहनों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीकी का प्रयोग महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में सफल हो चुका है। बता दें कि नालेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपोमार्ट में चल रहे तीन दिवसीय सेफ्टी और सिक्योरटी आइएफएसईसी एक्सपो में सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आयोजित प्रदर्शनी में भारत समेत चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान समेत 15 देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने घरेलू और अंतराष्ट्रीय ब्रांडों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

कोर्ट के बाहर ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या

जासं, रुड़की : उत्तराखंड में रामनगर कोर्ट के बाहर नगला कुबड़ा गांव के प्रधान की बाइक सवार बदमाशों ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटनाक्रम को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। एसएसपी के अनुसार सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। वहीं, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने देर शाम आगजनी कर डाली। प्रधान की हत्या के संदेह में दो घरों में आग लगा दी। तीन मोटर साइकिल, दो कार और एक ट्रैक्टर भी आग के हवाले कर दिया। आग से घिरे पांच लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। घटनाक्रम के चलते क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

झबरेड़ा थाना क्षेत्र के नगला कुबड़ा गांव के प्रधान कमर आलम शुक्रवार को रामनगर कोर्ट आए थे। देर शाम करीब पौने छह बजे ग्राम प्रधान कोर्ट से बाहर निकले। पैदल ही वह कुछ दूर खड़ी कार की तरफ जा रहे थे। इसी बीच पीछे से बाइक सवार दो बदमाश वहां आए। बाइक से उतरकर एक बदमाश प्रधान के करीब पहुंचा। इससे पहले कि ग्राम प्रधान कमर आलम कुछ समझ पाते, एक बदमाश ने तमंचा सटाकर उनके सिर पर गोली मार दी। कमर आलम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अयोध्या में स्थापित होगा आयुष विश्वविद्यालय

राजीव दीक्षित, लखनऊ

आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी परंपरागत परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय को अब अयोध्या में स्थापित करने का इरादा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आयुष विभाग ने अयोध्या के जिला प्रशासन को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए पत्र लिखा है।

योगी सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयुष विवि की स्थापना का फैसला किया है। पहले इस विवि की स्थापना के लिए आयुष विभाग ने बाराबंकी की नवाबगंज तहसील में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बगल में 32 एकड़ जमीन चिन्हित की थी। फिर राजधानी की चक गंजरिया सिटी में कैंसर इंस्टीट्यूट के बगल में स्वास्थ्य विभाग की 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। इसी बीच आयुष विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान सीएम ने अयोध्या में आयुष विवि की स्थापना का निर्देश दिया। चूंकि लखनऊ में पहले से ही कई विवि और शिक्षण संस्थान संचालित हैं, इसलिए उनकी मंशा है कि संसाधनों के विकेंद्रीकरण के लिहाज से आयुष विवि की स्थापना अयोध्या में की जाए। इससे अयोध्या जिले को नई पहचान भी मिलेगी।

आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपये आवंटित हैं। आयुष विभाग ने उप्र राज्य आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। आयुष विभाग के अधीन प्रदेश में आठ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नौ राजकीय होम्योपैथी कॉलेज और दो राजकीय यूनानी महाविद्यालय संचालित हैं। आयुष विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने पर यह सभी महाविद्यालय उससे संबद्ध होंगे।

बठिंडा एम्स में 23 से शुरू होगी नौ विभागों की ओपीडी

साहिल गर्ग, बठिंडा

बठिंडा में 23 दिसंबर से शुरू होने वाले एम्स में लोग अब 10 रुपये की पर्ची लेकर इलाज करवा पाएंगे। इसका समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। रजिस्ट्रेशन 8 बजे शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहां पर सिर्फ ओपीडी शुरू होगी। चेकअप कराने आए मरीज को कोई परेशानी होने पर इमरजेंसी सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए छह व चार बेड वाले दो अलग-अलग हॉल होंगे। इमरजेंसी सेवा में आइसीयू की तरह सुविधा मिलेगी। एम्स में सभी जरूरी मशीनें पहुंच चुकी हैं। इनकी टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। कुछ मशीनें अभी बाकी हैं, जो धीरे-धीरे आ जाएंगी। इसको लेकर गुरुवार को बठिंडा के एम्स में अधिकारियों की मीटिंग भी हुई।

एम्स की शुरुआत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन पहुंचेंगे। यहां पर शुरुआती समय में नौ विभागों की ओपीडी शुरू होगी, जबकि कुल 12 विभागों की यहां पर सेवाएं मिलेंगी। एम्स में ओपीडी के लिए 750 बेड हैं। इसको लेकर सोमवार को बठिंडा में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

ये हैं सुविधाएं

10 काउंटर रजिस्ट्रेशन के लिए होंगे
10 रुपये होगी ओपीडी की पर्ची
8 बजे सुबह से होगा रजिस्ट्रेशन
9 से 2 बजे तक मिलेगी ओपीडी सेवा
500 लोगों के बैठने का इंतजाम है ऑडिटोरियम में
अल्ट्रासाउंड के अलावा एक्स-रे व कलर डॉपलर भी होगा
बायो केमिस्ट्री व एथेलॉजी के भी होंगे टेस्ट

कांग्रेस विधायक छौक्कर व बेटे पर दर्ज होगी एफआइआर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- **गलत दस्तावेज देकर गुरुग्राम में रियल एस्टेट का फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप**
- **गुरुग्राम में गबन के आरोपित अक्षय ऊर्जा विभाग के अधिकारी की फिर जांच, 140 लोगों को दी थी सब्सिडी**

गुरुग्राम में रियल एस्टेट कारोबार के लिए गलत दस्तावेज देकर लाइसेंस हासिल करने के आरोप में समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे विकास छौक्कर पर एफआइआर दर्ज होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो, सीपीजीआरएमएस और सोशल मीडिया शिकायत निवारण ट्रैकर की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक में कांग्रेस विधायक और उनके बेटे पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर एवं आयोजना विभाग की एक शिकायत पर यह निर्देश दिया।

आरोप है कि गुरुग्राम में बिल्डर मैसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारक विकास छौक्कर और उनके बेटे ने लाइसेंस लेने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में शुमार समालखा के विधायक पर एफआइआर से हरियाणा की सियासत गरमाने के आसार हैं।

डॉ. राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी भूपेश्वर दयाल ने सांस्कृतिक कार्य विभाग की भ्रष्टाचार से संबधित एक शिकायत पर उन्होंने फिर से जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। गुरुग्राम में अक्षय ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी पर गबन के मामले में फिर से जांच होगी। पहले इस अफसर पर एफआइआर दर्ज की गई थी जिसे बाद में रद कर दिया गया। विभागीय कार्रवाई में कोई रिकवरी नहीं दिखाई गई जिस पर संज्ञान लेते हुए डॉ. गुप्ता ने सभी 140 लाभार्थियों को सब्सिडी देने की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह बिजली विभाग में कलेक्शन एजेंसी ने उपभोक्ताओं से बिलों की वसूली के बावजूद पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया। इसकी जांच भी होगी।

उच्चतर शिक्षा विभाग में अनियमितताओं की शिकायत पर डॉ. गुप्ता ने निर्देश दिया कि संबंधित एडीसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज कमेटी रेवाड़ी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाए। एक अन्य मामले में थानेसर निवासी ऊषा शर्मा ने शिकायत की थी कि वर्ष 2016 में शिक्षा विभाग में कार्यरत उनके पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें उचित लाभ नहीं मिल। उनकी शिकायत पर विचार करते हुए उन्हें सभी तरह के लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

नगर एवं आयोजना विभाग की सचिव रिचा राठी को सीएम विंडो का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक 31 दिसंबर को बुलाई गई है ताकि वे आपसी समन्वय स्थापित कर शिकायतों का जल्द निपटान कर सकें।

कोठी विवाद में लोकायुक्त ने तलब कर रखी गुम हुई फाइल

समालखा में धर्म सिंह छौक्कर के कोठी विवाद में लोकायुक्त ने पहले ही गुम हुई फाइल तलब कर रखी है। पूर्ववर्ती सरकार में छौक्कर की कोठी को कालोनी बताकर पास कर दिया गया था। जब लोकायुक्त की जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो कालोनी को पास करने की रिकार्ड फाइल ही लापता हो गई। शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव को लोकायुक्त ने केस की फाइल ढूंढने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। इस फर्जीवाड़े में समालखा नगरपालिका के पांच अधिकारियों को चार्टशीट किया जा चुका है, जबकि कई आइएएस अफसरों से जवाब तलब किया गया है। लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल 8 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

2014 से 2018 के बीच की शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष अभियान

सीएम विंडो पर शिकायतों की सुनवाई में लेटलतीफी पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2014 से 2018 के बीच की सभी शिकायतों का निपटारा 10 जनवरी तक कर दें। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। नोडल अधिकारियों का वाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान कर तेजी से शिकायतों का निपटारा किया जा सके। ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 21 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

पहली बार सामने आई दिमाग चकराने वाली क्रॉस वर्ड पजल

1913 में आज ही दुनिया की पहली क्रॉस वर्ड सामने आई। ऑर्थर वेन द्वारा तैयार इस पजल को न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार में साप्ताहिक फन पेज पर प्रकाशित हुआ। अखबार ने इसके जरिये क्रिसमस संस्करण में पाठकों का मनोरंजन किया।

मैडम क्यूरी और उनके पति ने रेडियम की खोज की

1898 में आज ही फ्रांस की भौतिकविद् मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। यूरेनियम को अलग करने पर उसमें उन्हें रेडियोधर्मी तत्व मौजूद मिले थे। मैडम क्यूरी पहली महिला थीं जिन्हें 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।

अमीन सयानी की आवाज के जादू का हर कोई कायल

अमीन सयानी का जन्म 1932 में आज ही के दिन बंबई (अब मुंबई) में हुआ। वह देश के चोटी के रेडियो उद्घोषक हैं। रेडियो पर आने वाले बिनाका गीत माला को अमीन सयानी अपनी खनकती आवाज के साथ पेश करते थे, जिसे आज भी लोग नहीं भूले हैं। उन्होंने कई विदेशी रेडियो कार्यक्रमों के लिए भी अपनी आवाज दी है। वह अब तक 50 हजार से ज्यादा कार्यक्रम और करीब 20 हजार जिंगल कर चुके हैं। 1992 में उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा। उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

इधर-उधर की

पेड़ पर चढ़े कुत्ते को उतारने के लिए करनी पड़ी मशक्कत

कैलिफोर्निया, एजेंसी : लेथरॉप मेंटेका अग्निशमन जिले की एक फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। अग्निशमनकर्मियों को एक कुत्ते को बचाने के लिए बुलाया गया था। दरअसल, जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि इसके बाद वह पेड़ से उतर नहीं सका। इसके बाद अग्निशमनकर्मियों ने सीढ़ी लगाकर उसे उतारा। कुत्ता सुरक्षित उतारा गया जबकि बिल्ली इस दौरान कूद कर भाग गई। फेसबुक पोस्ट में इन कर्मियों ने लिखा है कि हम सभी आश्वस्त हैं कि अब वह किसी बिल्ली का पीछा करने से पहले हजार बार सोचेगा। अब लोग इस पोस्ट की जमकर सराहना कर रहे हैं। पोस्ट को हजारों की संख्या में लाइक और कमेंट मिले हैं। लोग कुत्ते को लेकर लोटपोट कर देने वाले कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि पेड़ पर चढ़ना बिल्लियों का काम है, बेवकूफ कुत्ते।

शोध अनुसंधान

मशीन लर्निंग से हार्ट अटैक का लग सकता है अनुमान

शोधकर्ताओं ने दिल का दौरा (हार्ट अटैक) और हृदय गति रुकने के खतरों का सालों पहले ही अनुमान लगाने का एक नया तरीका खोज निकाला है। उन्होंने पाया कि कंप्यूटर के उपयोग से मशीन लर्निंग की मदद से हार्ट अटैक और कार्डिक डेथ के खतरों को लंबे समय पहले ही भांपा जा सकता है। इस तरीके से इन खतरों का मौजूदा विधियों की तुलना में ज्यादा सटीक अनुमान भी लगाया जा सकता है। कार्डियोवेस्कुलर रिसर्च पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार, मौजूदा विधियों की तुलना में मशीन लर्निंग हार्ट अटैक और कार्डिक डेथ के खतरे का बेहतर अनुमान लगा सकता है। अमेरिका के बायोमेडिकल इमेजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कहा, 'हमारे अध्ययन से जाहिर होता है कि मशीन लर्निंग की मदद से हार्ट अटैक और कार्डिक डेथ जैसे खतरों के कारकों का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।' -आइएएनएस

गर्भावस्था में शाम को ज्यादा खाने से बढ़ सकता है वजन

शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि शाम सात बजे के बाद बहुत ज्यादा खाने के चलते गर्भवती महिलाओं का वजन बढ़ सकता है। उन महिलाओं में भी इसी तरह वजन बढ़ने का खतरा पाया गया, जिनका गर्भावस्था के दौरान खानपान सही नहीं रहता है। अध्ययन के अनुसार, शिशु के जन्म के करीब डेढ़ वर्ष बाद इस तरह के खानपान वाली महिलाओं का वजन पांच किलो बढ़ने की संभावना तीन गुना ज्यादा हो सकती है। यह निष्कर्ष महिलाओं के दो समूहों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। सिंगापुर के केके वूमेंस एंड चिल्ड्रेन अस्पताल के शोधकर्ता लोय सी लिंग ने कहा, अध्ययन से जाहिर होता है कि गर्भावस्था में रात में खराब खानपान का संबंध वजन बढ़ने से है। -आइएएनएस

अमेरिका में मिला दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म वन

- वलुआ पत्थर की खदान में मिला 38.6 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों का व्यापक झुंड
- शोधकर्ताओं का अनुमान, न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया तक फैले हो सकते हैं ये वन

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने कैट्सकिल पर्वत की तलहटी में 3,000 वर्ग मीटर के जंगल की मैपिंग की है। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिका में बलुआ पत्थर की खदान में लगभग 38.6 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों का एक व्यापक झुंड मिला है। वैज्ञानिक इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म वन के अवशेष मान रहे हैं। अमेरिका के बिंघमटन विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क राज्य संग्रहालय के शोधकर्ताओं के अनुसार काहिरा के जीवाश्म जंगल न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया और उससे आगे तक फैल गए होंगे। ये जंगल अब तक के सबसे पुराने गिल्बोआ स्थित जंगलों से 20 से 30 लाख साल पुराने हैं। ये जंगल भी न्यूयॉर्क राज्य में हैं और काहिरा क्षेत्र से लगभग 40 किमी दूर हैं।

करंट बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि यह खोज पेड़ों के विकास और जिस दुनिया में हम रहे हैं उसके बदलाव पर एक नई रोशनी डालती है। ब्रिटेन के कार्डिफ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं सहित टीम ने हडसन घाटी में कैट्सकिल पर्वत की तलहटी में परित्यक्त खदान के 3,000 वर्ग मीटर के जंगल की मैपिंग की। शोध के सह लेखक और कार्डिफ यूनिवर्सिटी के क्रिस बेरी ने कहा कि यह छोटे से मध्यम आकार के शंकुधारी दिखने वाले पेड़ों के साथ एक खुले जंगल की तरह दिखाई देता था।

शोध से पता चलता है कि जंगल में कम से कम दो प्रकार के पेड़ थे। एक तीसरे प्रकार के पेड़ का भी एक एकल उदाहरण भी देखने को मिला। माना जा रहा है कि यह लाइकोपोड हो सकता था। ये सभी पेड़ बीज के बजाय केवल बीजाणुओं का उपयोग कर विकसित हुए। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन पेड़ों की जड़ें कई मीटर तक लंबी रही होंगी, जो एक नेटवर्क के रूप में कई एकड़ों में फैल सकती हैं।

लंबी उड़ानों की थकान मिटाने में मदद करेगी नई तकनीक

तलाशी राह ▶ अमेरिका के शोधकर्ताओं ने तैयार की एल्गोरिदम

शरीर की आंतरिक घड़ी को रखेगी नियंत्रित

ज्यादा लंबी दूरी तक हवा में सफर करने से बिगड़ जाती है सर्कैडियन रिदम। फाइल

न्यूयार्क, प्रेट्र : लंबी हवाई यात्राओं से होने वाली थकान से निपटने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जिनको बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं। इससे वे बेहतर गुणवत्ता की नींद प्राप्त कर सकते हैं।

अमेरिका के रेनसेलर पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने बताया कि शरीर की आंतरिक घड़ी में परिवर्तन होने से लोगों को उड़ानों में थकान का अनुभव होता है। आंतरिक घड़ी को सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है। यह शरीर की एक आंतरिक प्रक्रिया है जो जागने और सोने के चक्र को नियंत्रित रखती है। इसके साथ ही यह हमारे मेटबॉलिज्म, हार्मोन स्राव और मस्तिष्क तक को प्रभावित करती है। यदि हम ठीक से सो नहीं पाते तो इससे पूरा सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाता है।

इस तरह काम करती है तकनीक : 'पीएलओएस-वन' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि नई तकनीक में शरीर में एक छोटी-सी डिवाइस लगाई जाती है। यह डिवाइस शरीर की बायोमीट्रिक जानकारी को इकट्ठा करती है। इसके बाद शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई एल्गोरिद्म द्वारा उस जानकारी का विश्लेषण कर व्यक्ति को सोने और लाइट के बेहतर संयोजन के बारे में बताया जाता है, जिससे बिगड़े हुए सर्कैडियन रिदम को सुधारा जाता है।

इस अध्ययन के सह लेखक अगुंग जूलियस ने बताया कि इस एल्गोरिदम और किसी व्यक्ति के सर्कैडियन रिदम के गणितीय मॉडल का उपयोग करते हुए इस तकनीक से सटीकता से यह बताया जा सकता है कि उस व्यक्ति के सर्कैडियन रिदम को सही करने के लिए व्यक्ति को सोते समय कितनी रोशनी रखनी चाहिए। साथ ही उसे कब और कितना सोना चाहिए।

सर्कैडियन रिदम सही रखना बेहद जरूरी : शोधकर्ताओं ने बताया कि जब किसी व्यक्ति का सर्कैडियन रिदम उस टाइम जोन से मैच नहीं करता, जिसमें हम होते हैं तो शरीर की ऊर्जा, सतर्कता और अन्य जैविक क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की सर्कैडियन रिदम भिन्नता को रक्त या लार परीक्षण से निर्धारित किया जाता है, जो हार्मोन मेलाटोनिन के स्तर को मापता है।

आपकी लोकेशन का हर हाल में पता लगा लेगा फेसबुक

वाशिंगटन, आइएएनएस : फेसबुक यूजर ने यदि सेटिंग ऑफ कर रखी हो तो भी यूजर की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। फेसबुक ने अमेरिकी सीनेटरों के सामने यह स्वीकार किया है। सीनेटर क्रिस्टोफर ए कून्स और जोश हावले को भेजा गया पत्र अब ट्विटर पर वायरल हो गया है। फेसबुक के डिप्टी चीफ प्राइवेसी आफिसर रॉब शेर्मान ने इसका ब्योरा दिया है। उन्होंने कहा है कि यूजर ने अपने अकाउंट से ट्रैकिंग सर्विस ऑफ कर रखा हो तब भी उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।

फेसबुक ने यह जानकारी दो सेनेटरों द्वारा मांगी गई जानकारी के बाद दी है। उन्होंने तर्क दिया था कि किसी भी शख्स की लोकेशन की जानकारी के कई फायदे हो सकते हैं जिसमें विज्ञापन दिखाने से लेकर हैकर्स से लड़ने और गलत जानकारी से निपटने जैसी चीजें शामिल हैं।

फेसबुक का कहना है कि उसके यूजर के लोकेशन की जानकारी उन चीजों से मिल जाती है जिनमें वो टैग होता है या फिर अपने चेक इन डिटेल्स पेज पर शेयर करता है। या फिर दोस्तों के साथ कहीं डिनर पर जाता है। यूजर फेसबुक के शॉपिंग सेक्शन में अपनी खरीदी के लिए पता शेयर कर सकते हैं वहीं जिस सिस्टम से यूजर ने फेसबुक यूज किया है वहां का आइपी एड्रेस भी उसकी लोकेशन बता देता है। फेसबुक का यह बयान जारी होने के बाद एक बार फिर निजता का प्रश्न उठने लगा है।

फिल्म रिव्यू

ढेर सारे मसाले, पर स्वाद फीका

★★★

दबंग 3

मुख्य कलाकार : सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, किच्चा सुदीप, सई मांजरेकर, डिंपल कपाडिया
निर्देशक : प्रभु देवा
अवधि : 2 घंटे 42 मिनट

वर्ष 2010 में आई 'दबंग' में सलमान खान के किरदार चुलबुल पांडे की दबंगई दर्शकों को खासी पसंद आई थी। इस फिल्म से सोनाक्षी सिन्हा ने अपने अभिनय करियर का आगाज किया था। दो साल बाद इसकी सीक्वल आने पर पहली फिल्म की कामयाबी, धमाकेदार प्रचार, लोकप्रिय गाने और सलमान खान की मौजूदगी ने मसालों के साथ उसे गाढ़ा किया था। अब करीब सात साल के अंतराल के बाद इस सीरीज की प्रीक्वल आई है यानी कहानी अब चुलबुल पांडे के अतीत में जाती है। उसमें चुलबुल पांडे के पुलिस में भर्ती होने की कहानी बताई गई है। उसका असली नाम धाकड़ चंद पांडेय होता है।

'दबंग 3' में चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिनहुड पांडे का प्रमोशन हो चुका है। उसका सात साल का बेटा है। अपने पिता और भाई मक्खी (अरबाज खान) के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। कहानी का आगाज एक शादी में डकैती रोकने के लिए चुलबुल पांडे की धमाकेदार एंट्री से होता है। पिछली सीरीज से यह स्थापित किया जा चुका है कि चुलबुल अकेले चालीस-पचास लोगों को धूल चटाने में सक्षम है। जवान लड़कियों को अगवा कर उन्हें बेचने जा रहे गिरोह का भंडाफोड़ करने पर पता चलता है उसका सरगना बाली (सुदीप किच्चा) है। वहां से चुलबुल पांडे की कहानी फ्लैशबैक में आती है। युवा चुलबुल की पिछली जिंदगी से पर्दा उठता है। वह खुशी (सई मांजरेकर) से प्यार करता है, लेकिन बाली का दिल उस पर आ जाता है। बाली और चुलबुल में खुशी को लेकर ठन जाती है। खुशी वास्तव में रज्जो (सोनाक्षी सिन्हा) की मौसी की बेटी होती है। वर्तमान में बाली राजनेता बन चुका है। चुलबुल पांडे की दबंगई और बाली की ताकत में टकराव होने पर पुरानी रंजिश को लेकर एकदूसरे के पीछे पड़ना, डायलॉगबाजी और धारदार हथियारों के साथ एक्शन होना लाजमी है।

'दबंग 3' के निर्देशन की कमान इस बार प्रभु देवा को सौंपी गई है। उन्होंने सलमान खान के परिचित अंदाज को फिर से पेश किया है। 'दबंग 3' में पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन ज्यादा है। खलनायक को ताकतवर दिखाया गया है, हालांकि लगता नहीं है। 'दबंग 3' में एक्शन, कॉमेडी, इमोशन आदि भावों के दृश्यों के सारे मसाले हैं, लेकिन उन्हें समुचित तरीके से मिलाया नहीं गया है। इसीलिए थियेटर से निकल कर कोई स्वाद याद नहीं रहता। लेखक-निर्देशक ने दृश्यों में तारतम्य बिठाने की अधिक कोशिश नहीं की है। इस बार कहानी पिछड़ गई है। गानों के फिल्मांकन में भीड़ है। गाने भी खूब सारे हैं। इस बार कहानी खुद सलमान खान ने लिखी है।

इस बार भी पिछली फिल्म की कामयाबी को भुनाने की कोशिश की गई है। सलमान खान के अलावा किसी भी कलाकार या किरदार को उभारने का प्रयास नहीं किया गया है। खलनायक बने किच्चा सुदीप प्रभावित नहीं कर पाते हैं। 'वास्तव', 'अस्तित्व' जैसी फिल्म का निर्देशन कर चुके महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर ने 'दबंग 3' से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया है। गांव की भोली-भाली मासूम लड़की के रूप में वह सुंदर लगी हैं। सोनाक्षी सिन्हा समेत सभी अन्य कलाकार बेअसर रहते हैं। फिल्म में अनेक विसंगतियां भी हैं। बाली को खाई में गिराकर मार देने के बाद उसके बचने की वजहों का कोई जिक्र नहीं है। सोहेल खान का कैमियो क्यों रखा, उसकी वजह स्पष्ट नहीं होती। पर्यावरण, पानी बचाओ, एसिड अटैक, दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर संदेश देने की कोशिश जबरन ठूंसी गई लगती है। बहरहाल, फिल्म के अंत में 'दबंग 4' में चुलबुल के राजनेता के तौर पर आने का संकेत दिया गया है। **स्मिता श्रीवास्तव**

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

प्लास्टिक कचरे का निपटान

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुरीगंगा नदी तट पर रंग-बिरंगी चादर-सी दिखने वाले यह प्लास्टिक चिप्स हैं, जिन्हें प्लास्टिक कचरे की रीसाइक्लिंग से तैयार किया गया है। दुनियाभर में पर्यावरण की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय बने प्लास्टिक वेस्टेज से निपटने के लिए बांग्लादेश ने काफी ठोस कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 633,129 टन कचरा निकलता है। इसमें से फिलहाल करीब साठ प्रतिशत प्लास्टिक कचरे की रीसाइक्लिंग की जा रही है। इससे बांग्लादेश को प्रतिवर्ष कई करोड़ डॉलर का फायदा हो रहा है। एएफपी

23 करोड़ साल पुराना डायनासोर का कंकाल

ब्राजील के साओ जोआओ पोलेशिन रिसर्च सपोर्ट सेंटर के वैज्ञानिकों ने कापा में मांसाहारी डायनासोर बुरिओलेस्टेस स्कल्जी का जीवाश्म खोजा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जीवाश्म 233 मिलियन वर्ष(करीब 23 करोड़ साल) पुराना है। उनका कहना है कि यह दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्मों से एक है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मांसाहारी डायनासोर की यह प्रजाति पृथ्वी से समाप्त हो गई थी। इस स्थान पर खोदाई में और भी जीवाश्म मिलने की संभावना है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'छपाक' के लिए सोचे गए थे दो शीर्षक : मेघना गुलजार

फिल्म का शीर्षक उस फिल्म की कहानी का निचोड़ होता है। शीर्षक यानी टाइटल में फिल्म की कहानी की झलक मिल जाती है, लेकिन किसी फिल्म का शीर्षक सोचना आसान काम नहीं होता है। दर्शकों को आकर्षित करने के साथ ही उसमें कहानी का सार भी होना चाहिए। बात की जाए अगर 'छपाक' की तो इस फिल्म का शीर्षक कहानी की ओर इशारा करता है। यह फिल्म एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी से प्रेरित है। 'छपाक' की आवाज तब आती है, जब कोई तरल पदार्थ तेजी से फेंका जाता है। इस टाइटल को रखने का आइडिया फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार का ही था। मेघना का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए दो शीर्षक सोच रखे थे। वह बताती हैं कि उन्होंने 'गंधक' और 'छपाक' दो शीर्षकों पर सोचा था। मेघना ने बताया कि गंधक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हिंदी नाम है। फिल्म में टाइटल गाना डालना पड़ता है। ऐसे में गंधक शब्द गाने के लिए बेहद कड़क लफ्ज हो जाता। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म का नाम 'छपाक' रखा। मेघना बताती है कि उन्हें 'छपाक' शब्द में जो सबसे दिलचस्प बात लगी, वह यह थी कि यह शब्द बेहद नरम और काव्यात्मक है। एसिड भले ही तरल पदार्थ हो, लेकिन वह बहुत ही हानिकारक हो सकता है और हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि 'छपाक' शब्द खतरनाक एसिड से बिल्कुल उलट है। इस शब्द में एक नरमी है। इस वजह से फिल्म का नाम 'छपाक' रख दिया गया। फिल्म में दीपिका पादुकोण मालती के किरदार में हैं। रणवीर सिंह से शादी के बाद यह दीपिका की रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी। 'छपाक' 10 जनवरी को रिलीज होगी।

'स्ट्रीट डांसर 3 डी' में मुकाबला... गाना : रेमो

हिंदी सिनेमा में पुराने हिट गानों का रीमिक्स जोरशोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कड़ी में अब वरुण धवन और श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3' डी में मुकाबला गाना नजर आएगा। 25 साल पहले इस हिट गाने पर प्रभु देवा के डांस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके डांस को किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन सरीखा बताया गया था। एक बार फिर इस सुपरहिट गाने को 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में रीक्रिएट किया गया है। इस बार प्रभु देवा के डांस स्टेप्स को मैच करते हुए वरुण धवन और श्रद्धा कपूर नजर आएंगे। इस रीमिक्स गाने को यश नारवेकर और परंपरा ठाकुर ने गाया है। उसे तनिष्क बागची ने संगीतबद्ध किया है। उन्होंने ही गानों के नए बोल लिखे हैं। गाने को कोरियोग्राफ राहुल शेट्टी और राजू सुंदरम ने किया है। कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा खुद भी प्रभु देवा के प्रशंसक हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रभु देवा के आइकोनिक गाने मुकाबला पर डांस सीक्वेंस रखेंगे। रेमो कहते हैं, 'बच्चे के तौर पर वह गाना मुझे बहुत पसंद था। यह गाना हमारी टीम में भी सभी के लिए खास था। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को गाने का नया वर्जन उतना ही पसंद आएगा, जितना मूल गाना आया था।' यह फिल्म अगले साल 24 जनवरी को रिलीज होगी।

पहली बार दिखेगी श्रद्धा और रणबीर कपूर की जोड़ी

शुक्रवार को एक के बाद एक लगातार दो फिल्मों का एलान किया गया। 'प्यार का पंचनामा', 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'दे दे प्यार दे' जैसी फिल्मों के निर्माता लव रंजन ने रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म बनाने की घोषणा की। लव की प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई। लव रंजन और अंकुर गर्ग के संयुक्त निर्माण में बनने वाली यह फिल्म 26 मार्च 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म में रणवीर और श्रद्धा पहली बार एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे। रणवीर इन दिनों फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद अजय देवगन फिल्म्स की तरफ से अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर एक्शन कॉमेडी फिल्म की घोषणा की गई। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को साल 2021 की गर्मियों में रिलीज किया जाएगा। इंद्र कुमार इससे पहले 'इश्क', 'मस्ती' व 'टोटल धमाल' जैसी फिल्मों में अजय को निर्देशित कर चुके हैं। इस साल रिलीज हुई फिल्म 'दे दे प्यार दे' के बाद रकुलप्रीत के साथ अजय की यह दूसरी फिल्म होगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इससे पहले फिल्म 'मरजावां' में रकुल प्रीत के साथ काम कर चुके हैं। फिल्मों के शीर्षकों के बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है।

विधु विनोद चोपड़ा की 'शिकारा' का पहला मोशन पोस्टर आया

विधु विनोद चोपड़ा की आने वाली हिस्टोरिकल रोमांटिक फिल्म 'शिकारा' का पहला मोशन पोस्टर शुक्रवार को रिलीज किया गया। फिल्म विश्लेषक तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म का ट्रेलर आगामी 7 जनवरी 2020 को रिलीज किया जाएगा। फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में 1990 की वे घटनाएं होंगी, जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से हटाया गया था। चोपड़ा ने 'परिंदा', '1942 ए लव स्टोरी', 'मिशन कश्मीर' और 'थ्री इडियट्स' जैसी फिल्में बनाई हैं। 'शिकारा' 7 फरवरी 2020 को रिलीज होगी। विधु विनोद ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, तीस साल बाद हमारी कहानी कही जाएगी...।

अध्ययन

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं का दावा, प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आत्महत्या करने की भी बढ़ जाती है संभावना

वायु प्रदूषण भी बढ़ा देता है अवसाद का खतरा

लंदन, आइएएनएस : वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अब एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि उच्च स्तर के वायु प्रदूषण में लंबे समय तक रहने से लोग डिप्रेशन यानी अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों के आत्महत्या करने की संभावना भी ज्यादा होती है। वायु प्रदूषण और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध का पता लगाने वाले सबूतों की समीक्षा और मेटा-एनालिसिस स्वास्थ्य पत्रिका इनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स में प्रकाशित हुई है। इस अध्ययन में 16 देशों के आंकड़ों की समीक्षा की गई है।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता और इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक जोसेफ हेस ने कहा, 'हमारे निष्कर्ष इस साल सामने आए अन्य अध्ययनों से मेल खाते हैं, जो युवाओं के मामलों और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में एक महत्वपूर्ण सुबूत हो सकता है।' उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों के बीच समानता महज एक संयोग है, ये इस बात को और पुख्ता कर देते हैं कि वायु प्रदूषण से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

प्रतीकात्मक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी महीन कणों को 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब्ड से नीचे रखा जाना चाहिए। इसमें हवा में मौजूद छोटे-छोटे धूल के कणों को भी शामिल किया जाता है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने महीन कणों के प्रदूषण और वयस्कों में पांच अलग-अलग प्रतिकूल मानसिक स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध की जांच की थी। इस दौरान उन्होंने 25 ऐसे अध्ययनों की पहचान की, जो उनके मानदंडों में फिट बैठते थे, जिनमें से नौ प्राथमिक विश्लेषणों में भी शामिल थे। लंबे समय तक पार्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर को देखते हुए शोधकर्ताओं ने पांच अध्ययनों को एक मेटा-एनालिसिस में शामिल किया गया था।

10 फीसद बढ़ जाती है रोगी होने की संभावना : अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि महीन कणों के औसत स्तर पर वृद्धि होती है और लोग प्रदूषित हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो इस बात की संभावना 10 फीसद बढ़ जाती है कि वे अवसाद से ग्रसित हो जाएं।

तंत्रिका को भी होता है नुकसान : यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जुड़े और इस अध्ययन के मुख्य लेखक इसोबेल ब्रेथवेट ने कहा, 'हमने लगातार उन परिणामों का अध्ययन किया जिनकी समीक्षा में हमने लंबे समय तक वायु प्रदूषण जोखिम और अवसाद के बीच संबंधों का विश्लेषण किया गया था। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि प्रदूषित हवा से महीन कण रक्तप्रवाह और नाक दोनों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं और वायु प्रदूषण में न्यूरोइन्फ्लेमेशन में वृद्धि करता है, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान और हार्मोन उत्पादन में बदलाव होने की संभावना बढ़ जाती है।